बारहवां

प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी संबद्धता : पीढियों का जुडना

7-9 जनवरी, 2014, नई दिल्ली

कार्यवाही और आगे बढना

कार्यकारी सारांश

बारहवां

प्रवासी भारतीय दिवस

(7-9 जनवरी, 2014, नई दिल्ली)

- भारत का चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बडॉ. प्रवासी समुदाय है। अनुमानित तौर पर 25 मिलियन से भी अधिक प्रवासी भारतीय समुदाय प्रत्येक महाद्वीप में फैला हुआ है। हालांकि सदियों से भारतीय प्रवासियों का स्थानान्तरण कई कारकों की वजह से हुआ है, परंतु आज उनके आकार और भारत की विकास कथा में उनके योगदान की संभावना ने हमारी आंखे अनंत संभावनाओं के लिए खोल दी है। इसी के आलोक में, भारत और इसके प्रवासी समुदाय के बीच अर्थपूर्ण संवाद और आपसी हितकारी संबंद्धता का महत्व अत्याधिक बढ जाता है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए) द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में आयोजित किए जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस ऐसी नई सहक्रियाओं की संभावनाओं का पता लगाने और उनका विकास करने की प्रक्रिया को आगे बढाने का एक मंच प्रदान करता है।

- दिनांक 7-9 जनवरी, 2014, के बीच नई दिल्ली में आयोजित बारहवां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा युवक कार्यक्रम मंत्रालय की सहभागिता से किया गया। इस कार्यक्रम का समन्वय और प्रबंध फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कार्मस एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय समुदाय के समक्ष आने वाले मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई और देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को बढाने के लिए तौर-तरीकों का सुझाव दिया गया।

- इस सम्मेलन का मुख्य बल युवाओं की क्ष्ामता का दोहन करने पर था। भारत में, लगभग 50 प्रतिशत कार्यगत जनसंख्या 18-35 वर्ष आयु समूह के बीच है। इस सम्मेलन में प्रवासी युवाओं और युवा भारतीयों की विशिष्ट शक्तियों-विशेषीकृत कौशलों, अच्छा तकनीकी ज्ञान और मानव पूंजी, को आपस में मिलाते हुए एक संधारणीय और समावेशी विकास मॉडल विकसित करने का आह्वान किया गया.....देश में सेवा औद्योगिक विकास के लिए जिसकी आवश्यकता है। युवाओं का उल्लेख समाज में परिवर्तन के एक माध्यम के तौर पर किया गया।

- प्रारंभ में ही, भारत ने प्रवासी युवाओं और युवा भारतीयें को व्यापार, उद्योग और सामाजिक क्षेत्रों में भागीदारी बनाने के लिए एक साथ आगे आने का आह्वान किया। श्री वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री ने कहा "हमारा लक्ष्य इस प्रयोजनार्थ युवाओं के वैश्विक संपर्क को सुदृढ बनाना होना चाहिए।"

- पिछले कुछ समय से यह महसूस किया कि भारत को अपने जनसंख्यिकीय लाभांशों का लाभों का दोहन करने के लिए अपने युवाओं को सशक्त करने की एक समर्थकारी नीति की आवश्यकता है।

श्री जितेंद्र सिंह, युवक कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा राज्य मंत्री द्वारा शिक्षा, कौशल विकास,स्वास्थ्य देख रेख एवं खेल के माध्यम से भारतीय युवाओंको उत्पादक कार्य बल के तौर पर विकसित करने पर बल देने वालीएक नई राष्ट्रीय युवा नीति की घोषणा की गई।

- भारतीय प्रवासी समुदाय धर्म, मीडिया और मनोरंजन, योजना और योग के माध्यम से मातृभूमि से जुडॉ. रहना चाहते हैं। इस सम्मेलन में इस मत का समर्थन किया गया कि प्रवासी भारतीय अपने बच्चों में भारतीय मूल्य और संस्कृति विकसित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। यह सुझाव दिया गया कि भारतीय विश्वविद्यालय और अन्य सामाजिक संस्थाएं विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक असुरक्षा की भावना को दूर कर सकते हैं।

- प्रतिनिधिमंडलों ने भी भारत के साथ वायु संपर्क में सुधार करने और प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की नई पीढी की आकांक्षाओं को पूरा करने का आह्वान किया, जिनके लिए भारत सरकार की तरफ से अधिक सुकर और समर्थकारी नीतियें की आवश्यकता है। यह सुझाव दिया गया कि निवेश अवसरों के बारे में सूचना प्रदान करने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली के आधार पर संबंध विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने और एनआरआई निवेश के लिए एकल खिडकी मंजूरी के लिए युवा भारतीयों हेतु एक सर्व समावेशी संगठन की स्थापना की जा सकती है।

- इस बात का उल्लेख करते हुए कि भारतीय प्रवासियों द्वारा प्रेषित की जाने वाली धनराशि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से अधिक है, प्रतिनिधिमंडल ने अधिक धन भेजे जाने हेतु प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए सरकार से एक नीति बनाने का आग्रह किया, उन्होने उन भारतीय युवाओं के विश्वास को बढाने के लिए एक मेंटरशिप कार्यक्रमों को तैयार करने का भी सुझाव दिया जो शिक्षा सुविधाओं और रोजगार अवसरों की कमी के कारण देश के बाहर अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

- भारत को अपने आपको वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। सम्मेलन में इस बात का उल्लेख किया गया कि आगामी दशक में 54 मिलियन युवा भारतीय रोजगार की तलाश में होगे और चूंकि कृषि क्षेत्र में नौकरियों की अपेक्षित संख्या के अनुरूप अपनी गति को बनाए रखने की क्षमता नहीं है, इसलिए रोजगार के अवसर बढाने हेतु सकल घरेलू उत्पाद(जीडीपी) में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान बढाया जाना चाहिए प्रतिनिधमंडल ने सुझाव दिया कि वैश्विक मानकों के अनुरूप अपेक्षित शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ युवा कार्यबल का विकास करने के लिए मानव संसाधन में निवेश किया जाना आवश्यक है और अपने आवास वाले देश से विचारों, मॉडल्स, निधियों और सहयोग प्रदान करते हुए कौशल विकास में नवाचार लाने के लिए भारतीय प्रवासियों का सहयोग मांगा।

- इसके अतिरिक्त, कई नई नीतियों जैसे सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार को लागू करने के बाद भारत एक समर्थकारी परितंत्र विकसित करने की नई दिशा में अग्रसर हो चुका है। परंतु सरकार, काराबारी घरानों और सिविल सोसाएटी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन में विश्वास बहाल किए जाने की तत्काल आवश्यकता है, ओर प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि वास्तविकता की बजाय शोर-शराबे पर ध्यान न दिया जाए।

- प्रधानमंत्री डॉ.. मनमोहन सिंह ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के बाहर इस अवधारणा को दूर करने का आह्वान किया कि भारत अपनी लय खो रहा था और कहा कि सामाजिक चुनौतियों, भारतीय राजनीति के आकार और अभिशासन संबंधी मुद्दों का कोई आधार नहीं था।

- उन्होने विदेशों में भारतीय कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना और दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र जैसी पहलों की सराहना की और यह घोषणा की कि भारत प्रत्येक राज्य में प्रवासी भारतीय भवन स्थापित करना चाहता है।

- प्रतिनिधिमंडलों ने इस बात पर भी बल दिया कि भारत द्वारा एनआरआई की पूंजीगत बाजार में भागीदारी को आसान बनाए जाने देश में नवाचार को आगे बढाने तथा प्रौद्योगिकीय विकास में प्रवासी नेटवर्क का लाभ उठाने के तौर-तरीके तलाशने और संस्थानिक सहयोग जैसे अमेरिका के सामुदायिक कालेजों का भारतीय शिक्षा संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करने की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

- प्रतिनिधिमंडलों ने भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) और अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई)के समक्ष आने वाले विभिन्न मुद्दों जैसे वीजा संबंधी समस्याओं, पीआईओ और एनआरआई की नई पीढियों के बीच पहचान का संकट, एनआरआई के लिए अनुपस्थिति मताधिकार, दोहरी नागरिकता तथा एयर इंडिया के हवाई टिकटों के मूल्य को तर्कसंगत बनाए जाने, विशेष तौर पर अन्य के साथ साथ खाडी देशों से आने वालों के लिए, को भी रेखांकित किया।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास को बढाने के लिए गुणवत्ताधारक शिक्षा पर बल दिया गया। इसके लिए, राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली और इसके विश्वविद्यालयों को सुदृढ और समेकित करने के लिए भारतीय मूल के लोगों से सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि कुछ प्रतिष्ठित संस्थाओं और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं को छोडकर भारतीय शिक्षा प्रणाली नवाचार और दुनिया में किसी अन्य स्थान पर प्राप्त किए गए शिक्षा स्तरों की तुलना में अनुसंधान करने के लिए अनुकूल नही है। उन्होने प्रवासियों से इस प्रकार योगदान करने की आशा प्रकट की कि ऐसे नवाचारों और कौशलों का विस्तार हो और जो भारत के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में सहायक हो।

उद्घाटन सत्र

निराशा का कोई कारण नहीं, भारत बेहतर समय की तरफ अग्रसर

प्रधानमंत्री डॉ. *मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में प्रश्न उठाए जाने और सामाजिक परिवर्तनों के बारे में चिंताएं प्रकट किए जाने के बावजूद विदेशों में बसे हुए भारतीयों से सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का आह्वान किया।*

चित्र

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह प्रवासी भारतीय दिवस 2014 के
अवसर पर शुभारंभ द्वीप प्रज्जवलित करते हुए

बारहवें प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री डॉ.. मनमोहन सिंह ने यह आश्वासन दिया कि "वर्तमान के बारे में निराश होने और भविष्य की चिंता किए जाने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में हम आगे बेहतर समय की तरफ अग्रसर है और मै आपसे आग्रह करता हूं कि विश्वास और आशावाद के साथ इस देश के भविष्य के लिए कार्य करते रहें।

उन्होने देश के बाहर इस अवधारणा को दूर करने का आह्वान किया कि भारत अपनी लय खो रहा है और इस बात पर बल दिया कि सामाजिक चुनौतियों भारतीय राजनीति के आकार के बारे में चिंताएं और अभिशासन संबंधी मुद्दे निराधार हैं।

उन्होने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत, सहभागी और संवादात्मक है और अभी हाल ही के महीनों में अर्थव्यवस्था के मूल तत्व की अच्छी दशा रही है। " डॉ.. मनमोहन सिंह ने कहा," हमने बडी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने, कर प्रशासन में सुधार करने, राजकोषीय प्रबंध में सुधार करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन और उपयोगिता को युक्तिसंगत बनाने के लिए कई निर्णय लिए हैं। अधिक राजनैतिक समर्थन से हम गहन सुधार उपायों को विधिक स्वरूप प्रदान कर सकते थे -उदाहरण के लिए वित्तीय और बीमा क्षेत्र में । हालांकि, हमारे निर्णयों का प्रभाव पहले ही दिखना प्रारंभ हो गया है और भारत एक आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर उभर रहा है। मुझे यकीन है कि आपको आगामी कुछ माह में इसके स्पष्ट प्रमाण दिखाई देंगे।"

प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही के समय में महसूस की गई आर्थिक मंदी को स्वीकारते हुए कहा कि इस वित्त में भारत की विकास दर गत वर्ष की तरह संभवत: 5 प्रतिशत रहेगी और आगामी माह में देश की

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। "इस बात में कोई संदेह नहीं कि अभी हाल ही के समय में मंदी का दौर रहा है और इस वर्ष भी हम संभवत: गत वर्ष की तरह 5 प्रतिशत विकास दर रख पाएंगे।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारणों की वजह से यह स्थिति पैदा हुई हैं । इन चुनौतियो के बावजूद हमारी जीडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि भारत में उद्यमशीलता की भावना बहुत सजीव है और तेजी से आगे बढ़ रही हैं ।

2014 प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार विजेता उन्होने कहा कि भारत मे इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है जो चीजों को बड़े परिपेक्ष में नहीं देखते । गत दस वर्षों में ग्रामीण भारत के अधिकांश हिस्से को ब्रांडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। आज लगभग हजारों उच्चतर शिक्षा संस्थाए उच्च गति वाले राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का हिस्सा है ।

इस बात कि शिकायत करते हुए कि सरकार अधिक राजनैतिक समर्थन के अभाव में वित्तीय और बीमा क्षेत्रो मे गहन सुधार उपायो को विधायी स्वरूप प्रदान नहीं कर सकी, डॉ. सिंह ने कहा कि लिए गए निर्णयो का प्रभाव पहले ही दिखाई पड़ने लगा है और भारत एक आकर्षक विदेश स्थल के तौर पर उभर रहा है ।

उन्होने बल देकर कहा कि “मुझे यकीन है कि आपको आगामी कुछ माह में सार्थक प्रमाण दिखाई देंगे ।

शिक्षा क्षेत्र के संबंध में, जिसमे आप्रवासी भारतीयो की काफी रुचि है क्योकि उनमें से कई अपने बच्चो को शिक्षा के लिए यहाँ भेजते है, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश मे केन्द्रीय विश्वविधालयों कि संख्या 17 से बढ़कर 44 हो गई है जबकि भारतीय प्रोधोगिकी संसाथनों (आई आई टी) और भारतीय प्रबंध संसाथनों (आईआईटी) की संख्या दोगुनी हो गई है ।

प्राथमिक स्तर पर आज भारत का लगभग प्रत्येक बच्चा स्कूल जा रहा है । उन्होने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण आगामी 5 वर्षो के दौरान कार्यबल के लिए 50 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु निजी क्षेत्र सहित अन्य हितधारको के साथ कार्य कर रहा हैं ।

देश मे अवसंरचना विकास का वर्णन करते हुए उन्होने कहा, “हमने 17,000 किलोमीटर राजमार्ग और ग्रामीण क्षेत्रो में 200,000 कि.मी. से भी अधिक नई सड़कों का निर्माण किया हैं। स्वयं को अधिक सघारणीय ऊर्जा भविष्य प्रदान करने के लिए सौर, वायु और नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्रों में पहलों के द्वारा हमारी विधुत उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ रही हैं।”

“हमारे अभी हाल ही के निर्णयों का प्रभाव पहले ही दिखाई देने लगा है और भारत एक आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर उभर रहा है ।

मलेशिया भारत में निवेश करने वाला 18वां सबसे बड़ा देश है और राजमागों तथा अवसंरचना क्षेत्र में 72 परियोजनाओ को पूरा कर चुका है ओर इसकी 2005 बिलियन अमेरिकी डॉ.लर वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है मलेशिया ने

हम प्रवासियों को अपने मूल देश के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत करने की उनकी आकांक्षा में सरकार का सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करने का पुन: आश्वासन

डॉ.. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, भारत सरकार ।	भारतीय विश्वविद्यालयों/आईआईटी/आईआईएम को मलेशिया में अपने विश्वविद्यालयों केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया हैं। मणिपुर विश्वविद्यालय पहले ही अपना केंद्र वहाँ खोल चुका है। -डॉ.रक सेरी जी पालनीवेल प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्री और मलेशियाई इंडियन काँग्रेस के अध्यक्ष । मुख्य अतिथि, पीबीडी 2014	देते हैं। -श्री वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री

चित्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में गरीबी के स्तर लगातार कम हो रहे है। उन्होने उल्लेख किया कि, "भारतीय आर्थिक विकास प्रक्रिया भी सामाजिक तौर पर अधिक समावेशी और क्षेत्रीय तौर पर अधिक संतुलित हो गई है। समावेशी विकास हमेशा ही हमारी सरकार का मार्गदर्शी सिद्धांत रहा है और अभी हाल ही के वर्षो में हम इसे अधिक उत्साह और प्रयोजन के साथ लागू कर रहे हैं। हमारे गरीबी के स्तर तेजी से कम हो रहे है, आर्थिक तौर पर कमजोर राज्य तेज गति से विकास कर रहे है, कृषि विकास में तेजी आई है, और वास्तविक ग्रामीण मजदूरी वर्ष 2004 से तीन गुणा तक बढ गई है।"

उन्होने कहा कि ऐसा ऐतिहासिक विधान और योजनाओं के कारण हुआ है, जिन्होने, कार्य करने के अधिकार, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा का अधिकार जैसे अभूतपूर्व अधिकार प्रदान किए हैं। डॉ. सिंह ने घोषणा की कि," हमारी सरकार के लिए समावेशी विकास न केवल एक नैतिक अनिवार्यता अथवा एक राजनैतिक आवश्यकता है अपितु यह एक संधारणीय दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता का अनिवार्य संघटक है।"

उन्होने कहा कि सरकार की मुख्य प्राथमिकता लोगों को एक खुली, पारदर्शी, जवाबदेह और स्वच्छ सरकार प्रदान करना है। सूचना का अधिकार, लोकपाल विधान, सरकारी खरीद विधेयक, प्राकृतिक संसाधनों की आबंटन प्रणाली में परिवर्तन तथा हमारी विधि प्रवर्तन और लेखा-परीक्षा एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं।

स्वच्छ और पारदर्शी सरकार प्रदान करने के राजनीति के संबंध में डॉ. सिंह ने कहा कि यह कार्य जटिल था "क्योंकि हमें देश की राजनीति के संघीय स्वरूप का सम्मान करते हुए संस्थापित प्रक्रियाओं और प्रणालियों को दुरूस्त करना था।"

"अभिशासन का सुदृढ़ीकरण एक अनवरत जारी रहने वाली प्रक्रिया है और हम कभी यह दावा नहीं कर सकते कि हमने पर्याप्त कार्य कर लिया है, परंतु मुझे पूरा भरोसा है कि हम सही दिशा में आगे बढ रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और उत्त्रदायित्वों को निभाने में, जो दुनिया व्यापक तौर हमसे आशा करती है, भारत की क्षमता के बारे में विश्वास व्यक्त किया। "मै इस बात को लेकर भी आश्वस्त हूं कि भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय में भ्रमणशीलता इसके 22 मिलियन से भी अधिक राजदूतों के बीच संयोजन आगामी वर्षो में और गहरा एवं समृद्ध होता जाएगा" - प्रधानमंत्री

डॉ. सिंह ने श्री डॉ.टुक सेरी जी पालनीवेल प्राकृतिक संसाधन और पय्रावरण मंत्री एवं अध्यक्ष, मलेशियन इंडियन कांग्रेस जो इस वर्ष प्रवासी भारतय दिवस के मुख्य अतिथि भी थे, को भारत के सतत् समर्थन और सहायता और मलेशिया के साथ संबंधों को हर संभव तरीके से आगे बढाने का आश्वासन दिया।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रवासी मुद्दों के समाधान और प्रवासी भारतीयों तथा उनकी मातृभूमि के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।

वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (एमओआईए) ने दिल्ली में आयोजित बारहवें प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रवासी भारतीयों के कल्याण हेतु सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित किया और उन्हे अपनी मातृभूमि के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ करने मे मंत्रालय के प्रचुर सहयोग का पुन: आश्वासन दिया।

श्री रवि ने कहा, "हम महसूस करते है कि अर्थव्यवस्था और कारोबार आधुनिक दुनिया के फ्लेवर हैं। जबकि प्रवासी भारतीय अपने पूर्वजों की मातृभूमि के रूप में भारत की और भावनात्मक तौर पर मुडकर देखते हैं, परंतु इसके साथ ही वे भारत में अवसर भी देखते है और हमारी बढती हुई अर्थव्यवस्था में सद्भावी बनने के इच्छुक हैं।

प्रवासी भारतीयों के कल्याण के संबंध में डॉ. सिंह ने कहा, "हमने विदेशों में भारतीय कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना भी प्रारंभ की है। दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का कार्य इसी वर्ष पूरा कर लिए जाएगा। हम प्रवासी भारतीय भवनों की स्थापना करने में राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु एक योजना भी प्रारंभ करने के इच्छुक हैं,"

<u>प्रधानमंत्री के भाषण की मुख्य बाते:</u>

- भारत सभी राज्यों में प्रवासी भारतीय केंद्र का निर्माण करना चाहता है और दिल्ली में इसकी स्थपना इसी वर्ष कर दी जाएगी।
- भारत की बचत और निवेश दरें अभी भी जीडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक है और देश में उद्धमिता की भावना अत्याधिक सजीव है।
- शिक्षा क्षेत्र में आमूल-चूल सुधार किया गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 17 से 44 तथा आईआईटी और आईआईटी और आईआईएम की संख्या दोगुनी हो गई है।

- भारत ने 17,000 किलोमीटर राजमार्गों और गांवों में 200,000 कि.मी. से भी अधिक नई सडकों का निर्माण किया गया है।
- भारत के गरीबी स्तर तेजी से कम हो रहे हैं, आर्थिक तौर पर कमजोर राज्य तेजी से विकास कर रहे है, कृषि विकास में तेजी आई है और ग्रामीण मजदूरी दरों में 2004 से तीन गुणा वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण आगामी पांच वर्षों में 50 मिलियन भारतीयों को कौशल प्रदान करेगा।
- भारत ने खुली, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई), लोकपाल और सरकारी अधिप्राप्ति विधेयक को कानूनी स्वरूप प्रदान किया।

श्री पालनीवेल ने भारतीय कारोबारियों और प्रवासियों को मलेशिया के पॉम ऑयल उद्योग में प्रचुर निवेश अवसरों का दोहन करने के लिए आमंत्रित किया और जैविक संसाधनों के उपयोग शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र में भारत के साथ कार्य करने की इच्छा व्यक्त की और उन्होने भारतीय उद्योग से उनके देश में पांच सुपर आर्थिक गलियारों में उपलब्ध रियायतों और प्रोत्साहनों का लाभ उठाने का आग्रह किया।

डॉ.टुक सेरी जी पालनीवेल का भाषण:

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बैंक से मलेशिया में शाखा खोलने का आग्रह। वर्तमान में बैंक आफ बडौदा, आंध्रा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा संचालित वाणिज्यिक बैंक मलेशिया में कार्य कर रहा है।
- मलेशिया अपने उत्तरी गलियारा आर्थिक क्षेत्र, इस कदर आर्थिक गलियारे, पूर्वी तटीय आर्थिक क्षेत्र, साबह विकास गलियारे और सारावक नवीकरणीय उर्जा गलियारे में भारत के सहयोग की असीम संभावना देखता है।
- मलेशिया जैव-विविधता के मुद्दे पर भारत के साथ गहनता के साथ कार्य करना चाहता है।
- मलेशिया आईआईटी से शाखा खोलने की अपेक्षा करता है,
- मलेशिया अपने राष्ट्रीय जैविक विविधता अधिनिम 2002 के कार्यान्वयन में भारत के अनुभव से सीखने का दावा करता है।

चित्र

प्रधानमंत्री डॉ.. मनमोहन सिंह इस अवसर पर एक पुस्तक का

विमोचन करते हुए

"इनक्रेडिबल ऑपरचुनिटिज बैक होम।"

श्री पालनीवेल ने कहा कि हाल ही के वर्षों में मलेशिया आर्थिक और राजनैतिक घटनाक्रमों के कारण एक संभावित निवेश किए जाने वाले राष्ट्र के तौर पर उभरकर सामने आया है। मलेशिया, भारत में निवेश करने वाला 18वां सबसे बडॉ. देश है और राजमार्गों एवं अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में 72 परियोजनाओं को पूरा किया है और इसकी 2.05 बिलियन अमेरिकी डॉ.लर वाली बडी अर्थव्यवस्था है। उन्होने भारतीय विश्वविद्यालयों/आईआईटी/आईआईएमको मलेशिया में अपने विश्वविद्याय केंद्र खोलने के लिए आमंत्रित किया। मणिपाल विश्वविद्यालय ने अपना केंद्र पहले ही खोल दिया है।

मलेशियाई मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जैविक संसाधनों और लाभ शेयरिंग विधेयक की सुलभता हेतु प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान कर रही है। इस विधेयक का आशय जैविक संरचनाओं के उपयोग से लाभों की शेयरिंग और सुलभता के संदर्भ में जैविक विविधता समझौते(सीबीडी)के प्रावधानों को कार्यान्वित करना है।

श्री वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री, भारत सरकार ने भारतीय प्रवासियों के कल्याण के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और उन्हे अपने मूल देश के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के सुदृढीकरण के प्रयास में सरकार के भरपूर समर्थन का पुन: विश्वास दिलाया।

मंत्री ने कहा कि सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की पृष्टभूमि और हस्ताक्षर किए जा रहे सामाजिक सुरक्षा करारों के कारण खाडी देशों में भारतीय कर्मकारों के शोषण में काफी कमी आई है। श्री रवि ने कहा, "मंत्रालय की पहली प्राथमिकता खाडी देशों में भारतीय कर्मकारों के हितों का संरक्षण करना है। हमने कई कदम उठाए है। अब शिकायतों में काफी कमी आई है।"

इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि भारत ने लगभग सभी खाडी देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों पर हस्ताक्षर किए है, जिससे कम वेतन पाने वाले कर्मकारों के शोषण को कम करने में सहायता मिली है।

उन्होने कहा कि भारतीय मिशन भारतीय कर्मकारों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए शरण प्रदान करने और स्वदेश वापस भेजने की सुविधाओं सहित सभी प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।

श्री प्रेम नारायण, सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने भी इसी प्राकर के विचार व्यक्त किए और प्रतिनिधिमंडलों का उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद किया, जो इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस में एक नए उच्च कार्यक्रम में 60 देशों के लगभग 900 प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया जिसमें से लगभग 200 मलेशिया से थे।

भारत की प्रगति के प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रीका से भारत लौटे थे।

पूर्ण सत्र - 1

भारत के विकास और वृद्धि का कार्यक्रम

भारत का आत्मगौरव

भारत अपने प्रवासियों से न केवल विधियों के अर्थों में सहायता चाहता है अपितु देश में नवाचार और कौशल विकास प्रारंभ करने में सहायता चाहता है।

चित्र

श्री कमल नाथ, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के लोग (पीआईओ) और अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) देश के आत्मगौरव का एक बडॉ. स्त्रोत रहे हैं क्योंकि उन्होने देश के विकास और वृद्धि की कहानी में बडी भूमिका निभाई है-

श्री नाथ ने कहा कि अवसंरचनात्मक विकास पर बोलने हुए मंत्री ने कहा कि भारत का विकास अवसरंचनात्मक विकास से पहले हुआ है। शहरों की संख्या में बढोतरी होने के साथ ही शहरी अवसंरचना अपनी गति नहीं बनाए रख सकी और यह एक बडी चुनौती के तौर पर उभरकर सामने आई है । सरकार ने कई परियोजनाएं प्रारंभ की है जैसे कई भारतीय शहरों में मेट्रो रेल लाइनों का निर्माण करना और इसे श्रेष्ठ परिवहन प्रणाली के साथ समेकित करने के लिए तौर-तरीकों पर विचार किया जा रहा है।

उन्होने इस बात की और ध्यान दिलाया कि किस प्रकार दिल्ली मेट्रो का चरण 5 पूरा किए जाने के बाद इसकी कुल लंबाई 402 कि.मी. हो जाएगी और यह लंदन भूमिगत रेल लाइन से भी अधिक होगी। उन्होने कहा कि इसी प्रकार की मेट्रो की योजना देश के विभिन्न शहरों के लिए बनाई जा रही है।

श्री नाथ ने इसक बात पर बल दिया कि भारत के लिए अभिशासन और प्रबंधन हेतु विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक जटिल राष्ट्र है, श्री नाथ ने कहा कि, "नए भारतीय दृष्टिकोण को स्वीकार किए जाने और लागू किए जाने की आवश्यकता है। ग्रामीण भारतीयों की व्यय करने की आय में बढोतरी के साथ ही देश ने अभूतपूर्व विकास किया है, जो एक नए महत्वकाक्षी वर्ग के तौर पर उभरकर सामने आया है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है।"

श्री आनन्द शर्मा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को विनिर्माण पर ध्यान देना चाहिए और इसे एक विनिर्माण हब बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। श्री शर्मा ने कहा, "आगामी दशकों में लगभग 54 मिलियन स्नातक नौकरी के अवसरों की तलाश करेंगे, इसलिए रोजगार के अवसर बढाने के लिए जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को व्यापक स्तर तक बढाए जाने की आवश्यकता है।"

उन्होने विश्वास व्यक्त किया कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश में उच्च और दीर्घकालिक विकास की अपार संभावनाएं है बशर्ते कि युवा बिग्रेड के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं।

उन्होने कहा कि ऐसा केवल विकास के अनुकूल माहौल तैयार करके ही संभव हो सकता है। श्री शर्मा के अनुसार भारत में कुशल कार्यबल की कमी है और इसलिए मानव संसाधनमें निवेश किए जाने और युवाओं को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। "वैश्विक मानकों के अनुरूप अपेक्षित शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त युवा कौशल कार्यबल तैयार किया जाना महत्वपूर्ण है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढेंगें।"

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र
भारत के पूंजी बाजार में अप्रवासी भारतीयों की भागीदारी को बढाए जाने की आवश्यकता है और ऐसा वित्तीय और कराधान विनियमों सुधार प्रारंभ करके किया जा सकता है। एक संगठन के तौर पर फिक्की ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है
-श्री सिद्धार्थ बिरला अध्यक्ष, फिक्की

चित्र
भारत को विशिष्ट अभिशासन और प्रबंध की आवश्यकता है क्योंकि यह एक जटिल राष्ट्र है, नए भारत के विजन को स्वीकार करने और लागू किए जाने की आवश्यकता है ।
-श्री कमलनाथ शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री

चित्र
भारत की ख्याति इसके विशिष्ट राष्ट्रीय स्वतंत्रता संर्घष के कारण है और आज भारत की लोकतंत्र दुनिया भर में सबसे बडॉ. और बेहतर है।
-डॉ.. मोहन गोपाल निदेशक, रजीव गांधी समसामाजिक अध्ययन संस्थान

चित्र
भारतीय प्रवासियों को यह समझाना चाहिए कि भारत ने केवल बिलियन लोगों का एक राष्ट्र है अपितु बिलियन अवसरों वाला राष्ट्र भी है और उन्हे निश्चित तौर पर आगे आकर हमारे साथ मिलकर कार्य करना चाहिए
-श्री आनन्द शर्मा वाणिज्य और उद्योग मंत्री

चित्र
हमें अधिक सुधारों के साथ एक ऐसा परितंत्र विकसित करना चाहिए जहां हम 8 प्रतिशत की विकास दर पुन: प्राप्त कर सकें और इस संबंध में विभिन्न सरकारी उपाय किए गए हैं।
-श्री सैम पित्रोदा, जन सूचना, अवसंरचना और नवाचार के संबंध में प्रधानमंत्री के सलाहकार

इसके अतिरिक्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक ऐसा परितंत्र और निवेश का माहौल तैयार किया है, जिसने भारत को एक महत्वपूर्ण और आकर्षक निवेश स्थल बलाया है। उन्होने कहा कि सरकार ने तीन

महत्वपूर्ण सुधार नामत: मिंग्ल ब्रांड रिटेल, बैंकिंग सुधार और हाल ही में मल्टी ब्रांड रिटेल, प्रारंभ किए हैं।---

प्रधानमंत्री ने कहा कि, अधिक प्रगतिवादी सुधारों की प्रक्रिया जारी है जिनमें मुख्य सरकारी अधिप्राप्ति विधेयक, सूचना प्रदाता संरक्षण विधि और कोयला विनियामक निकाय शामिल है।

उन्होने यह भी घोषण की कि शीघ्र ही ई कारोबार प्लेटफार्म को प्रारंभ किया जाएगा। यदि जीएसटी(वस्तु और सेवाकर) का समाधान हो गया तो इसमे विकासदर में लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि होगी।

श्री सैम पित्रोदा, जन सूचना, अवसंरचना और नवाचार के संबंध में प्रधानमंत्री के सलाहकार , ने कहा कि आज भारत में उच्च दूरसंचार कनेक्टिविटी है और इस कनेक्टिविटी का उपयोग प्रक्रिया की पुन: अभिकल्पना और देश के विकास और वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए किया जाना चाहिए।

"भारत एक समावेशी और संधारणीय आर्थिक विकास प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा, आम असमानता को कम करने और गरीबी हटाने में सहायता मिलेगी। ऐसा केवल संसाधनों के उत्तम उपयोग द्वारा ही संभव हो सकता है।"

श्री पित्रोदा के अनुसार सबसे बडी चुनौती सभी मोर्चों पर उल्लेखनीय विकास दर प्राप्त करना और अर्थव्यवस्था को पुन: उच्च विकास दर के पथ पर वापस लाना है। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा कि "कई नीतियों जैसे शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार लागू किए जाने से भारत अधिक सुधारों के साथ नया परितंत्र सृजित करने की नई राह पर आगे बढ चुका है, जिससे जीडीपी की 8 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त किया जा सकता है।"

श्री पित्रोदा ने कहा कि गत दो दशकों में अर्थव्यवस्था कई ढांचागत सुधारों के साथ शानदार गति से आगे बढी है और इस प्रकार अर्थव्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धी बन गई है, "इससे अधिक निवेश, बचत को बढावा मिला और वैश्विक परिणामों एवं व्यापार मात्रा में भारत की हिस्सेदारी को बढाने में सहायता मिली।"

भारत के सुदृढ आर्थिक मूलतखों में विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होने कहा: "गत दशक में औसत विकास दर बढकर 8 प्रतिशत रही है जो 90 के दशक में 5.5 प्रतिशत से अधिक है। इसके साथ वृहत आर्थिक मूलभूत तत्वों और वित्तीय आधार के कारण लचीली बनी रही।"

हालांकि, श्री पित्रोदा ने यह स्वीकार किया कि सरकार ने कई योजनाएं और विनियम प्रारंभ किए है जिनमे शीघ्र ही महत्वपूर्ण बदलाव होगें। उन्होने सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्लेटफार्म सहित जन सूचना अवसंरचना जैसे कानूनों को बदलते हुए भारत के प्रमाण के तौर पर उद्धत किया।

उन्होने यह भी घोषणा की कि सबसे निचले स्तर पर नवाचार का वित्त पोषण करने के लिए बिलियन-डॉ.लर कोष की स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होने इस बात पर बल दिया कि उन्हे भारत की भविष्य की संभावनाओं में तेजी की आशा हैं।

श्री सिद्धार्थ बिरला, अध्यक्ष फिक्की ने कहा कि कारोगार करने और इसके विस्तार को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक माहौल की आवश्यकता है उन्होने कहा कि अभी हान ही के समय में, काराबारियों को इस यर्थाथता में विश्वास न करने लिए क्षमा किया जा सकता है कि भारत में कारोबार के लिए समग्र अनुकूल ढांचा विद्यमान है।"

उन्होने सभी हितधारकों से देश में निवेश आकर्षित करने के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का आग्रह किया। उन्होने कहा: "आज यहां मौजूदा सरकार के नेताओं के सकारात्मक आशयों ने विषय-वस्तु की बजाय कही-सुनी बातों को पीछे छोडने का कार्य किया है। मीडिया, सिविल सोसाइटी और आन्दोलनों द्वारा माहौल को पीछे धकेला जाना आसान है। फिक्की का यह मानना है कि सरकार, कारोबार और सिविल सोसाइटी के बीच आपसी विश्वास को पुन: बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है।

उन्होने इस बात पर भी बल दिया कि संभावित परिणामों, कर साम्यता और प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से कारोबारों के विश्वास को बढावा देने के लिए सुशासन की आवश्यकता है। "यद्धपि फिक्की घरेलू पूंजीगत बाजारों के सुद्ढीकरण की बात करता है, हम देखते हैं कि अप्रवासी भारतीयों की हमारे पूंजीगत बाजारों में भागीदारी को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता है। हम इस बात से सीख सकते है कि प्रवासी भारतीयों ने अपने बाजारों में भागीदारी कैसे की, हम इस बात का प्रयास करेंगे कि क्या किन्ही ठोस सुझावों को विकसित किया जा सकता है।"

श्री बिरला ने फिक्की की इस प्रतिबद्धता पर पुन: बल दिया कि सामाजिक आर्थिक पहलों में शामिल होते हुए विभिन्न क्षेत्रों के प्रवासियों ने संसाधनों, विशेषज्ञता को साझा करके तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं ग्रामीण विकास पर समय व्यतीत करते हुए भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होने इस बात को रेखांकित किया कि "कैसे सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से किए गए प्रक्रियागत सुधार हमें विकास पथ पर आगे बढनें में सहायता प्रदान करेंगे और सरकार सही दिशा में आगे बढ रही है।" हालांकि उन्होने इस बात को भी रेखांकित किया कि मीडिया और सिविल सोसाइटी संगठनों को भारत के विकास और वृद्धि के साथ सकारात्मक रूप से आगे बढने के लिए कारोबार में सहभागी बनने की तत्काल आवश्यकता है।

डॉ.. जी. मोहन गोपाल, निदेशक, राजीव गांधी सम सामाजिक अध्ययन संस्थान ने इस बात पर बल दिया कि भारत का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों को उनकी पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना समान अवसर और समानतौर पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करना होना चाहिए। इसके आगे उन्होने कहा कि,

"समानता के बिना कोई भी विकास और वृद्धि टिकाऊ नही हो सकते हमें एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ कार्य करने की आवश्यकता है जहां विकास समानता को बढावा देता हो। इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सत्तावादी शासन एवं लोक-लुभावने उपाय देश को विकास के पथ पर आगे नही ले जा सकते क्योंकि "हमें उदारवादी राजनीतिक मूल्यों की आवश्यकता है।"

सत्र की मुख्य बाते:

- प्रवासी समुदाय न केवल धन अथवा निवेश के अर्थो में भारत के विकास में योगदान देने का इच्छुक है अपितु कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करने के अर्थो में भी योगदान करना चाहता है।
- प्रतिनिधिमंडल चाहते थे कि बेहतर संवाद के लिए फिक्की जैसे कारोबारी निकायों द्वारा अपने चैपटर उनके संबंधित देशों में भी खोले जाए।
- प्रवासियों की तरफ से निवेश आकर्षित करने के लिए अभिशासन सुधार महत्वपूर्ण है और सरकार ने इस मोर्चे पर पहले ही कुछ बेहतर कार्य किया हैं।
- दुनिया भर में कुशल और अत्याधिक कुशल व्यावसायियों की मांग में बढोतरी हो रही है और सरकार का राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन इस दिशा में एक सही कदम है।
- अप्रवासी भारतीयों की पूंजीगत बाजार में भागीदारी बढाए जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा ऐसी प्रणालियां लागू किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा प्रणाली को अप्रवासी भारतीयों को पूंजीगत बाजार में भागीदारी हेतु अधिक आकर्षित और प्रोत्साहित किया जा सके।

पूर्ण सत्र 2

भारत की साफ्ट पावर

भारत को गौरवशाली और शक्तिशाली बनाना

प्रवासी भारतीय समुदाय से विदेशों में देश के मूल्यों, आस्थाओं संस्कृति और विरासत के प्रसार और उसे लोकप्रिय बनाने में भारत के श्रेष्ठ राजदूत की भूमिका निभाने का आग्रह किया गया।

चित्र

वर्तमान महत्वकांक्षी भारत 2025 तक शेष दुनिया को प्रेरित करने का कार्य करने लगेगा जब इसके पास 900 मिलियन लोग कार्य करने वाले आयु वर्ग में होगें। श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि परवर्ती सरकारों के लिए लोगो की सामूहिक क्षमता का अहसास करवाने के लिए अवसंरचना और अवसर प्रदान करना एक चुनौती होगी।

21वीं सदी में हम देख रहे है कि युवा भारत दुनिया में सामाजिक आंदोलनों का एक भाग बनना चाहता है। मंत्री ने कहा कि महत्वकांक्षी भारत न केवल हमारे लिए प्रेरक भारत बनेगा अपितु शेष दुनिया को भी प्रेरित करेगा।

इसके अतिरिक्त श्री सिब्बल ने कहा कि वर्ष 2020 तक 600 मिलियन भारतीय बडे शहरों में स्थानान्तरित होगें तथा उनके पास उपल्ब्ध श्रेष्ठ शिक्षा सहित अद्यतन प्रौद्योगिकी को अपनाएगें।" यह उन्हे उनकी क्षमताओं का पूर्ण दोहन करने और भारत को शेष दुनिया के साथ संवाद आपसी संपर्क का एक हब विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा"

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की निपुणता के बारे में बोलते हुए उन्होने कहा कि वर्ष 2006 में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं (आईटीईएस) से प्राप्त राजस्व 40 बिलियन अमेरिकी डॉ.लर था जो वर्तमान में बढकर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। उन्होने कहा कि इसमें से 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात आय से प्राप्त हुआ। यह भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा किए गए विकास को दर्शाता है, श्री सिब्बल ने यह कहते हुए प्रवासियों की सराहना की कि वे भारत की साफ्ट पावर के प्रतीक है और उन्होने भारत को गौरव दिलवाया है और आशा प्रकट की कि वे ऐसा करना जारी रखेंगे।

श्री सलमान खुर्शीद, विदेश मंत्री, जिन्होने इस सत्र की अध्यक्षता की, ने प्रवासियों से देश के मुल्यों, आस्थाओं, संस्कृति और विरासत के प्रसार और उसे लोकप्रिय बनाने में भारत के श्रेष्ठ राजदूत की भूमिका निभाने का आग्रह किया।

मंत्री ने प्रवासियों से भारत को अपना ब्रांड नाम और वैश्विक प्रतिष्ठा बनाने में सक्रिय नेटवर्क स्थापित करने का आग्रह किया ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के आकार पर ध्यान दिए बिना विदेशी अर्थव्यवस्थाओं के साथ गहरे आर्थिक संबंध स्थापित किए जा सकें।

श्री चंद्रेश कुमारी कटोच, संस्कृति मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि प्रवासी भारतीयों को अपने मेजबान देशों में प्रोत्साहक कार्यक्रमों का आयोजन कर देश की समृद्ध विरासर और सांस्कृतिक मूल्यों का सक्रिय तौर पर प्रचार-प्रसार करना चाहिए। उन्होने भाषा, वास्तुकला, बौद्ध परंपराओं, बॉलीवुड, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और जोखिम विज्ञान की बाते करते हुए भारत की सांस्कृतिक पंहुच को रेखांकित किया।

उन्होने कहा कि ,"भारत दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं मे से एक है और इसका पूरी दुनिया में प्रभाव है। ब्रिटिश शासन के दौरान, दुनिया में जाकर बसने वाले भारतीयों ने भारत की संस्कृति के विस्तार और प्रभाव को फैलाया। अप्रवासी भारतीयों ने भारत की संस्कृति को बढावा दिया हैं।"

मंत्री ने उन प्रभावशाली भारतीय व्यक्तियों जैसे महात्मा गांधी, रबींद्र नाथ टैगोर, विवेकानंद, अमृता शेरगिल, वासुदेव, राजा रवि वर्मा, होमी भाभा, सुनिता विलियम, कल्पना चावला और इंदिरा गांधी को याद किया जिन्होने विदेशों में भारतीय संस्कृति और सॉफ्ट पावर को बढावा दिया।

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र
आप (प्रवासी भारतीय) देश के मूल्यों, आस्थाओं, संस्कृति और विरासत का विदेशों में प्रसार करने और उसे लोकप्रिय कनाने में भारत के श्रेष्ठ राजदूत है।
- श्री सलमान खुर्शीद,विदेश मंत्री,

चित्र
वर्ष 2025 तक 900 मिलियन भारतीय कार्यकरने वाले आयु समूह में होगें। शायद भारत (तब) दुनिया का सबसे अमीर देशा होगा। मै आशा करता हूं कि प्रवासी अवसर प्रदान कर सकते हैं। - श्री कपिल सिब्बल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी एवं

चित्र
भारत वित्तीय और सैन्य तौर पर चीन जितना शक्तिशाली नहीं है। परंतु यह सॉफ्ट पावर के तौर पर निश्चित ही एक महाशक्ति हैं। - श्री चंद्रेश कुमारी कटोच, संस्कृति मंत्री

चित्र
फिल्मों, क्रिकेट, पाक, प्रणाली नृत्य, संस्कृति और पर्यटन में अधिक लोगों को आकर्षित करने की क्षमता हैं। हमारे पास प्रचुर मात्रा में साफ्ट पावर हैं।
-डॉ.. के चिंरजीवी, अभिनेता, प्रोड्यूसर और राजनेता

चित्र
भारत के पास पावर हैं। इसके पास हर जुबिन मेहता, फिल्में, विविधता और लोकप्रियता हैं।ब्रिटेन में 10,000 भारतीय रेस्त्रां हैं। हावर्ड बिजनेस स्कूल फैकल्टी में 20 प्रतिशत भारतीय है। हम आशा करते है कि हम किसी भारतीय को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगें।

विधि और
न्याय मंत्री

- लार्ड कर्ण
बिल्लमोरिज
सीबीईडीएल,
सदस्य, हाउस
आफ लार्डस, यूके

डॉ. के चिंरजीवी, अभिनेता, प्रोड्यूसर और राजनेता ने कहा कि मीडिया विभिन्न सभ्यताओं के बीच संबंध स्थापित करने में एक प्रभावी उपकरण बन गया है और भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र ने इस मोर्चे पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है।

उन्होने कहा कि भारत साफ्ट पावर को आकर्षित करने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है, जिसे भोजन, संगीत, प्रौद्योगिकी और फिल्मों के माध्यम से किसी देश की संस्कृति को साझा करने और दर्शाने के तौर पर परिभाषित किया गया हैं।

डॉ. चिंरजीवी ने कहा कि भारत साफ्ट पावर विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक बनकर उभरा है।

भारत के वैश्विक प्रभाव का एक बहुत लंबा और जटिल इतिहास रहा है, जो एशिया में हिंदू और बौद्ध विचारों के प्रचार प्रसार, गणित, ज्योतिष विज्ञान और अन्य भौतिक तथा अलौकिक विज्ञान संबंध में अरबी और इस्लामिक विचारों में योगदान से लेकर अभी हाल ही में पश्चिमी विश्वविद्यालयों में मानव और बौद्धिक सम्पदाओं के निर्यात, विभिन्न देशों के बीच सहयोग और बहु-स्तरीय संगठनों, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों, तक फैला हुआ हैं।

राजनेता के अनुसार, दुनिया भर में फैले हुए 25 मिलियन सुदृढ प्रवासी भारतीयों ने जीवन के कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की है तथा अपने आवास देश को सांस्कृतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक अनुभव से समृद्ध किया है। उन्होने भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के तौर पर उभार में भी उल्लेखनीय योगदान किया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढती हुई अर्थव्यवस्था और एक वाइब्रेंट, बहुलतवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनैतिक देश के रूप में भारत वैश्विक दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर को दर्शाने के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। उन्होने कहा कि ऐसे परिदृश्य में मास-मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है।

जैसाकि अमेरिका ने दुनिया को अपनी सॉफ्ट पावर दर्शाने के लिए हॉलीवुड का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है उसी प्रकार भारतीय फिल्म उद्योग में भारत के लिए ऐसा ही करने की असीम क्षमता है। आज, भारत पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों का सबसे गतिशील विकल्प प्रदान करता है। भारत का फिल्म उद्योग संभवत सबसे बडॉ. है और यह भारतीय संस्कृति को बढावा देने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है- डॉ.. चिंरजीवी।

आज यह हॉलीवुड को पीछे छोडते हुए दुनिया का सबसे बडॉ. फिल्म उद्योग है, जिसका वार्षिक आउटपुट 10,000 से भी अधिक फिल्में हैं। सैटेलाइट टीवी और इंटरनेट का धन्यवाद करते हुए उन्होने कहा

कि इनके कारण भारतीय फिल्मों और इंडियन सोप ओपेरा की वैश्विक दर्शकों तक पहुंच हो गई है, और अभिनेता से राजनेता बने डॉ. चिंरजीवी ने कहा कि दुनिया भर के लोग भारतीय समाज और संस्कृति से परिचित हुए हैं।

भारतीय फिल्म उद्योग, जिसके दुनियाभर में काफी अधिक दर्शक हैं, भारत की इमेज को पुन चमकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वितीय और राजनीतिक निवेशकों के लिए भारत एक आकर्षक निवेश स्थाल हैं। भारतीय शोबिज क्षेत्र की गतिशीलता और विश्वास में सतत वृद्धि हो रही है। भारतीय फिल्मों की दुनिया भर में बढती हुई लोकप्रियता से प्रतीतहोता है - डॉ. चिंरजीवी।

उन्होंने कहा कि विदेशों में रंगमंच का वर्तमान योगदान कुल फिल्म उद्योग राजस्व में लगभग 7 प्रतिशत है और आगामी वर्षों में इसकी हिस्सेदारी बढने की संभावना है। अतंर्राष्ट्रीय बाजार में फिल्मों के सुदृढ विपणन से विदेशी रंगमंच योगदान को और बढाया जा सकताहै,जो वर्ष 2016 में कुल फिल्म उद्योग राजस्व में 8 प्रतिशत तक रहने की संभावना हैं।

प्रख्यात अभिनेता ने कहा कि, "भारतीय फिल्में सीमाओं को पार कर रही है, वर्ष 2012 में विदेशी थिय्रेटरिकल रिलीज से लगभरग 7.6 मिलियन रूपये प्राप्त हुए थे तथा आगामी पांच वर्षों में लगभग 11.9 बिलियन रुपये के आकार सहित 9.4 सीएजीआर की वृद्धि की आशा की जा रही है। हमें फिल्मों के माध्यम से भारत की सॉफ्ट पावर को सुदृढ करने के लिए दुनिया के विभिन्न भागों में रह रहें । काफी संख्या में प्रवासियों का सही उपयोग किए जाने की आवश्यकता है परंतु इसके साथ ही हमें भारतीय फिल्मों को अधिक व्यापक स्तर और गहराई तक पहुॅचाने के लिए भारतीय प्रवासियों से आगे भी सोचना होगा।"

उन्होने कहा कि, "इसके भारत की सॉफ्ट पावर पर गुणात्मक प्रकार के प्रभाव होगे, भारतीय फिल्में आज सीमाओं को पार कर रही हैं और उनमें से कई सफलतापूर्वक पहुॅच बनाने में कामयाब रही हैं परंतु उनके ज्यादातर प्रयास विदेशों में भारतीय प्रवासियों को आकर्षित करने तक ही सीमित होते हैं।

डॉ. चिंरजीवी ने कहा कि हॉलीवुड दुनिया पर इसलिए राज नहीं कर रहा है कि एक किसी विशेष समूह तक सीमित है, अपितु इसकी पहुॅच सीमाओं और संस्कृतियों के परे भी है। उनके अनुसार, ऐसा इसलिए है क्योंकि हॉलीवुड फिल्में वैश्विक स्तर पर दर्शकों को ध्यान में रखते हुए कतिमय विशष पर बनाई जाती हैं। भारतीय फिल्मों को भी भारत की सॉफ्ट पावर को अधिक सुदृढ करने के लिए दुनिया को ध्यान आकर्षित करने हेतु अद्यतन प्रौद्येगिकियों का उपयोग करते हुए विषय आधारित फिल्में बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होने सुझाव दिया कि नीतिगत स्तर पर भारत सरकार को विदेशों से भारतीय फिल्मों के वहां पर निर्बाध प्रदर्शन और जारी किए जाने की सुविधा प्रदान करने हेतु बातचीत करनी चाहिए। "आज की स्थिति में, विभिन्न देशों में कई तरह के प्रतिबंध है जैसे स्क्रीनस की संख्या जिन पर भारतीय फिल्में जारी की जाती हैं। उन्होने आशा व्यक्त की कि भारतीय सिनेमा प्रवासियों और विदेशी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए अधिक संख्या में विषय आधारित फिल्में बनाएगा।

डॉ. चिरंजीवी ने कहा कि पर्यटन भी सॉफ्ट पावर के तौर पर कार्य करता है। "पर्यटक भारत सिर्फ घूमने के लिए आते है और दुबारा से खर्च करने वाले पर्यटक के तौर पर आते हैं। उन्होने कहा कि मनोरंजन उद्योग 9.4 प्रतिशत की संयोजित दर से आगे बढ रहा है, जिससे भौगोलिक सीमाओं के पार भारतीय संस्कृति को बढावा देने की इसकी क्षमता का पता चलता है। उन्होने वीजा ऑन अराइवल, अंतर मंत्रालयी उलझन और स्वच्छता इत्यादि के बारे में चिंता व्यक्त की, जो उनके अनुसार भारतीय पर्यटन के लिए विदेशी नागरिकों को आकर्षित करने में बाधा पैदा कर रहे है।

"भारत एक ऐसा स्थान है, जहॉ सच्चे अर्थो में लोकतंत्र है।" भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्यमी करण लार्ड कर्ण बिल्लमोरिया सीबीईडीएल, सदस्य, हाउस आफ लार्डस, ब्रिटेन। इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सुधारों के संबंध में मैगनाकारी और वेस्टमिनिस्टर हो सकते है, परंतु यहां (भारत) मं सच्चा लोकतंत्र है।

श्री बिलिमोरिया ने दर्शकों की तालियों की गडगडॉ.हट के बीच कहा कि, यहां सच्चा लोकतंत्र है, जहां एक पार्टी एक में शून्य से प्रारंभ करती है और एक राज्य के चुनाव जीत जाती है।"

श्री बिलिमोरिया का संदर्भ दिल्ली में आम आदमी पार्टी से था, जिसने 15 वर्ष के लगातार शासन के बाद कांग्रेस का सत्ता से बाहर करते हुए दिल्ली के चुनाव में विजय पाई थी। आम आदमी पार्टी का गठन नवंबर, 2012 में किया गया था।

इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि, " अन्य भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाएं भारतीय विरासत का प्रचार प्रसार करने और उसको बढावा देने में सक्षम हैं, हालांकि, उनका मानना था कि सॉफ्ट पावर तभी अर्थपूर्ण होती है जब इसके साथ हार्ड पावर भी विकसित हो,

श्री बिलिमोरिया, कोबरा बीयर के मालिक ने यह भी कहा कि भारतीय ब्रिटेन से अधिक मतदान करते हैं।

उन्होने कहा कि ब्रिटेन में 10,000 भारतीय रेस्त्रां से भारतीय सॉफ्ट पावर को स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है और भारतीय पकवान ब्रिटेन में पसंदीदा भोजन बन रहे हैं।

हालांकि, उन्होने कहा कि भारत द्वारा अपनी विदेश सेवा और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) को सुदृढ किए जाने कि आवश्यकता है, जो वर्तमान में 600 है, इसे लोक कुटनीति कहा कि, "चूंकि, राजनयिक और विदेश सेवा के अधिकारी सॉफ्ट पावर को बढावा देने वाले होते हैं, इसलिए भारत को विदेशों में स्थित कार्यालयों में स्टॉफ की संख्या बढानी चाहिए। अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना में वर्तमान में भारत की विदेशों में अधिकारियों की संख्या काफी कम है। लोक कूटनीति आवश्यक है। भारतीय मूल के 25 मिलियन लोग भारत के ब्रांड राजदूत है। जीएमजीएसी में युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

श्री बिलिमोरिया ने कहा कि भारतीय ब्रिटेन में कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और उन्हे वरीयता, प्रदान की जा रही है। उन्होने कहा कि उन्हे आशा है कि वे अपने जीवन काल में किसी भारतीय को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे।

श्री बिलिमोरिया ने सुझाव दिया कि, "चूंकि विदेशों में ज्यादातर भारतीय दूतावासों की दशा दयनीय है इसलिए उनका उन्नयन करने के प्रयास किए जाने चाहिए क्योंकि वे भी देश की सॉफ्ट पावर को बढाने में योगदान देते हैं। वीजा ऑन अराइवल प्रक्रिया में तेजी लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए।

सत्र की मुख्य बाते:

- दर्शको में से एक सदस्य ने सुझाव दिया कि भारत को एक चेतावनी मंत्रालय का गठन करना चाहिए ताकि योग्यता प्राप्त युवक कार्यबल को नौकरियों की जानकारी मिल सकें।
- श्री सिब्बल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य वर्तमान न्यायाधीश नागरिक अनुपा(एक मिलियन नागरिकों के लिए 14 न्यायाधीश) को 30 न्यायाधीश प्रति मिलियन तक बढाना हैं।

प्रवासी भारतीय दिवस भाषण

'प्रवासियों के अनुभव संबंधी विचार'

प्रवासियों को भारत से प्यार और स्नेह की आवश्यकता है

कनाडॉई संसद के सदस्य श्री उज्ज्ल दोसांझ ने प्रवासियों का मातृभूमि के साथ भावनात्मक लगाव और इसके समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं तथा इसके विकास में बाधाएं पैदा कर रही समस्याओं के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए भावुक भाषण के माध्यम से भी दिलों को छू लिया।

कनाडॉई संसद के सदस्य श्री उज्जवल दोसांझ ने प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान भाषण देते हुए ब्रिटेन और कनाडॉ. में अपने प्रवास के दिनों के संर्घषों के बारे में बताया - प्रवासियों के अनुभव संबंधी विचारों को साझा किया। भारतीय प्रवासियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और अपनी मातृभूमि के प्रति उनकी चाहत को दर्शाने के लिए भारतीय मूल के राजनेता ने कहा कि भारतीय प्रवासियों का संघर्ष हजारों वर्ष पूर्व उस समय प्रारंभ हुआ जब महमूद गजनी उन्हें अफगानिस्तान के दस्तीनगर लेकर गया। उन्होने कहा कि उसके बाद वे पश्चिम की तरफ चले गए। प्रवासियों ने कभी भारत को नही भुलाया।

प्रवासियों के साथ संबंधों के बारे में श्री दोसांझ ने कहा कि उन्हे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन्हे सिर्फ भारतीय नागरिकों का "प्यार और स्नेह" चाहिए। यह सुझाव देते हुए कि भारत को मुलभूत क्षेत्रों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देने की आवश्यकता है, कनाडॉ.ई संसद के सदस्य ने कहा कि, "भारतीयों के जीवन को बेहतर और सुकर बनाए, उन्हें शिक्षित कीजिए और उनकी स्वास्थ्य देखभाल कीजिए। इसके बाद प्रवासी भारत आएंगे।

उन्होने यह कहते हुए भारत में विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अधिक सॉफ्ट पावर के तौर पर उभर सकता है।

"महात्मा गांधी भारत को आजादी दिलाने और इसे एक बेहतर देश बनाने के लिए भारत लौटे थे। यदि आज वे यहां पर जिंदा होते तो कहते कि हमें जागृत होने की आवश्यकता है.... कनाडॉ के लोगों को मतदान का अधिकार उस समय मिला जब 1947 में भारत को आजादी मिली।"

उन्होने पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा वेंकुवर, कनाडॉ में दिए गए भाषण का उल्लेाख किया जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने प्रवासियों से कहा कि "आप चाहे कही भी रहें परंतु अपने देश के प्रति वफादार रहें।

उन्होने विवादित लेखक श्री सलमान रूश्दी जैसे लोगों को भारत से बाहर रखे जाने की तार्किकता पर भी प्रश्न चिंह लगाया। श्री दोसांझ ने कहा कि, "खजुराहो की भूमि पर हम उन लोगों को बाहर कर रहें है जो अलग तरह से चित्रण करते हैं। धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जो हमारी संरक्षा करता है और यह हमें संविधान द्वारा प्रत्याभूत किया गया है। भारत में जातिवाद, साम्प्रदायिक और कट्टरता का कोई स्थान

नहीं है, जैसाकि नोबल पुरस्कार विजेता ओर कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा है स्वतंत्रता चारों तरफ होनी चाहिए।"

उन्होने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि भारत भ्रष्टाचार जैसे मुख्य मुद्दों पर भी चुप रहता हैं। "हम कमरे में हाथी-भ्रष्टाचार के बारे में चुप हैं। कानूनों से कोई देश महान नहीं बनता, अच्छे और ईमानदार लोग देश को महान बनाते हैं। किसी ने गांधीजी से पूछा था, "क्या आप नए भारत की खोज कर रहे है। गांधीजी ने उत्तर दिया था, "मै एक नए भारतीय की खोज कर रहा हूॅ।‘’

श्री दोसांझ ने इस बात का उल्लेाख किया कि भारत में 1984 के दंगों, गोधरा दंगों और अभी हाल ही में उत्तार प्रदेश के मुज्जफरनगर दंगों से बचा जा सकता था। "यदि दक्षिण अफ्रीका भेदभाव का अंत कर सकता है तो हम गोधरा और मुज्जफरनगर का अंत क्यों नहीं कर सकते। भविष्य युवाओं का है। हमें एक बेहतर दुनिया की आशा को जिंदा रखना चाहिए जैसाकि गांधीजी का सपना था।"

उन्होने वर्ष 2014 में दिल्ली चुनावों द्वारा किए गए बदलावों की सराहना की। "परिवर्तन को देखकर अच्छा लगा। कोई लाल बत्ती नहीं होनी चाहिए। परिवर्तन की शुरूआत नीचे से होती है। प्रत्येक भारतीय यह समझता है कि भ्रष्टाचार भारत की आत्मा को खाए जा रहा है।" श्री दोसांझ।

उन्होने कहा कि केवल राजनेताओं पर दोषारोपण करने का कोई लाभ नहीं है। श्री दोसांझ ने कहा कि, "सिस्टम को दोष देना ठीक नहीं है क्योंकि हम स्वयं सिस्टम हैं। इसलिए हमें सिस्टम को ही बदलना होगा।"

चित्र

राज्यों में निवेश के अवसर

निवेश के लिए प्रवासियों की क्षमता का दोहन

इस सत्र के दौरान कई राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात, बिहार, मेघालय, केरल, हरियाणा और पंजाब ने निवेश के अवसरों को दर्शाया और भारतीय प्रवासियों से उनके संबंधित राज्यों के विकास और वृद्धि में भूमिका निभाने का आग्रह किया।

चित्र

इस सत्र, जिसकी अध्यक्षता डॉ. मोंटेक सिंह आहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने की, में मुख्य मंत्रियों ने अलग अलग प्रस्तुतियां दी। विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विदेशी निवेश की आवश्यकता को रेखांकित किया।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है और औद्योगिक विकास को बढावा देने के लिए अवसंरचना सृजित किए जाने की आवश्यकता है। डॉ. आहलुवालिया ने अपने भाषण में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को रेखांकित किया।

उन्होने कहा, "यह बात सही है कि विनिर्माण क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा हैं। हमें विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत को बेहतर अवसंरचना की आवश्यकता हैं।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दस्तावेज से यह स्पष्ट पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए अवसंरचना का कितना महत्व है।

उन्होने देश में कारोबार करने की सुगमता के महत्व पर भी बल दिया और कहा कि विनिर्माण कार्यकलापों को बढावा देने के लिए यह एक पूर्व आवश्यकता हैं।

डॉ. आहलुवालिया ने कहा कि "ये अनुमान (सूची रैंकिंग) विभिन्न राज्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। यदि प्रत्येक राज्य श्रेष्ठ राज्य की तरह कार्य करे तो भारत की रैंकिंग 134 से बढकर 67 हो जाएगी।"

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र
प्रत्येक राज्य की दक्षता को उनकी निवेश वृद्धि में दर्शाया गया है। तथा कथित'बीमारू' राज्यों ने गत सात वर्षो में सकारात्मक प्रदर्शन किया है।
- डॉ. मोंटेक सिंह आहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग

चित्र
केरल एक मुख्य मानव संसाधन हब के तौर पर उभरकर सामने आया हैं। स्वास्थ्य, उच्चतर शिक्षा और आईटी इसके फोकस क्षेत्र रहे है क्योंकि ये शानदार अवसरों के मौके प्रदान करते हैं।
श्री ओमान चांडी मुख्यमंत्री, केरल

चित्र
हरियाणा अवसरों की भूमि रहा है। यह कई बहु राष्ट्रीय कंपनियों का घर है और विदेशी तकनीक एवं सहयोग में 1,000 से भी अधिक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।
श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री, हिरयाणा

चित्र
वर्ष 2012 में भारत की आजादी की 65वीं वर्षगांठ पर एक विकसित भारत से बडी कोई श्रद्धाजंलि नहीं हो सकती, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो तथा जिसकी सभी प्रशंसा करते हो और साथ ही स्थानीय स्तर पर प्ररेणादायी, समावेशी, लचीला और एकीकृत हो।
- श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, गुजरात

चित्र
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सभी राज्य सरकारों के अध्यक्षों को इसके सामूहिक और चंहुमुखी विकास के लिए संभावित निवेशकों को आकर्षित करने हेतु क्षेत्र के विपणन हेतु हाथ मिलाना चाहिए।
-डॉ.. मुकुल संगमा, मुख्यमंत्री, मेघालय

योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने इस बात का उल्लेख किया कि राज्य सरकारें राज्यों में होने वाले दो-तिहाई निवेश के लिए स्वंय उत्तरदायी है। अत: यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर है कि निवेश को

लेकर उनकी क्या राय हैं। डॉ. आहलुवालिया ने कहा कि सभी राज्यों को विदेशी और घरेलू निवेशा को आकर्षित करने के लिए सक्रिय और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि "योजना आयोग के तौर पर हम एक चीज करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यह पता लगाने के लिए अपने औद्योगिक समूहों के साथ कार्य कर रहे है कि वास्तव में 'कारोबार करने की सुगमता' को कैसे सुधारा जा सकता है..... हमारे पास पर्याप्त संख्या में ऐसी कंपनियां नहीं है जो छोटे स्तर पर कार्य प्रारंभ करके सही अर्थों में बडी हो जाए।"

केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमान चांडी ने भी प्रवासी निवेश के लिए पुरजोर समर्थन किया। उन्होने कहा कि केरल सूचना और संचार प्राद्योगिकी , पर्यटन, खाद्य और कृषि-संसाधन, स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं, जल प्रौद्योगिकी और हरित उर्जा, जैव-प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश के अत्याधिक अवसर प्रदान करता हैं।

केरल राज्य ने अवसंरचना विकास, पतनों, पोत निर्माण, संभार और कचरा प्रबंधन में निवेश अवसरों को भी रेखांकित किया। श्री चांडी ने कहा कि, "राज्य एक मुख्य मानव संसाधन हब के तौर पर उभरकर सामने आया हैं। स्वास्थ्य, उच्चतर शिक्षा और आईटी इसके फोकस क्षेत्र रहे है क्योंकि शानदार अवसरों (प्रवासियों के लिए) प्रदान करते है।"

"केरल भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में एक अग्रणी राज्य है। राज्य प्रत्येक वर्ष अत्याधिक कुशल कार्यबल प्रदान करता है जो देश में किसी भी अन्य राज्य की अपेक्षा भी अधिक बेहतर और उत्पादक सिद्ध हुआ है।" - श्री चांडी

केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि अद्यतन अधिकारिक अनुमानो के अनुसार उनके राज्य को विदेशी प्रेषणों के माध्यम से 75000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि प्राप्त हुई है ।

केरल की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्होने कहा कि राज्य सरकार ने 100 प्रतिशत साक्षरता हासिल कर ली है और इसने शिक्षा तथा मानव संसाधनों के सवर्धन में भरी निवेश किया है क्योकि राज्य ने अपने वार्षिक बजट का 40 प्रतिशत सभी स्तरो पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आबंटित किया

है ।

उन्होने कहा कि केरल ने कई नीतिगत उपाय किए है तथा निवेशको को आकर्षित करने के लिए कई प्रोत्साहन भी दिए है जिससे राज्य देश का सबसे पसंदीदा निदेश स्थल बनकर उभरा है ।

उन्होने घोषणा कि की राज्य की प्राथमिकता उद्धमशीलता को बढ़ावा देना और रोजगार बाजार का रूपान्तरण करना है । मुख्यमंत्री ने कहा कि “सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली संभवत निवेशको और वित्त पोषको को केरल में आकर्षक अवसर प्रदान करेगी और हम आपका विविध प्रकार के कार्यकर्मों मे स्वागत करते है ।“

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपने सम्बोधन में कहा कि उनका राज्य भारतीय प्रवासियों कि युवा पीढ़ी पर विशेष ध्यान देगा और उन्होने हरियाणा द्वारा प्रदान किए जा रहे विभिन्न निवेश अवसरो का भी उल्लेख किया ।

श्री हुड्डा ने कहा कि ," यह (हरियाणा) काफी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियो का घर है और यहा विदेशी तकनीकी अथवा वित्तीय सहयोग से 10000 से भी अधिक परियोजनाए संचालित की जा रही है । गत वर्ष राज्य की औसत आर्थिक विकास पर 9 प्रतिशत थी जो राष्ट्रीय विकास दर 7.7 प्रतिशत से अधिक थी ।

हरियाणा की औद्योगिक अवसरंचना में विकास की सुविधा हेतु अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के लोगों (पीपीपी) को प्रदान की जा रही विशेष सुविधाओ को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक औधोगिक संपदा में 10 प्रतिशत औधोगिक प्लांट उनके लिए आरक्षित किए गए है । उन्होने प्रवासियों से इस विंडो का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया ।

इसके अतिरिक्त श्री हुड्डा ने कहा कि इच्छुक निवेशको को मार्गदर्शी और परामर्शी सेवाएं प्रदान करने और अप्रवासी भारतीयो एवं भारतीय मूल के लोगों के समक्ष आने वाली संपत्ति, वैवाहिक कलह तथा कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओ का समाधान करने के लिए एक विदेशी निवेश और एन आर आई प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है ।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय निवेश और प्रति व्यक्ति योजनागत बजट आवंटन के संबंध में अधतन आंकडो को भी प्रस्तुत किया, जो उनके अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक थे ।

इसके अतिरिक्त, श्री हुड्डा ने कहा की हरियाणा ने स्वयं को सरप्लस राज्य बना लिया है क्योकि इसकी विधुत उत्पादन क्षमता कुछ वर्ष पूर्व 1.587 मेगावाट से बढ़कर 5.300 मेगावाट तक पहुच गई है । उन्होने कहा कि राज्य की सभी प्रांतो से विधुत उत्पादन क्षमता 10000 मेगावाट है, जो वर्ष 2005 में 4000 मेगावाट थी ।

उन्होने कहा कि "राज्य में तकनीकी संस्थाओ की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है , जो वर्ष 2005 में 161 से बढ़कर वर्ष 2013 में 662 तक हो गई है और इनमे विधार्थियों की दाखिला क्षमता 150000 विधार्थी है ।" उन्होने राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, सोनीपत और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी का उदाहरण भी दिया, जो हरियाणा में शिक्षा संबंधी अवसंरचना परियोजनाओ की दो मुख्य संस्थाए है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) का संदेश में समर्थन करने वाला प्रथम राज्य था और यह आशा व्यक्त की कि एक बार कार्यान्वित किए जाने के बाद यह परोक्ष तौर पर अवसंरचना सर्जित करेगा और अधिक रोजगार पैदा करेगा।

श्री हुड्डा ने कहा कि राज्य ने युवाओं और खिलाड़ियों के बीच खेलों को बढ़ावा दिया और हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और देश को सम्मान दिलाया।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 से भी अधिक देशों में फैले लगभग 25 मिलियन सुढ़ध प्रवासियों ने भारत के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।

श्री मोदी ने कहा, “हजारों मील दूर होने के बावजूद भी आप अपने देश के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।”

उन्होने प्रवासियों से देश की देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भूमिका निभाने का आहवान किया।

उन्होने प्रवासियों से देश की राजनीतिक प्रक्रिया में भूमिका निभाने का भी आहवान किया।

उन्होने कहा, “भारत में आगामी महीनों में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। हमारे देश के इतिहास में इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपको भी पीछे नहीं रहना चाहिए आपको भी इस क्रांति में भाग लेना चाहिए।”

गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रवासियों, विशेष तौर पर जो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं, को प्रवासी भारतीय दिवस, 2015 के दौरान विश्व भर से आए भारतीयों से जुडने का निमंत्रण दिया, क्योंकि यह महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटने का शताब्दी वर्ष हैं।

श्री मोदी के अनुसार, भारत न केवल भारतीय मूल के लोगों से वित्तीय निवेश की आशा करता हैं।

उन्होने कहा कि अभी हल ही के वर्षों में निवेशकों -घरेलू और विदेशी दोनों-में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सीधा राज्यों के साथ संवाद प्रारम्भ किया हैं। इससे राज्यों के बीच अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा की हैं। "यह परवर्ती सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक लाभ प्रदान करेगी और इस प्रक्रिया को गहन करेगी।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच वर्ष बाद देश महात्मा गांधी की जंयती के 150वें वर्ष का आयोजन करेगा और वर्ष 2022 में अपनी आजादी का 65वां वर्ष मनाएगा। इन दोनों अवसरों पर देश को प्रवासियों की भावना और उन शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होने "हमारे भविष्य निर्माण के लिए हमें आजादी प्रदान की।"

उन्होने कहा कि वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75वें वर्ष पर विकसित भारत से बडी कोई श्रद्धांजलि नही हो सकती, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो तथा जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं और साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रेरणादायी, समावेशी, लचीला और एकीकृत हो।

हमें सभी को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने, गांवों और शहरों में गुणावत्ता परक जीवन प्रदान करने, कृषि का विकास करने, उत्पादक तौर पर कार्य करने वाला युवा, बराबर की भागीदार महिलाएं अच्छी भौतिक और सामाजिक अवसंरचना, वैश्विक प्रतिस्पर्धी उद्योग और व्यापार, वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानकों, नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित समाज और अर्थव्यवस्था, वाइब्रेंट लोकतंत्र और सक्रिय तथा जन समर्थित सुशासन को मूर्तरूप प्रदान करने का सच्चे अर्थों में प्रयास करना चाहिए।

श्री मोदी ने अमरूत महोत्सव, भारत@75, का भी उल्ल्ोख किया, जहां "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना से सभी भारतीयों को हाथ और दिलों को मिलाना चाहिए।

डॉ. मुकुल संगमा, मुख्यमंत्री मेघालय, ने अपने भाषण में देश के पूर्वोतर क्ष्ेात्र में भौगलिक बाध्यताओं का उल्लेख किया, जो कभी-कभी एनआरआई और पीआईओ सहित निवेशकों को अपनी सरप्लस धनराशि का निवेश करने से हतोत्साहित करती हैं। हालांकि, उन्होने इस बात पर बल दिया कि संपूर्ण उत्तर पूर्व क्षेत्र में विशेष तौर पर मेघालय में खनिजों सहित नवीन और नवीकरणीय उर्जा स्त्रोतों का दोहन करने की संभावना है और आग्रह किया कि इनका दोहन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

उन्होने कहा कि मेघालय आकर्षक लाभ के वायदे सहित निवेशक-अनुकूल शासन भी प्रदान करता हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्वोतर क्ष्ेात्र की सभी राज्य सरकारों के अध्यक्षों को इस क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के लिए संभावित निवेशकों के लिए क्षेत्र की मार्केटिंग हेतु हाथ मिलाने के लिए भी आग्रह किया।

एक अलग सत्र को संबोधित करते हुए बिहार की उद्योग मंत्री श्रीमती रेणू कुमारी ने कहा कि उनके राज्य को विकास प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रवासियों से सहयोग की आवश्यकता है।

उन्होने कहा कि औद्योगिक विकास और राजय में विकास को बढावा देने के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति, 2011 का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया हैं।

इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न यूनिटों ने बिहार में 5,600 करोड रुपये से भी अधिक का निवेश किया है जिसके बदले इन यूनिटों को 1,000 करोड रुपये से अधिक के विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

श्रीमती रेणू कुमारी ने कहा "कृपया आएं और बिहार में निवेश करें। यहां सभी में क्षेत्रों में संभावनाएं हैं।"

राजस्थान ने अपने विशाल खनिज भंडॉ.रों, बाजार की सुलभता, प्रशिक्षित जनशक्ति, अपेक्षाकृत कम लागतों, भूमि की उपलब्धता, शांतिपूर्ण कानून-व्यवस्था और औद्योगिक संबंधों तथा अन्य राज्यों की तुलना में प्रदान किए जाने अत्याधिक लाभों को रेखांकित किया।

अपने प्रस्तुतिकरण में, राजस्थान के अधिकारियों ने कहा कि राज्य विद्युत की उपलब्धता में सुधार कर, विश्व-स्तरीय राजमार्गो और सडकों को प्राथमिकता प्रदान कर इस लाभ की स्थिति को और व्यापक बनाएगा।

पंजाब के अधिकारियों ने प्रवासियों से निवेश का आग्रह करते हुए कहा कि "यहां अच्छी अवसंरचना, उद्योगों के लिए आकर्षक पॉलिसी पैकेज, पंजाब का कारोगार करने की दृष्टि से सुकर बनाने के प्रयास, प्रचुर प्रतिभा और कौशलों की उपलब्धता, जीवन की बेहतर गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धी संचालन लागत, समृद्ध अर्थव्यवस्था और प्रभावी उपभोक्ता आधार, अग्रणी कृषि राज्य, बडॉ. औद्योगिक आधार, बडे बाजारों की सुलभता और उत्कृष्ट औद्योगिक और श्रम संबंध हैं।"

निवेश अवसरों का प्रदर्शन

विभिन्न राजय सरकारों के शीर्ष अधिकारियों ने प्रवासियों की तरफ से निवेश आकर्षित करने के प्रयास में अपने संबंधित क्षेत्रों में अवसरों को रेखांकित किया।

राजस्थान

चित्र

श्री विनोद अजमेरा, आयुक्त, राजस्थान फांउडेशन एवं आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार ने अपनी प्रस्तुति में यह कहते हुए राजस्थान की विरासती संरचनाओं और पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को रेखांकित किया कि यह किलों, महलों और हवेलियों की धरती है, समृद्ध कला, संस्कृति और दस्तकारी, जीवंत और रंगीली जीवन परंपराओं, विश्व प्रसिद्ध मेलों और त्योहारों और अपने आतिथ्य-सत्कार के लिए मशहूर लोगों की धरती हैं।

उन्होने तीर्थ स्थलों जैसे अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और अन्य स्थलों, विश्व प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारणों और राष्ट्रीय उद्यानों तथा 'स्वर्णिम त्रिभुज' (दिल्ली-जयपुर-आगरा) के प्रसिद्ध पर्यटन सर्किट का भी उल्लेख किया। उन्होने राजस्थान पर्यटन यूनिट नीति-2007 का भी वर्णन किया, जिसमें न केवल होटलों को शामिल किया गया है अपितु पर्यटन यूनिटों जैसे-स्पॉज, गोल्फ अकादमियों, कक्षों सहित गोल्फ कोर्स, पडॉ.व स्थलों इत्यादि को भी शामिल किया गया हैं।

निवेशकों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के संबंध में उन्होने कहा कि कृषि भूमि को शहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि को गैर-कृषि कार्यों के लिए परिवर्तित करने हेतु कोई परिवर्तन प्रभार नहीं वसूला जाता है।

श्री विनोद अजमेरा कहा कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि आबंटन को बढाया गया है और विभिन्न पर्यटन यूनिटों के लिए विशेष आरक्षित मूल्य स्थानीय क्षेत्र की जिला स्तरीय समिति दर (डीएलसी) पर ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र के वाणिज्यिक आरक्षित मूल्य का 10 से 50 प्रतिशत रखा गया हैं।

उन्होने कहा कि आवासीय भूमि और भवनों, जिनका उपयोग शहरी क्षेत्रों में बिना अनुमति के होटलों अथवा अन्य पर्यटन यूनिटों के संचालन के लिए किया जा रहा है तथा प्रचालन में हैं, का नियमितीकरण राजस्थान म्यूनिसिपल नियमावली, 2000 के तहत 25 प्रतिशत नियमिती करण शुल्क के भुगतान के बाद मेरिट के आधार पर करवाया जा सकता हैं।

सुश्री वीनू गुप्ता, प्रधान सचिव, उद्योग और एमडी, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश (आरआईआईसीओ) ने अपने भाषण की शुरूआत राजस्थान को विभिन्न रंगो वाले इन्द्रधनुष के रूप में

चित्रित करते हुए की-जिसका मुख्य फोकस पर्यटन और उद्योग पर है और अन्य के साथ साथ इनके उप-क्षेत्रों पर हैं।

उन्होने कहा कि राजस्थान राज्य अपनी समृद्ध खनिज और संबंधित उद्योगों, पर्यटन और वस्त्र उद्योग के लिए मशहूर है और यह ऑटोमोबाइलस, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं और सौर उर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति कर रहा हैं।

सुश्री गुप्ता कहा कि राजस्थान, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत (342,239 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र है और यहां सुविकसित अवसंरचनात्मक सुविधाएं है, उभरता हुआ स्वास्थ्य और शिक्षा हब, प्रगतिशील कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार सहित स्थिर राजनैतिक माहौल और सुदृढ कानून-व्यवस्था तथा शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध हैं।

प्रधान सचिव, उद्योग ने कहा कि राज्य में विश्व स्तरीय बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (एकईजेड) हैं। उन्होने 750 एकड भूमि पर विकसित अद्यतन आईटी एसईजेड सहित जयपुर में पहिंद्रा वर्ल्ड सिटी, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी पार्क, छिलोत में कोरियाई पार्क (विकसित किया जा रहा है), राज्य में सबसे बडे जयपुर अलवर और जोधपुर में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों (ईपीआईपी), जयपुर में रत्न और जवाहरात एवं दस्तकारी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा किशनगढ (अजमेर) में तैयार किए जा रहे मेगा फूड पार्क का उल्लेख किया।

सुश्री गुप्ता कहा कि राज्य में कच्ची सामग्रियों की आसान उपलब्धता है। उन्होने कहा कि, "राज्य में 79 प्रकार के खनिज है जिनमें से 58 का वाणिज्यिक दोहन किया जा रहा हैं।" इसके अतिरिक्त, राजस्थान देश का दूसरा सबसे बडॉ. सीमेंट उत्पादक राज्य है जिसकी कुल क्षमता 44 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। यह सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर और स्टील ग्रेड चूना पत्थर का भी अग्रणी उत्पादक राज्य हैं।

सुश्री गुप्ता के अनुसार दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे का लगभग 39 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा। यह एक उच्च प्रभाव वाला औद्योगिक क्षेत्र है, जो समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) के दोनों तरफ 150 कि.मी. के दायरे में है और यहां 90 मिलियन अमेरिकी डॉ.लर की निवेश संभावनाएं हैं। उन्होने कहा कि निवेश के मुख्य फोकस क्षेत्र अवसंरचना, विद्युत, सेरेमिक(चीनी मिट्टी) एवं कांच, ऑटो एवं ऑटो एनसिलिएरिज, सौर उर्जा एवं विनिर्माण, आईटी एवं आईटीईसी, सीमेंट एवं खनिज, कृषि संसाधनों, वस्त्र, पर्यटन, रत्न और जवाहरात और शिक्षा हैं।

श्री एन के बजाज ने राजस्थान के कनाडॉ. के साथ सहयोग के संबंध में भाषण दिया, जहां प्रचुर अध्ययन अवसर और जानकारियां साझा करने के अवसर हैं।

श्री रमन कुमार शर्मा, निदेशक एवं उपाध्यक्ष, होडॉ. सिटी कार लिमिटेड इंडिया ने तयुकडॉ.(भिवाडी), राजस्थान में होंडॉ. निर्माण यूनिट स्थापित करने और इसके कार्यान्वयन के दौरान राजय में अपने बेहतर अनुभवों का उल्लेख किया। उन्होने राज्य द्वारा निवेशकों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों के बारे में बताया। सरकार विकास, सुधार की इच्छुक और संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाने वाली है। विद्युत की स्थिति

अच्छी होने के साथ ही उन्हे प्रतिस्पर्धी औद्योगिक संबंधों वाला परिवेश भी मिला। सुश्री शर्मा ने कहा कि निर्माण यूनिट अपनी पहली कार, इसके प्रारंभ होने के 7 वर्ष के भीतर मार्च, 2014 तक बाजार में ले आएगी।

श्री नंदा पोद्दार, शिक्षाविद्, ने राजस्थान में उपलब्ध प्रचुर कौशल विकास संभावनाओं का उल्लेख किया। उन्होने कहा कि राजस्थान में स्वदेशी ज्ञान प्रणाली का पुनरूद्धार करने की संभावना हैं। अध्यापकों के प्रशिक्षण सहित कौशल विकास पर विशेष ध्यान मुख्य एजेंडॉ. होना चाहिए। सुश्री पोद्दार के अनुसार, राजस्थान को विश्व सांस्कृतिक स्थल के तौर पर दर्शाया जा सकता हैं।

बिहार

चित्र

बिहार पर एक अलग सत्र के दौरान, राज्य सरकार के अधिकारियों ने राज्य की एक आकर्षक निवेश स्थल की संभावनाओं पर प्रकाश डॉ.ला।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास और संवर्धन के दृष्टिकोण से औद्योगिक संवर्धन नीति, 2011 को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। उन्होने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बिहार में कारोबारियों ने 5,600 करोड रुपये से भी अधिक का निवेश किया है, जिसके एवज में उन्हें 1000 करोड रुपये से भी अधिक का प्रोत्साहन प्रदान किया गया हैं।

अधिकारियों ने दर्शकों को बताया कि कम से कम 191 यूनिटों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है और इसके अतिरिक्त 184 यूनिटों में उत्पादन का कार्य विभिन्न चरणों में हैं। गत एक वर्ष में 91 यूनिटों ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया है जिससे राज्य में 495 करोड रुपये का निवेश हुआ हैं। गत एक वर्ष में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में दिए गए प्रोत्साहन के कारण प्रति वर्ष चावल मिलों की क्षमता में 800,000 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने कहा कि निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए इस वर्ष एक नई नीति अधिसूचित की गई है, जिससे निजी उद्यमियों को अपनी यूनिट स्थापित करने हेतु भूमि का प्रबंध करने में सुविधा मिलेगी।

राज्य सरकार ने भी राजय में सूक्ष्म, माध्यम और लघु उद्यमों(एकएसएमई) के विकास हेतु 'मुख्यमंत्री' सुक्ष्म एवं लघु कलस्टर योजना' प्रारंभ की हैं।

अधिकारियों ने निवेशकों के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के समाधान की योजनाओं को भी रेखांकित किया। उद्योग और उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में संवाद स्थापित करने के लिए गत एक वर्ष से उद्यमी पंचायतों का आयोजन किया जा रहा हैं। उन्होने कहा कि पटना में डॉ.यमंड पॉलिशिंग यूनिट की स्थापना राज्य में औद्योगिकरण के एक बिल्कुल को दर्शाती हैं।

गुजरात

प्रवासी भारतीय दिवस में गुजरात के लिए एक विशेष संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सवयं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। इस विचार-विमर्श में भाग लेने वाले अन्य लोगों में श्री प्रदीप सिंह जडेजा, राज्य मंत्री, गुजरात सरकार और श्री पकंज कुमार, प्रधान सचिव, एन आर आई प्रभाग, गुजरात शामिल थें।

अपने स्वागत भाषण में श्री जडेजा ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बारे में उल्लेख किया और यह बताया कि गुजरात सरकार ने पत्तनों और सडकों जैसी विश्व-स्तरीय और बेहतर अवसंरचना के लिए किस प्रकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली का उपयोग किया।

उन्होने विकास प्रक्रिया में सभी की भागीदार सुनिश्चित काने वाली गुजरात की विशिष्ट रणनीति का भी उल्लेख किया। श्री जडेजा ने कहा कि गुजरात "सबका साथ सबका विकास" (सभी के सहयोग से सबका विकास) मंत्र पर कार्य करता हैं। उन्होने कहा कि यह उस परम्परागत दृष्टिकोण में बिल्कुल अलग है जिसमें सरकार को दाता और लोगों को ग्राही समझा जाता हैं।

राज्यमंत्री ने कहा कि गुजरात में समावेशी विकास के प्रयास न केवल सरकार की नीतियों के माध्यम से किए जा रहे हैं अपितु समग्र तौर पर समाज के कार्यों से भी किए जा रहे हैं। उन्होने कहा कि विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली वाली परियोजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र की सहभागिता 'जन भागीदार' (लोगों की सहभागिता) तथा लोक सेवकों की बेहतर भागीदारी से किया जा रहा हैं।

उन्होने प्रवासियों का अपने मेजबान देशों में भारत और विशेष तौर पर गुजरात में निवेश के लिए लाकिंग करने के लिए किया, जो उनकी द्वीवार्षिक निवेश समारोह वाईब्रेंट गुजरात में उनकी भागीदारी से स्पष्ट था।

उन्होने अप्रवासी गुजराती समुदाय द्वारा गुजरात के विकास हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों का भी उल्ल्ोख किया। श्री जडेजा ने कहा, "गत दशक में बहुत से लोग उस समुदाय की बेहतरी, जिससे वे स्वयं आते हैं, के लिए अपने पैतृक गांवों में विश्व-स्तरीय स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण हेतु दान करने के लिए वापस आए हैं।

गुजरात राज्य अप्रवासी गुजराती प्रतिष्ठान ने भारतीय मूल के लोगों और अप्रवासी भारतीयों द्वारा ऐसे सभी प्रकार के दान को इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचित पुस्तक "वतन सेवा-भावनाओं की स्वीकृति" में अभिलिखित किया है।

इस अवसर पर गुजरात के विकास के संबंध में एक लघु फिल्म भी दिखाई गई।

श्री मोदी ने अपने भाषण में सामाजिक कार्यों के लिए योगदान हेतु प्रवासियों का धन्यवाद किया। उन्होने पर्यटन और अवसंरचना क्षेत्रों में गुजरात की सफलता की कहानी को साझा किया, उन्होने कहा कि

गुजरात में पर्यटन को बढावा देने के लिए उन्होने श्री अमिताभ बच्चन को ब्रांड एंबेसडर बनाया है-जिससे राज्य में अधिक संख्या में पर्यटकों को लाने में सहायता मिली है।

उन्होने भारतीय प्रवासियों को कच्छ के रण में रण उत्सव के तीन माह चलने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होने कहा कि गुजरात का फोकस छह विश्व स्तरीय औद्योगिक शहर विकसित करने पर है और उन्होने धोलरा एनआईआर का उदाहरण दिया, जिसे वैश्विक और व्यापार हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है, उन्होने ऐसे शहरों को "देश के आर्थिक पुनउत्थान का इंजन" बताया।

श्री पंकज कुमार ने श्री मोदी ओर अन्य भाग लेने वालों का अपने विचार व्यक्त करने तथा प्रवासियों का गुजरात राज्य सत्र में पूरे उत्साह से भाग लेने, जिसमें 300 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया, के लिए धन्यवाद किया।

पंजाब

चित्र

बारहवें प्रवासी भारतीय दिवस में पंजाबी प्रवासियों को संबोधित करते हुए डॉ. करण अवतार सिंह, प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य, पंजाब सरकार ने कहा कि राज्य सरकार ने कारोबार के लिए वहनीय माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

श्री सिंह ने कहा, "राज्य सरकार ने निवेश आार्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस प्रयोजन के लिए पंजाब निवेश संवर्धन ब्यूरो (पीबीआईपी) का गठन किया गया है। उन्होने कहा कि यह ब्यूरो प्रत्येक निवेशक के लिए संबंध अधिकारी के तौर पर वरिष्ठ नागरिक प्रदान करेगा।

उन्होने कहा कि सरकार ने उद्यमियों के लिए एकल खिडकी सेवा प्रारंभ की है। इस प्रणाली के अंतर्गत पंजाब ने कारोबार प्रारंभ करने के लिए विभिन्न विभागों की आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ही आवेदन-पत्र तैयार किया है। उन्होने कहा कि मंजूरी बिना भागदौड समयबद्ध तरीके से प्रदान की जाएगी।

श्री सिंह ने श्रोताओं को सूचित किया कि, "पंजाब ने नागरिक-केंन्द्रित अभिशासन प्रदान किया है और सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है जिसमें लगभग 149 सेवाओं को शामिल किया गया है। सरकार ने थानों में "सांझ केंद्र" नामक ऑनलाइन केंद्र तथा ई-जिला "सुविधा केंद्र" प्रारंभ किए हैं।

श्री सिंह अनुसार, राज्य की नई औद्योगिक नीति के चार मुख्य उद्देश्य है:-

- डीलर्स और विभाग के बीच न्यूनतम अंतरापृष्ठ
- एक ही चरण पर कराधान
- समर्पित रिफंड निधि

- रिफंड में तेजी लाने के लिए रेटिंग योजना

उन्होने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में सरकार ने मूल्य संवर्धित कर (वेट) और केंद्रीय बिक्री कर (सीएमटी), विद्युत शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में कई तरह के प्रोत्साहन प्रदान किए हैं।

उन्होने कहा कि पंजाब सरकार ने वेट (मूल्य संवर्धित कर रिफंडस का स्थायी समाधान करने के लिए पंजाब वेट रिफंड निधि नामक एक समर्पित कार्मिक निधि का गठन किया हैं।

पंजाब विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए भी काफी कार्य कर रहा हैं। "इसलिए यहॉ उन लोगों के लिए भी बेहतर अवसर हैं जो विद्युत क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं।"

श्री सिंह ने कहा "राज्य में देश का सबसे बेहतर सडक नेटवर्क है और यहां प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 133 किलोमीटर का उच्चतक सडक घनत्व है। 2900 करोड रुपये के निवेश से 567 किलोमीटर लंबी सडकों संबंधी 11 परियोजनाओं का विकास किया जाएगा।" उन्होने कहा कि अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता औद्योगिक गलियारा, जिसमें अमृतसर, जालंधर और लुधियाना शहर शामिल हैं, क्षेत्र के औद्योगिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य करेगा।

उन्होने कहा कि इस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तकफ 150-200 किलोमीटर के दायरे में विकास किए जाने से लगभग पूरा राज्य इसके अंतर्गत आता हैं।

अपने संबोधन में, जस्टिस अरविंद कुमार गोयल, अध्यक्ष, एनआरआई आयोग ने कहा कि आयोग राज्य में अप्रवासियों के हितों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु कार्य कर रहा है। उन्होने आयोग की उपलब्धियां जैसे एनआरआई के लिए अनिवार्य तौर पर विवाह पंजीकरण, विदेश में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने विदेशों में पंजाबियों की अवैध हिरासत और यूएसए में पंजाबियों पर हमले इत्यादि की स्थिति में प्रभावित राहत निधि, को रेखांकित किया।

उन्होने पंजाबी प्रवासियों को यह बताया कि पंजाबी मूल के सभी एनआरआई को विशेष, विशेषाधिकार कार्ड प्रदान किए गए है, जिससे वह विभिन्न दुकानों, मॉल इत्यादि में छुट प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्ड का उपयोग एनआरआई के बच्चों का शिक्षा संस्थाओं में दाखिले हेतु आरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह दाखिले में कोटा प्रदान करता हैं।

केरल

चित्र

केरल ने उन क्षेत्रों का निर्धारण किया है जिनमें तेज गति से विकास किए जाने की संभावना है, जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खाद्य और कृषि संसाधन स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं, जल प्रौद्योगिकी, नैनो टैक्नोलॉजी, और अन्य सनराइज क्षेत्र, शहरी अवसंरचना, पतनों, पोत निर्माण और संचार सहित अवसंरचना एवं कचरा प्रबंधन। केरल भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्य हैं।

केरल प्रति वर्ष उच्च कौशलयुक्त कार्यबल प्रदान करता है, जो देश में किसी भी अन्य राज्य की अपेक्षा अधिक उत्पादक और बेहतर सिद्ध हुआ हैं। केरल ने शिक्षा और मानव संसाधन के संवर्धन में भारी निवेश किया हैं।

किसी भी अन्य राज्य ने अपने वार्षिक बजट का 40 प्रतिशत शिक्षा के लिए निर्धारित नहीं किया है। केरल मानव संसाधन का एक हब बन गया है जो अन्य देशों की आवश्यकताओं को पूरा करता हैं।

समवर्ती सत्र 1

नवाचार और प्रौद्योगिकी

भविष्य के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित करना

चित्र

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एडं इंडस्ट्री (फिक्की), विज्ञान और प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण करने पर कार्य कर रहे हैं। गत पॉच वर्षों में लगभग 150 प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण किया गया है, जिससे 1500 करोड रुपये का बाजार विकसित हुआ हैं।

चित्र

डॉ. ए. दीदार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)के पूर्व नौकरशाह और महासचिव, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एडं इंडस्ट्री (फिक्की) ने कहा कि भारत ने 2010-2020 के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया है, जो प्रधानमंत्री की भारत को अधिक नवाचारी और वैज्ञानिक बनाने की नीति का एक भाग हैं।

उन्होने कहा गत चार वर्षों में इस दिशा में कई पहलें की गई हैं। डॉ.. सिंह ने फिक्की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण इसके सामान्य और प्रभावी माध्यम पर कार्य कर रहे हैं। गत पॉच वर्षों में लगभग 150 प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण किया गया है, जिससे 150 करोड रुपये का बाजार विकसित हुआ हैं।

सुश्री एस.रमादोराई, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण ने अपने भाषण में कौशल विकास के महत्व पर बल दिया। उन्होने कहा कि इस समय भारत में राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मोर्चो पर इतना सब कुछ घटित हो रहा है। भारत बदल रहा है और लोगों की आंकाक्षाएं अपने उच्चतम स्तर पर हैं। "आज भारत के समक्ष कौशल विकास की चुनौतियां हैं। भारतीय युवाओं को रोजगार की संभावनाओं उच्च कौशलयुक्त कार्यक्रमों, उद्यमशीलता कार्यकलापों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उन सबका परिणाम रोजगार पैदा करने के रूप में होना चाहिए।

उन्होने रोजगार अवसरो को बढाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होने इसमें प्रौद्योगिकी और नवाचार की प्रासंगिकता तथा इसमें प्रवासियों की भागीदारी पर चर्चा की। लगभग 70 प्रतिशत भारतीय युवाओं को 2050 तक काम की जरूरत होगी और इन मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। भारत सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढावा दे रही है।

सुश्री रमादोराई ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि फिक्की जैसी संस्थाओं को प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। "उन्होने देश में क्षमता निर्माण औरनई नवाचारी सकेंद्रण प्रणालियों तथा शिक्षा के लिए नवाचार समर्पित मल्टी-मॉडल्स के लिए एनएसडी

निधि का उल्लेख किया। उन्होने हाल ही के वर्षों में अस्तित्व में आए विभिन्न जोब पोर्टल्स का भी उल्लेख किया, जो शहरी और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार विकसित करने में सहायता कर रहे हैं। आज सुदृढ सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने में सहायता कर रही हैं। सरकार द्वारा प्रौद्योगिकियों और मित्तव्ययी नवाचारों पर कई अनुदानों का भारी व्यय किया गया हैं।

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र
भारत ने 2010-2020 दशक को नवाचार दशक के रूप में घोषित किया है जो प्रधानमंत्री की एस राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के तौर पर अधिक नवाचारी और वैज्ञानिक बनने की नीति का एक भाग हैं।
-डॉ.. ए. दीदार सिंह, महासचिव, फिक्की

चित्र
भारत का लगभग 70 प्रतिशत युवा वर्ष 2050 तक कार्य बल होगा और उनके मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। - श्री सुब्रमणियम रमादोराई, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए)

चित्र
भारत को नए और मूल नवाचारों की अवश्यकता हैं और ऐसा केवल इस क्षेत्र मेन अनुसंधान और विकास के माध्यम से ही संभव हैं।
-श्री बिरेंद्र (राज)दत्त पीएच.डी. अध्यक्ष एवं सीईओ, एपीआईसी कॉरपोरेशन एडं फोटो आईसी कॉरपोरेशन

चित्र
भारत मानव संसाधन और विशेष तौर पर युवा जनसंख्या के अर्थों में काफी सुदृढ है। नवाचार निवेश परितंत्र में काफी परिवर्तन हो रहे हैं - श्री प्रसाद यरलागड्डा, क्वीन्सलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ब्रिसबेन आस्ट्रेलिया

उन्होने निम्नलिखित सुझाव दिया:

- प्रवासी अपनी मातृभूमि से अपने नए विचारों को लाकर श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा कर सकते हैं
- वे भारत में नवाचार और प्रोद्योगिकी क्षेत्र में निधियाँ ले सकते हैं।
- वे भारत में एक डिजिटलीकृत विषय वस्तु पुस्तकालय की स्थापना में सहायता कर सकते हैं ।
- वे दोनों देशों की संस्थाओ को एक साथ एक मंच पर लाकर भारत में संयुक्त सस्थाओ की स्थापना करने के लिए कह सकते हैं ।
- वे भारत के साथ नए उपकरणों/तकनीकों की प्रोद्योगिकीयों को साझा कर सकते हैं।

उन्होने भारतीय प्रवासियों से स्वेच्छा से विशेष प्रस्ताव तैयार कर भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के पास भेजने और उनकी फीडबैक तथा सुझावों के लिए भी आग्रह किया।

अपने समापन सम्बोधन में उन्होने कहा की भारत में अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने की परवर्ती पहले ही प्रारम्भ हों चुकी हैं और वर्तमान में अनुसंधान हेतु कई निधियाँ जैसे आईपी संरक्षण, निधि, सामाजिक नवाचार निधि, प्रोद्योंगिकी विकास निधि इत्यादि उपलब्ध हैं। भारत में प्रौद्योगिकी जानकारियों का संरक्षण करने के लिए सुदृढ़ आईपीआर कानून हैं। भारत में कई सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यकर्मों का सफलतापूर्क संचालन किया जा रहा हैं।

उन्होने सुझाव दिया कि भारत सरकार कौशल विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकती हैं:

- प्रत्येक विषय के लिए क्षेत्र कौशल परिषद
- रोजगार भूमिकाओं के लिए दक्षताएँ

प्रोफेसर प्रसाद मरलागदधा ने भारत, हाँगकाँग, सिंगापुर, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में उद्योग तथा विश्वविदयालयों में 30 वर्ष तक कार्य किया हैं। वे कुवींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्मार्ट सिस्टम रिसर्च थीम (2005-2009) के संस्थापक निदेशक थे। उन्होने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने असाधारण योगदान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से कई अवार्ड प्राप्त किए हैं। उन्हें अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में सामग्री और विनिर्माण इंजीनियरींग विषय में असाधारण योगदान के लिए वर्ल्ड अकादमी आफ मेन्यूफक्चारिंग एंड मटिरील्स द्वारा फ्रेडरिक स्टाब गोल्डन आकुल अवार्ड प्रदान किया गया ।

उन्होने कहा कि प्रौद्योगिकियों अनुसंधान और विकास के लिए निधियाँ सीमित हैं। उन्होने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों कि बराबर की भागीदारी पर बल दिया। इसके बाद उन्होने अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बात की, जिसमें निम्नलिखित उद्योग शामिल थे:

- आटोमेटिव उद्योग
- खनन उद्योग और
- प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन इंडस्ट्री

उन्होने औस्ट्रालिया के बारे में निम्नलिखित सूचनाओं को साझा किया:

- ऑस्ट्रेलिया विनिर्माण के लिए उपयुक्त स्थान नहीं हैं और उत्पादन के लिए बहुत महँगा हैं
- ऑस्ट्रेलिया में कौशल बहुत महँगा हैं और पूर्व में दिए गए सुझाव के अनुसार त्रुटियों को दूर नहीं किया हैं
- ऑस्ट्रेलिया में उच्च उत्पादक प्रौद्योगिकियों पर ध्यान दिया जाता हैं
- पर्यावरण संरक्षण लागत ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक हैं और इसके लिए मंजूरियाँ प्राप्त करना काफी मुश्किल हैं
- ऑस्ट्रेलिया में 35 वर्ष से कम आयु की युवा जनसंख्या बहुत अधिक हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया में आगामी वर्षों में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों का एक बड़ा समूह होंगा।

उन्होने आज भारत में उपलब्ध संसाधनो के विशाल समूह का भी उल्लेख किया। इसके बाद उन्होने अडॉ.नी, जीवीके, निवेश का उद्धारण दिया। उन्होने विमानन उद्योग मेन अपने अनुभवों को साझा किया जहां उन्होने विमानपत्तनों पर सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उन्होने कहा की उन्होने

जीवीके विमानपत्तनों के साथ विमानपत्तनों सुरक्षा के भविष्य के संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होने फ्रेक्चर फिक्शन के लिए ऑप्टिकल एनाटोमिकल प्रिंट संबंधी द्वितीय केस अध्ययन का भी उल्लेख किया। उन्होने एलगोरिथम का विकास किया हैं जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की ट्रामा और आर्थोपेडिक सर्जरी रोबोट की सहायता से की जा सकेंगी तथा विदेशों में कई अस्पतालों द्वारा इस प्रोद्धयोगिकी का प्रयोग कैसे किया जा रहा हैं।

अपने सम्बोधन मे उन्होने कहा कि भारत मानव संसाधन विशेष तौर पर युवा जनसंख्या के अर्थो में काफी सुदृढ़ हैं। नवाचार निवेश परितंत्र में काफी परिवर्तन हो रहे हैं। गत दस वर्षो की तुलना मे मौद्रिक संपदा काफी आगे बढ़ चुकी हैं परंतु और प्रगति करने के लिए हमें सरकार की तरफ से भारत में नवाचार परितंत्र के प्रोत्साहन हेतु एक दृढ़ प्रतिबद्धता चाहिए ।

डॉ। राज दत्त फोनेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राकृतिक और अनिवार्य सीक्वेंस के मोर्चा पर नई प्रोद्योगिकी उद्यमिता के अग्रेता हैं। भौतिक विज्ञान, फ्लूड मैकेनिक्स, इमेज अण्डरस्टैंडिंग, रोबोटिक्स और कृत्रिम आसूचना में उनके अनुसंधान और योगदान ने उन्हे सूचना अंतरण और प्रोसेसिंग में हमारी भविष्य की आकांक्षाओ को पूरा करने में ऑप्टिकल नेटवर्कों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में रूपांतरकारी समझ प्रदान की हैं। न केवल एक दूरदृष्टा के तौर पर अपितु उनके व्यवहारिक प्रयास सेमिकंडक्टर्स से विशाल नेटवर्कों के सम्पूर्ण फोटोनिक इंटरकनेक्टस स्पेक्ट्रम तक फैले हुए हैं।

उन्होने आर एंड डी निवेशों, नवाचारों, विवादित प्रद्योगिकियों और वैश्विक नेतृत्व के बीच संपर्क स्थापित करने पर बल दिया। उन्होने फोटोन (प्रकाश के कण) संबंधी अपने कार्य का उल्लेख किया। उनका मत था कि केवल नवाचार भविष्य निर्माण नहीं कर सकता अपितु इसके लिए निवेश की भी आवश्यकता हैं। उन्होने भारत सरकार और उद्योग से अनुसंधान और विकास और मुख्य तौर पर हार्डवेयर की खरीद में निवेश आवश्यक हैं ताकि भारत से गरीबी मिटाने में सहायता मिल सके।

भारत में अनुसंधान और विकास सुविधाओं में निवेश न किए जाने के कारण यहाँ से सॉफ्टवेयर उद्योग में प्रतिभा पलायन हो रहा हैं एपल अपने प्रोद्योगिकी पार्ट के कारण आईफोन से भारी लाभ कमा रहा हैं जबकि चीन जैसे देश, जो इसके कलपुर्जों को असेंबल करते है, बहुत कम लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत कम लाभ प्राप्त करते हुए भारत को नये और मूल नवाचारों की आवश्यकता हैं और ऐसा केवल इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास द्वारा ही संभव हैं। उन्होने कहा कि आगे बढने का तरीका - जोखिम लेना और युवाओं को शामिल करते हुए अनुसंधान और विकास में निवेश करना । उन्होने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि भारत को केवल सेवा प्रदाता के बजाय नवाचारी राष्ट्र के तौर पर भी उभरने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे नवाचारों के संबद्ध में आईपी संरक्षण पर अत्यधिक बल दिया और इसे एक साधारण उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि किस

प्रकार एप्पल भारत में एक फोन 250 अमेरिकी डॉलर में बेचकर 150 अमेरिकी डॉलर का लाभ कमा रहा हैं।

समवर्ती सत्र-2

भारत में स्वास्थ्य देख-रेख अवसर

स्वास्थ्य धन भी है

केंद्र सरकार द्वारा गत कुछ वर्षों में 35 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों को 1,11,000 करोड़ रुपये भी जारी गए किए हैं।

चित्र

"भारतीय स्वास्थ्य देख-रेख उद्योग के वर्तमान स्तर को 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2017 में 160 बीलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुच जाने कि संभावना को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने 39 और चिकित्सा महाविद्यलयों को सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों के तौर पर स्तरोन्नपन करने का निर्णय लिया है ताकि अधुनातन तृतीयक स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान की जा सके। सुश्री संतोष चौधरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री ।

उन्होने सूचित किया कि गत 6-7 वर्षों में 10 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों को सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों के रूप में स्तरोन्नपन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गत कुछ वर्षों में 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 1,11,000 करोड से अधिक रुपये भी जारी किए गए हैं।

सरकार के ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य मिशनों पर प्रकाश डॉ.लते हुए उन्होने कहा, "सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार करने के लिए नए निर्माण और उन्नयन कार्य सहित लगभग 51,000 स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की गई है, देश भर में अनिवार्य और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं में 70,000 बेड और शामिल किए गए हैं।"

मंत्री ने कहा कि 12वीं योजना अवधि में, सरकार लोगों के लिए औषधियों और उपचार की सुलभ अनिवार्य रेंज प्रदान करते हुए देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्रदान करने हेतु पहलों को सुदृढ करेगी। आयुष सेवाओं, शिक्षा संस्थाओं, औषधियों के गुणवता नियंत्रण और औषधीय पौधों के समग्र विकास हेतु सरकार एक राष्ट्रीय आयुष मिशन, कार्यान्वित करने की योजना बना रही है जिसके माध्यम से यूएचसी में परम्परागत चिकित्सा प्रणालियों द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने का आशय रखा गया हैं।

सुश्री संगीता रेड्डी, कार्यकारी निदेशक, अपोलो अस्पताल ने सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्वास्थ्य देख-रेख की मांग और आपूर्ति में असंतुलन बहुत ज्यादा बढ गया है। इसका तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता है ताकि बढते हुए अतंर को दूर किया जा सके और भारत लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। गत कुछ वर्षों में, भारत ने स्वास्थ्य देख-रेख क्षेत्र में काफी उपलब्धियां प्राप्त की है परंतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से काफी कुछ किया जाना शेष हैं।

डॉ.. जयेश बी शाह, एमडी एवं अध्यक्ष, एएपीआई, यूएसए ने कहा कि यूएसए में कार्य कर रहे भारतीय मूल के काफी संख्या में डॉक्टरों ने, जहां कही भी संभव हुआ, विभिन्न पायलट परियोजनाओं के माध्यम से भारत में रोगियों का उपचार करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी ही एक परियोजना 'सेवक' है, जिसे अहमदाबाद में प्रारंभ किया गया है। यूएसए के डॉ.क्टरों में जुडॉ.व की भावना है और वे महसूस करते हैं कि परोपकार की भावना से अपनी मातृभूमि की सेवा करने की उनकी बारी हैं।

डॉ.. अशोक सेठ, अध्यक्ष फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट, ने स्वास्थ्य देख-रेख क्षेत्र में उभरते हुए अवसरों का उल्लेख किया और कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से इनका लाभ उठाया जा सकता है। अवसंरचना विकसित करने की मौजूदा नीतियों के स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, परंतु इस संबंध में कार्रवाई नही की गई जिसके लिए केवल सरकार पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता।

इस विषय पर विचार-विमर्श में भाग लेने वाले आम लोगों में डॉ.. नंदिनी टंडन, उपाध्यक्ष एवं बोर्ड सदस्य, ईएल केमिनो अस्पताल, सिलिकॉन वेली और श्री ई.एम. नजीब, काग्रकारी निदेशक, केरल चिकित्सा विज्ञान संस्थान शामिल थे।

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र
स्वास्थ्य देख-रेख क्षेत्र की मांग और आपूर्ति में असंतुलन काफी बढ गया है। इसका तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता है - सुश्री संगीता रेड्डी, कार्यकारी निदेशक, अपोलो अस्पताल

चित्र
12वीं योजना अवधि में, सरकार लोगों के लिए औषधियों और उपचार की सुलभ अनिवार्य रेंज प्रदान करते हुए देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्रदान करने हेतु पहलों को सुदृढ करेगी।
- सुश्री संतोष चौधरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री

चित्र
यूएसए में कार्य कर रहे भारतीय मूल के काफी संख्या में डॉ.क्टरों ने, जहां भी संभव हुआ, अहमदाबाद में प्रारंभ की गई 'सेवक' जैसी पहल के माध्यम से भारत में रोगियों का उपचार करना प्रारंभ कर दिया है।
- डॉ.. जयेश बी शाह, एमडी एवं अध्यक्ष, एएपीआई, यूएसए

चित्र
अवसंरचना विकसित करने की मौजूदा नीतियों में स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, परंतु इस संबंध में कार्रवाई नही की गई जिसके लिए केवल सरकार पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता।
डॉ.. अशोक सेठ, अध्यक्ष फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट

समवर्ती सत्र

प्रवासी संगठनों की बैठक

पीढियों का जुडना

इस सत्र का आयोजन विभिन्न प्रवासी संगठनों और सदस्यों को अपनी चिंताएं और आशाएं साझा करने के लिए एक मंच पर लाने हेतु किया गया था।

चित्र

श्री टी.पी. श्रीनिवासन, आईएफएस(सेवानिवृत), सत्र के संचालक ने संक्षेप में प्रवासी संगठनों की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होने कहा कि प्रवासी संगठन न केवल प्रवासियों के हितों को बढावा देते हैं अपितु अपने स्वंय के कल्याण हेतु स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं की स्थापना भी करते हैं। उन्होने उल्लेख किया कि क्षेत्रीय, भाषाई और राजनैतिक विचारों के आधार पर प्रवासी संगठन बनाए जाने लगे हैं।

श्री श्रीनिवासन ने इस सत्र के महत्व को एक ऐसे मंच के तौर पर रेखांकित किया, जिसमें प्रवासी संगठनों के सुदृढीकरण के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया जा सकता है, ऐसे तौर तरीकों की स्थापना पर विचार-विमर्श किया जा सकता है जहां संगठनों और भारत सरकार के बीच निरंतर आदान-प्रदान किया जा सके और प्रवासियों की चिंताओं से जुडे हुए ऐसे मुद्दों पर चचा्र की जा सके, जिनपर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किए जाने की आवश्यकता हैं।

इस सत्र के ऐनेलिस्ट(पेनल में शामिल लोग) ने निम्नलिखित मुद्दों और चिंताओं पर विचार-विमर्श किया:

श्री अशूक रामाशरण, अध्यक्ष, जीओपीआईओ, यू.एस ने कान्सूलर सेवाएं, संपति अधिकारों जैसे मुद्दों क समाधान करने के लिए भारतीय प्रवासियों और भारत सरकार की सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। उन्होने विभिन्न देशों में भारतीय प्रवासियों के अद्यतन ऑकडों/सॉख्यिकी के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव किया। उन्होने मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए भारत सरकार के साथ अर्थपूर्ण संवाद का भी सुझाव दिया।

डॉ.टो मेरी उत्तमा एस.सेमी वेल्लू ,भारत और दक्षिण एशिया में अवसंरचना के लिए विशेष दूत, प्रधानमंत्री विभाग, मलेशिया सरकार ने उल्लोख किया कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपनी छाप छोड रहा है। भारतीय प्रवासियों द्वारा बहुत से अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है, अत: उन्हे भारतीय उद्योग और भारत सरकार के साथ सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। उन्होने भारतीय प्रवासियों के बच्चों को प्राथमिकता प्रदान किए जाने पर बल दिया।

लार्ड दिलजीत सिंह राणा, सदस्य, हाउस ऑफ लार्डस, यूके ने युवाओं को प्रोत्साहित करने, ज्ञान शेयरिंग अर्थात नवाचारी विचारों के अर्थों में पीआईओ/एनआरआई की भूमिका को रेखांकित किया।

उन्होने प्रवासी भारतीय दिवस के परिणामों की समीक्षा करने और ऐसे कार्यक्रमों से प्रोदभूत होने वाल भविष्य के कदमों/कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उन्होने भारतीय प्रवासियों के साथ संपर्क स्थापित करने, भारतीय प्रवासियों की डॉ.यरेक्टरी का अनुरक्षण करने तथा भारतीय प्रवासियों को आपस में जोडनें के लिए वैश्विक स्तर के सम्मेलन का आयोजन करने हेतु एक वेबसाइट प्रारंभ करने का सुझाव दिया।

श्री नवल बजाज, अध्यक्ष, इंडो-चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, ने भारतीय युवाओं और प्रवासी युवाओं के बीच निंरतर आदान-प्रदान पर बल दिया, जिससे लाभकारी भागीदारी हो सकती है। उन्होने भारतीय प्रवासियों के लिए आउटरीच कार्यक्रम तैयार करने का भी सुझाव दिया ताकि उन्हे भारतीय संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने में सहायता की जा सकें।

उन्होने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर अपने संगठन के ट्रेड मिशन योजना संबंधी प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया कि प्रवासी संगठनों के साथ कार्य करने और मुद्दों का समाधान करने के लिए सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर करने पर ध्यान देना चाहिए।

एडवोकेट वाई.ए. रहीम, अध्यक्ष, भारतीय संघ शारजंहा ने अपने संगठन की उपलब्धियों जैसे स्कूलों की स्थापना, भारतीय प्रवासियों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए अंशदान का उल्लेख किया।

श्री के. कुमार, संयोजक, भारतीय प्रवासी समुदाय कल्याण समिति, ने भी अपने संगठन की उपलब्धियों जैसे जरूरतमंद बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान, भारतीय प्रवासियों को वित्तीय और चिकितसा सहायता प्रदान करने, जेल में कैदियों के मामलों का निपटारा इत्यादि का उल्लेाख किया। उन्होने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से खाडी देशों में भारतीय प्रवासियों के मुद्दों पर गहन ध्यान देने का अनुरोध किया।

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र एक मंच के तौर पर सत्र की महत्ता प्रवासी संगठनों के सुदृढीकरण के तौर-तरीकों तथा इन संगठनों और भारत सरकार	चित्र हम भारतीय प्रवासियों के बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉ.टो मेरी उत्तमा	चित्र हमें विभिन्न देशों में भारतीय प्रवासियों के अद्यतन ऑकडों/सॉख्यिकी	चित्र हमें भारतीय प्रवासियों के साथ संपर्क स्थापित करने, भारतीय प्रवासियों की डॉ.यरेक्टरी का	चित्र हमें भारतीय प्रवासियों के लिए आउटरीच कार्यक्रम तैयार करने चाहिए ताकि वे भारतीय संस्कृति के बारे में

के बीच निरंतर आदान-प्रदान के तौर-तरीकों की स्थापना करने पर विचार-विमर्श करने में है - श्री टी.पी. श्रीनिवासन, आईएफएस (सेवानिवृत)पूर्व राजदूत	एस.सेमी वेल्लू ,भारत और दक्षिण एशिया में अवसंरचना हेतु विशेष राजदूत, प्रधानमंत्री विभाग, मलेशिया सरकार	को अद्यतन करना चाहिए। श्री अशूक रामाशरण, अध्यक्ष, जीओपीआईओ, यू.एस	अनुरक्षण करने तथा भारतीय प्रवासियों को आपस में जोडनें के लिए वैश्विक स्तर के सम्मेलन का आयोजन करने हेतु एक वेबसाइट रखनी चाहिए। - लार्ड दिलजीत सिंह राणा, सदस्य, हाउस ऑफ लार्डस, यूके	अधिक जान सकें। - श्री नवल बजाज, अध्यक्ष, इंडो-चैंबर्स ऑफ कॉमर्स

श्री महयेंद्र उतधान, ने भारतीय प्रवासियों के लिए उठाए गए सकारात्मक कदमों जैसे दूरदर्शन का प्रसारण, और युवा प्रवासी भारतीयों के लिए उत्कृष्टता और महत्व केंद्रों की स्थापना की प्रशंसा की। उन्होने कुछ उपायों का भी सुझाव दिया, जिन्हे शामिल किया जाना चाहिए जैसे, सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना, जीआईओटीवी, पीआईओ कार्ड जारी किया जाना, भारतीय प्रवासियों के लिए सोशल नेटवर्किंग और वीजा ऑन अराईवल।

उन्होने अपने इस सुझाव के साथ सत्र का समापन किया कि भारत सरकार को विश्व श्रम अथवा करारनामें संबंधी सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना के लिए आगे आना चाहिए।

भारत को मीडिया और मनोरंजन उद्योग का हब बनाया जाना

मीडिया और मनोरंजन पहले ही एक साधन के तौर पर कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा भारत अपने प्रवासियों के साथ जुडॉ. हुआ है। प्रश्न यह है: हम भारत को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग का हब कैसे बना सकते हैं।

चित्र

संचालक श्री विक्रम चंद्रा, निदेशक एवं सीईओ, एनडीटीवी पेनलिस्ट: डॉ.. कमल हसन, फिल्म निर्माता, प्रोडयूसर, अभिनेता, निदेशक, राजकमल फिल्म इंटरनेशनल, श्री रमेश सिप्पी, फिल्म प्रोडयूसर एवं निदेशक, सुश्री अनुराधा प्रसाद, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बी.ए.जी. फिल्म एडं मीडिया लिमिटेड, श्री मुनीष गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध संपादक, पीआईओटीवी प्राइवेट लिमिटेड।

श्री विक्रम चंद्रा

मीडिया और मनोरंजन पहले ही एक ऐसे साधन के तौर पर कार्य कर रहा है, जिसके माध्यम से भारत माता अपने बच्चों के साथ जुडी हुई है। प्रश्न यह है हम भारत को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन उद्योग का हब कैसे बना सकते हैं।

डॉ.. कमल हसन

आज भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग संभावित विकास के शीर्ष पर है, हालांकि इसमे थोडॉ. विलंब हुआ हैं। तथापि, अभी भी हमें अपनी क्षमता का दोहन करने के अर्थों में बहुत आगे जाना हैं।

श्री रमेश सिप्पी

मोबाइल उद्योग दुनिया के किसी भी देश की अपेक्षा भारत में सबसे तेजी से बढा है, अमेरिका से भी ज्यादा तेजी से बढा हे। आधुनिक प्रौद्योगिकी इसी प्रकार कार्य करती है इसी प्रकार भारत में मीडिया और मनोरंजन उद्योग का विकास हो रहा है और हम दुनिया की बराबरी कर रहें है। हमारे उत्पादों के उपभोक्ता दुनिया भर में फैले हुए हैं। यदि हम गुणवत्तापरक सामग्री तैयार करते है, तो लोग इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ बेहतर तरीके से अपना कार्य करना हैं।

सुश्री अनुराधा प्रसाद

भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग एक ऐसी शक्ति है जिसे अभी उन्मुक्त किया गया हैं। इस भारी-भरकम उद्योग का विस्तार न केवल देश और भारतीय प्रवासियों के लिए हुआ है अपितु पूरी दुनिया में

इसका विस्तार हुआ है। अभिसरण के युग में भारतीय युवा पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

श्री मुनीष गुप्ता

मैंने भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से प्रवासी मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की तरफ अपने कदम बढाए थे। परंतु दो दशकों में, भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में इतने क्रांतिकारी बदलाव हुए है कि इसने मुझे वापस आकर इस उद्योग में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

जब हम विश्व राजनीति और विश्व अर्थव्यवस्था की बात करते है, तो भारत एक बडे देश के तौर पर सामने आता है- हमें भारतीय मीडिया मनोरंजन क्ेात्र की संस्थाओं को भी वही स्थान दिलवाना है, बॉलीवुड ने पहले ही इस दिशा में प्रवासी भारतीयों के सहयोग से भारतीय भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जाना चाहिए ताकि विश्व बाजार में एक बडी संस्था बन सके। इस संबंध में, प्रवासी भारतीय दिवस ने अपने विचार-विमर्श में भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग को शामिल करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

फिल्म

श्री विक्रम चंद्रा

भारतीय फिल्मों को विदेशों में बडी सफलता के तौर पर देखा जा रहा हैं। धूम-3 ने विदेशों में 150 करोड रुपये से अधिक का कारोबार किया है, आप क्या सोचते है कि यह किस तरह बढ रहा है।

डॉ.. कमल हसन

इस उद्योग के लोग इस बात से सहमत होने कि यह तो केवल एक शुरूआत भर है।

भारत 1 बिलियन से अधिक लोगों का देश है और औसत टिकट का मूल्य 150 रुपये है। हमारी जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखते हुए और कितने लोग भारत में फिल्में देखते हैं, हमारा लक्ष्य 1 बिलियन रुपये के कारोबार का होना चाहिए।

ऐसा करने के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि हम टिकट बिक्री इत्यादि में पारदर्शिता रखेंगे, तो हम 1 बिलियन रुपये के कारोबार के सपने को पूरा कर सकते है। और मुझे आशा है कि ऐसा मेरे अभिनय काल में ही देखने को मिलेगा। टिकटों की दरें राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित नही होनी चाहिए -इससे हमारी फिल्मों के बेहतर मुद्रीकरण में सहायता मिलेगी।

श्री रमेश सिप्पी

मुझे आशा है कि ऐसा 2020 तक होगा कई वर्षों पूर्व जब शोले फिल्म बनाई गई थी, तो इसने बाजार का केवल 15-20 प्रतिशत ही कारोबार किया। धूम-3 ने 50 प्रतिशत कारोबार किया हैं। यह समय के साथ बढता जाएगा।

इसके अतिरिकत, विदेशी फिल्म निर्माता जानते है कि भारत में ऐसी कहानियां हैं जो दुनिया को सुनाई जा सकती हैं। स्लमडॉग मिलियोनेयर का उदाहरण हमारे सामने है।

<u>सुश्री अनुराधा प्रसाद</u>

युवा फिल्म निर्माता आज के दौर में ऐसी फिल्में बना रहे है, जो न केवल भारत में लोकप्रिय होती हैा अपितु पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करती हैं। भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अगला कदम अंग्रेजी भाषा में फिल्में बनाना होगा। जो शेष दुनिया तक पहुॅच बनाने के लिए एक संपर्क भाषा के तौर पर प्रयोग की जा सकती है।

भारत में पर्याप्त प्रतिभा है, बस हमें आगे बढने के लिए सरकार के समर्थन की आवश्यकता है, मै उस दिन का उत्सुकता से इंतजार कर रही हूं जब दुनिया फिल्मों के बारे में सोचे तो बॉलीवुड का स्थान हॉलीवुड से उॅचा हों।

<u>श्री मुनीष गुप्ता</u>

वह दिन अब अधिक दूर नहीं है। बॉलीवुड की फिल्में अपने राजस्व का 50 प्रतिशत भारत से कमाती है और शेष 50 प्रतिशत अन्य देशों से अर्जित करती हैं। जबकि हॉलीवुड की फिल्मों के कुल राजस्व का 35 प्रतिशत उन अंग्रेजी भाषी देशों से अर्जित किया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर है।

परंतु ऐसा करने के लिए प्रतिभाओं का पोषण करने वाले स्कूलों की आवश्यकता है। फिल्म और टीवी उत्पादों के लिए अवसंरचना क्षेत्र में काफी अधिक निवेश किए जाने की आवश्यकता है

सरकार को भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग की सहायता करनी चाहिए ताकि यह भारत में अन्य उद्योगों के समकक्ष खडॉ. हो सके।

टेलीविजन

<u>श्री विक्रम चंद्रा</u>

टीवी उद्योग (विशेष तौर पर न्यूज) वर्तमान में बहुत बुरी दशा में है। इसके लिए बिजनेस मॉडल सही कार्य नही कर रहे हैं। अन्य देशों के विपरीत जहां दर्शकों से प्राप्त लाभ प्रसारक और वितरक के बीच बॉटा जाता है, भारत में ज्यादातर धनराशि केबल आपरेटर्स ले जाते हैं और इसके अतिरिक्त विरतण हेतु कैरिज शुल्क की भी मांग करते हैं। टीवी क्षेत्र राजस्व के लिए पूरी तरह से विज्ञापन पर आधारित है और विज्ञापन रेटिंग प्रणाली के अनुसार मिलता है, जो निष्क्रिय और अविश्वसनीय हैं।

इसके अतिरिक्त, विशेष तौर पर टीवी न्यूज की सामग्री भी अपेक्षा के बिलकुल आसपास नहीं हैं।

सुश्री अनुराधा प्रसाद

सरकार अभी तक उद्योग के लिए इतनी सहायक नहीं रही है जितना इसे होना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, उद्योग के लिए अन्य संघारणीय राजस्व मॉडल की खोज और विकास किया जाना संभव नही हुआ है।

भारत के समक्ष दूसरी समस्या यह है कि इतना बडॉ. राष्ट्र होने के बावजूद हमारे पास बीबीसी, सीएनएन और अलजजीरा की तरह एकल वैश्विक टीवी ब्रांड नहीं है। यदि दुनिया के किसी एक भाग में कुछ उल्लेखनीय घटित होता है, तो भारतीय न्यूज चैनल इसे कवर करने के लिए वहां नही होते हैं। हमारी विरल उपस्थिति होती है परंतु समग्र तौर पर नहीं। हमें भारत से समग्र वैश्विक ब्रांड की आवश्यकता है।

श्री रमेश सिप्पी

सोशल मीडिया हमें अधिकारों, स्वतंत्रता और दुनिया के बारे में अधिक जागरूक कर रहा हैं। टीवी उद्योग के भविष्य के बारे में सोचते समय हमें इस नए मीडिया अभिसरण के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा।

श्री मुनीष गुप्ता

इस उद्योग में कई तरह की समस्याएं हैं। कई चैनलों के लिए सामग्री में विशिष्टता नहीं है और कई क्षेत्रों में अतिलंघन हैं।

ऐसा महसूस होने का दूसरा कारण कि टीवी क्षेत्र अच्छा नहीं कर रहा है, विदेशी कॉरपोरेट हैं - जिन्होने भारत में प्रवेश तो कर लिया परंतु उद्योग के अभी राजस्व प्राप्त करना प्रारंभ नही किया है

पेनल की सिफारिशें

- विषय-वस्तु हल्का होने के मुद्दें का समाधान किया जाना चाहिए तथा विशिष्ट और अच्छी विषय-वस्तु को बढावा दिया जाना चाहिए।
- कोई प्रसारणकर्ता जितनी बेहतर विषय-वस्तु प्रोड्यूस करना चाहता है उतने ही अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। इसलिए, वैकल्पिक राजस्व माडल विशेष तौर पर न्यूज के लिए, का विकास किया जाना चाहिए।
- रेटिंग प्रणालयों को संशोधित और अद्यतन किया जाना चाहिए।
- अभिसरण पारितंत्र का लाभ उठाया जाना चाहिए, विशेष तौर पर चूंकि सोशल मीडिया में अधिक संख्या में युवा दर्शकों के साथ संपर्क स्थापित करने की क्षमता है।
- ब्रॉडबैंड/डिजिटल कनेक्ट में मीडिया एवं मनोरंजन पारितंत्र को पूरी तरह बदलने की ताकत हैं। यह आवश्यक है कि सरकार को देश भर में 100 प्रतिशत डिजिटिलिकरण के मुद्दें को आगे बढाना चाहिए।

समवर्ती सत्र-5

खाडी देशों में आप्रवासी भारतीयों के मुद्दें

खाडी देशों में आप्रवासी भारतीयों की चुनौतियां

पेनलिस्ट ने खाडी क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों के लिए गहन मॉनीटरिंग और विनियामक प्रणाली, उपयुक्त परामर्श प्रक्रिया तथा भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता सहित कई चुनौतियों की पहचान की।

चित्र

श्री ई. अहमद, विदेश राज्यमंत्री ने खाडी देशों में आप्रवासी भारतीयों के मुद्दें सत्र की शुरूआत यह रेखांकित करते हुए की कि गत कई वर्षों में भारत ने खाडी देशों के साथ गहरे संबंध विकसित कर लिए हैं और अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, रक्षा तथा कई अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक भागीदारी विकसित की है। उन्होने कहा कि खाडी देशों में भारतीय पसंदीदा प्रवासी है क्योंकि उनका स्वभाव कानून को मानने वाला और तकनीकी दक्षता वाला हैं। श्री अहमद ने इस बात पर बल दिया कि खाडी क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों के लिए गहन मॉनीटरिंग और विनियामक प्रणाली, उपयुक्त परामर्श प्रक्रिया तथा भर्ती प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। उन्होने स्वीकार किया कि हम सही दिशा में आगे बढ रहे है, परंतु खाडी देशों में भारतीय प्रवासियों के लिए काफी कुछ किया जाना शेष है। इस में भारतीय प्रवासियों के लिए काफी कुछ किया जाना शेष है। इस सत्र में जीसीसी देशों में भारतीय राजदूजों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था।

श्री के.सी. जोसफ, ग्रामीण विकास, योजना, संस्कृति मंत्री और नोरका, केरल ने इस बात का उल्लेख करते हुए कि विदेशों से प्रेषित की जाने वाली धनराशि केरल की जीडीपी का 20 प्रतिशत से अधिक है, प्रवासियों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होने उल्ल्ोख किया कि केरल सरकार द्वारा खाडी क्षेत्र में अप्रवासियों के हितो की सुरक्षा के लिए उनके भारत वापस लौटनें पर पुनर्वास कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने सहित प्रारंभ की गई कई विशिष्ट और महत्वपूर्ण पहले प्रारंभ की गई हैं।

श्री एम.ए. युसूफ अली, प्रबंध निदेशक, ईएमई के ग्रुप एवं उपाध्यक्ष, नोरका रूटस ने इस बात को रेखांकित किया कि सत्र में 75,000 करोड रुपये से अधिक धनराशि प्रेषित करने वाले अप्रवासियों, जो 7 मिलियन से अधिक हैं, के मुद्दों को शामिल किया गया हैं। उन्होने खाडी देशों में रहने वाले अप्रवासियों के महत्व और भारत के चहुँमुखी विकास में उनकी भूमिका को स्वीकार किया।

डॉ.. बी. रवि पिल्लई, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आरपी ग्रुप ऑफ कंपनी ने सउदी अरब में कार्य कर रहे भारतीयों के समक्ष आने वाले नियक्वेट मुद्दों का प्रभावी समाधान करने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया। उन्होने खाडी देशों में रहने वाले भारतीयों के मुद्दों का समाधान करने के लिए कई तरीकों का सुझाव दिया, उदाहरण के लिए, अप्रवासियों को प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं में तेजी लाना तथा खाडी क्षेत्र के लिए अधिक संख्या में उडॉ.ने प्रारंभ किया जाना।

श्री वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री भी सत्र के दौरान उपस्थित थे।

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र
भारतीय लोग अपने कानून को मानने वाले स्वभाव और तकनीकी दक्षता के कारण खाडी देशों में सबसे पसंदीदा प्रवासी हैं।
- श्री ई. अहमद, विदेश राज्यमंत्री

चित्र
हम उन मुद्दों पर चर्चा कर रहे है जिनमें 7 मिलियन अप्रवासी भारतीय शामिल है और जो 75,000 करोड रुपये से अधिक धनराशि स्वदेश भेजते हैं।
- श्री एम.ए. युसूफ अली, प्रबंध निदेशक, ईएमई के ग्रुप एवं उपाध्यक्ष, नोरका रूटस, केरल

चित्र
केरल सरकार द्वारा खाडी क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों के हितों के संरक्षण हेतु उनके भारत वापस लौटनें पर पुनर्वास कार्यक्रम सहित कई पहलें प्रारंभ की गई हैं।
- श्री के.सी. जोसफ, ग्रामीण विकास, योजना, संस्कृति मंत्री और नोरका रूटस, केरल

इस सत्र में निम्नलिखित मुद्दें को उठाया गया और उन पर चर्चा की गई:

- अप्रवासी भारतीयों के लिए मतदान का अधिकार
- भारत और खाडी क्षेत्र के बीच बहुत कम संख्या मे एयर इंडिया की उडॉ.नें
- विदेश धन प्रेषित किए जाने पर कर छूट
- अप्रवासी भारतीयों के लिए विधिक सेवाएं
- अप्रवासी भारतीयों के लिए भारतीय समुदाय कल्याण निधि
- गरीब अप्रवासी भारतीयों के लिए पेंशन योजनाएं
- विदेशों में भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की संख्या बढाए जाने की आवश्यकता
- अप्रवासी भारतीयों के मृत शरीरों को भेजा जाना
- जेल भेजे गए अप्रवासी भारतीयों की समस्याएं

पेनलिस्ट ने यह आश्वासन दिया कि भारत सरकार ने उक्त मुद्दों का समाधान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी हैं। उदाहरण के लिए, सरकार ने अप्रवासी भारतीयों को मत सूची में नामांकित कर लिया है और वे यदि चुनाव के समय भारत में मौजूद हैं तो अपना वोट डॉ.ल सकते हैं। उन्होने स्वीकार किया कि भारत और खाडी क्ेात्र के बीच उडॉ.नों की संख्या कम है और सेवाओं में सुधार का प्रयास किया जा रहा हैं। उन्हाने विश्वास दिलाया कि भारतीय समुदाय कल्याण निधि का उपयोग पूरी तरह से अप्रवासी भारतीयों के कल्याण हेतु किया जा रहा हे। ओमान में भारतीय राजदूत ने कहा कि उन्होने लगभग 80 प्रतिशत निधियां संवितरित कर दी हैं। बहरीन में भारतीय राजदूत ने कहा कि वे जेलों में बंद भारतीयों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

श्री वायलार रवि ने आश्वासन दिया कि वे उठाए गए मुद्दों को देखेंगे और उनका यथाशीघ्र समाधान करने का प्रयास करेंगे।

भारत के अगले स्वर्णिम युग के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है।

चित्र

प्रवासी भारतीय दिवस 2014 के विदाई सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शिक्षा इस बात का निर्धारण करेगी कि भारत कितनी शीघ्रता से अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होता हैं।

बारहवां प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय प्रवासियों का वार्षिक सम्मेलन, के विदाई सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा कि, "मेरा विश्वास है कि शिक्षा वह खुबियां है जो भारत के लिए अगला स्वर्णिम युग ला सकती है।"

उन्होने कहा कि, " हमारे लोगों को शिक्षित करने में हम जितनी सफलता प्राप्त करेंगे, उसी से यह निर्धारण होगा कि भारत कितनी शीघ्रता से अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होता हैं।

राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि यदि भारत को 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की विकास दर हासिल करनी है, जैसकि 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अभिकल्पना की गई है, तो "हमें इसके अनुकूल कारक लागू करने होगें और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है - शिक्षा।"

उन्होने कहा कि 1930 में सी.वी रमण द्वारा नोबल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद भारत से किसी भारतीय ने यह पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है और कहा कि देश के शिक्षा संस्थाओं को अनुसंधान और विकास पर अधिक फोकस करना चाहिए।

राष्ट्रपति ने कहा, "मै हमारे शिक्षा संस्थाओं से अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करने तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग स्थापित करते हुए दुनिया भर के श्रेष्ठ संकाय को हमारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के लिए आमंत्रित कर अधिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का आग्रह करता हूं।"

उन्होने कहा कि सरकार ने उच्चतर शिक्षा को प्राथमिकता दी है और अधिक संसाधनों से इसकी सहायता की है तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में नामांकन वर्ष 2006-07 में 1.39 करोड से बढकर 2011-12 में 2.18 करोड हो गया हैं।

राष्ट्रपति श्री मुखर्जी ने कहा, "गत 9 वर्षों से सरकार ने उच्चतर शिक्षा को प्राथमिकता दी है तथा अधिक संसाधनों के माध्यम से इसकी सहायता की है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में नामांकन वर्ष 2006-07 में 1.39 करोड से बढकर 2011-12 में 2.18 करोड तक पहुॅच गया हैं। भारत में आज 659 डिग्री प्रदान करने वाली संस्थाएं और 33,023 कॉलेज हैं। एक ऐसी दुनिया जहां प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिबंध बढते जा रहे हो, नवाचार भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा।"

श्री मुखर्जी ने कहा कि हालांकि, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद भारत में विश्वस्तरीय संस्थाएं बहुत कम हैं।

उन्होने कहा कि, "अब समय आ गया है कि हम उच्चतर शिक्षा के संबंध में विश्व में अपना अग्रणी स्थान पुन: प्राप्त करें। हमारें 'सख्या' बढाने के प्रयास 'गुणवता' बढाने के प्रयासों के समानुपात में होने चाहिए।

चित्र

श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के विदाई सत्र के दौरान धन्यवाद-प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए

उन्होने कहा कि एक ऐसी दुनिया जहां प्राकृतिक संसाधनें पर अत्याधिक प्रतिबंध बढते जा रहे हो, वहां भारत को नवाचार पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

उन्होने कहा, "चीन और अमेरिका नवाचार के मोर्चे पर अग्रणी राष्ट्र है और वर्ष 2011 में दोनो देशों द्वारा अलग-अलग पॉच लाख से भी अधिक पेटेंट आवेदन पेश किए गए।"

" इसके विपरीत भारत ने केवल 42,000 पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किए जो इन देशों से बहुत पीछे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, केवल तीन भारतीय कंपनियां विश्व की 100 सबसे अधिक नवाचारी कंपनियों की सूची में शामिल हैं।"

उन्होने उद्योग और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं दोनों से ही अनुसंधान और विकास में केवल 119 अनुसंधानकर्ता है जबकि चीन में 715 और अमेरिका में 468 हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में कुल 71,000 विद्यार्थियों में से केवल 4,000 पीएच.डी. विद्यार्थी हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कुल 60,000 विद्यार्थियों में से केवल 3,000 पीएच.डी. विद्यार्थी हैं।

उन्होने यह कहते हुए कि भारत में उच्चतर शिक्षा के मानकों को अत्याधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए कहा कि: "इस स्थिति का समाधान करने की दिशा में आप जैसे प्रवासी भारतीय जो यहां एकत्रित हुए हैं, सरकार के प्रयासों को पूरा करने और उनमें सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

राष्ट्रपति इस बात को नोट करते हुए प्रसन्न थे कि इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस में चर्चा के दौरान नवाचार और प्रौद्योगिकी के संबंध में एक सत्र शामिल किया गया। राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक वर्ष नवाचारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। उन्होने कलाकारों और लेखकों सहित प्रतिभाशाली युवा नवाचारकों को आमंत्रित करते हुए राष्ट्रपति भवन में रहने का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि नवाचारी विचारों को आगे बढाया जा सके तथा उन्हे मेंटरिंग और सहायता प्रदान की जा सके।

उन्होने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के ज्यादातर अन्य देशों की अपेक्षा अधिक लचीली हैं।

उन्होने कहा, " मुझे पक्का विश्वास है आपको हमारे लोगों की वंशानुगत समुत्थानशक्ति तथा हमारी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता, जो अस्थायी उतार चढाव से उभरने की क्षमता रखती है, में भरोसा हे।"

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस एक ऐसा अवसर है जब भारत सरकार और भारतीय लोग भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों का नवीनीकरण और सुद्दढीकरण करते हैं। यह भारतीयों के लिए देश में और देश के बाहर रहने वाले लोगों के बीच आपसी हितों के संबंधों को आगे बढाने का अवसर है।

उन्होने इस वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को बधाई दी। “उन्होने अपने निवास स्थान वाले देशों में अपनी पहचान बनाई है और उन अपने निवास स्थान वाले देशों में अपनी पहचान बनाई है और उन समुदायों के कल्याण को आगे बढ़ाया है, जिनके बीच वे रहते हैं और कार्य करते हैं।

उन्होने कहा, “भारतीय प्रवासियों ने, मेजबान देशों मे अपने योगदान और सफलता के माध्यम से, निरंतर अपने पूर्वजों की भूमि को सम्मान दिलाया है। यह सभी भारतीयों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि प्रवासी भारतीय समुदाय का सम्मान इसकी कार्य संस्कृति, अनुशासन और स्थानीय समुदायों के साथ सफल मेल-मिलाप के लिए किया जाता हैं।”

राष्ट्रपति ने उन 13 अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए, जिन्होने सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट योगदान दिया हैं।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता इस प्रकार थे:

सुश्री सीनेटर भीसा सिंह, लोक सेवा, ऑस्ट्रेलिया

श्री कुरियन वर्गीस, कारोबार, बहरीन

श्री वासुदेव चंचलानी, कारोबार एवं लोकसेवा, कनाडॉ. रामकृष्णा मिशन, फ़िजी, सामुदायिक सेवा, फ़िजी

श्री विकास चंद्र सांवल, शिक्षा और संस्कृति, फ़्रांस

श्री सतनारायण सिंह रविन बलदेव सिंह, लोकसेवा, नीदरलैंड

श्री सशिन्द्रन मुथुवेल, लोकसेवा, पापुआ न्यू गिनी

श्री शिशबुड्डीन वावा कुंजू, सामुदायिक सेवा, सऊदी अरब श्रीमती ईला गांधी, लोकसेवा, दक्षिण अफ्रीका

डॉ. शमशीर वायलिल परमबद्ध - स्वास्थ्य देख-रेख कारोबार

श्री शैलेश लखमन वारा, लोकसेवा, यूके, यूएई

सुश्री रेणू खातोर, शिक्षा, यूएई

उन्होने आशा व्यक्त की कि प्रवासी भारतीय दिवस “हमारे आपसी लाभ के सम्बन्धों को गहरा बनाने” में कई पहलों को प्रारम्भ करेगा।

उन्होने कहा, “सरकार अपनी तरफ प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ सक्रिय भागीदारी को जारी रखेगी तथा एक सुदृढ़ और समृद्ध भारत बनाने में उनकी बहुमूल्य भागीदारी के सभी अवसरों का पता लगाएगी।

सुश्री ईला गांधी, महात्मा गांधी कि परपोत्री ने एक्सेपटेंस स्पीच दी जबकि धन्यवाद प्रस्ताव श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया, जिन्होने अध्यक्ष श्री प्रेम नारायण, पुरस्कार विजेताओं, प्रतिनिधिमंडलों और फिक्की का धन्यवाद किया जिन्होने इस प्रवासी भारतीय दिवस को सफल बनाया और अगले वर्ष पुन: मिलने कि आशा व्यक्त की ।

पुरस्कार

चित्र

<u>सुश्री सीनेटर लीसा मारिया सिंह</u>

सुश्री सीनेटर लीसा मारिया सिंह ऑस्ट्रेलिया संसद के लिए चुनी जाने वाली प्रथम दक्षिण एशियाई मूल की महिला सदस्य हैं। राजनीति में आने के बाद से उन्होने विभिन्न मंत्रालयों में कार्य किया है। वे वर्तमान में तस्मानिया की सीनेटर हैं। वे ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक और भाषाई तौर पर विविध समुदायों विशेष तौर पर भारतीय और फ़िजी समुदायों की समर्थक रही हैं और ऐसी सरकारी नीतियों को आगे बढ़ाया है जो उनकी आवश्यकताओ को पूरा करती हैं। उन्होने भारत में परियोजनाओ सहित ऑस्ट्रेलियाई प्रवासी सहायता कार्यक्रम के विस्तार का समर्थन किया है तथा स्वास्थ्य और कर्मकारों के अधिकारों के मुद्दों पर भारतीय गैर-सरकारी संगठनो के साथ कार्य किया हैं।

सुश्री सीनेटर लीसा सिंह को उनके और भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच सम्बन्धों को आगे बढ़ाने में लोकसेवा में असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है।

<u>श्री कुरियन वर्गीस</u>

श्री कुरियन वर्गीस, बहरीन में एक प्रख्यात प्रवासी भारतीय कारोबारी हैं। उनकी खाड़ी देशों और भारत में निर्माण, अतिशय-सरकार, स्वास्थ्य देख-रेख, शिक्षा इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई कंपनियाँ हैं। उन्होने बेघरों को अपने घरों निर्माण और शादियों करने के लिए दिए गए दान सहित बहरीन और भारत में विभिन्न धर्मार्थ सस्थाओं को करोड़ों रुपये दान किए हैं। वे आईएनकेईएल(इन्फ्रास्ट्रक्चर केरल लिमिटेड) के निदेशक और मुख्य शेयरधारी हैं।

श्री कुरियन वर्गीस को भारत की छवि सुधारने तथा विदेशों में भारत के बारे में बेहतर समझ पैदा करने के लिए कारोबार के क्षेत्र मे उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

<u>श्री वासुदेव चंचलानी</u>

श्री वासुदेव एक उद्यमी और लोकोपकारक हैं, जो कनाडॉ. में रहते हैं। उनकी पहले शिक्षा, अनुसंधान और प्रत्यापक लोक नीति निर्माण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में होती हैं। वे कनाडॉ. के भारत केन्द्रित नीतिगत बदलावों के समर्थन में अग्रणी मोर्चों पर रहे हैं।

श्री वासुदेव चंचलानी को कारोबार और लोकसेवा के क्षेत्र में योगदान और भारत एवं कनाडॉ. के बीच सम्बन्धों को आगे बढ़ाने तथा भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रोत्साहन संबंधी प्रयासों के लिए जाना जाता हैं।

<u>रामाकृष्णा मिशन</u>

रामाकृष्णा मिशन 1937 से फ़िजी में समुदायों की सेवा कर रहा है तथा शिक्षा और धर्मार्थ कार्यकलापों में शामिल रहा हैं।

प्राकृतिक आपदाओं के समय उनके राहत और पुनर्वास कार्य सभी जानते हैं। मिशन के कार्यों ने माननीय मूल्यों और सौहार्द, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने में योगदान दिया हैं।

रामाकृष्णा मिशन, फ़िजी को समुदाय सेवा और लोकोपकार कार्यकलापों तथा विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया।

श्री विकास चंद्र सान्थाल

श्री विकास चंद्र सान्थाल फ्रांस के प्रतिष्ठित शिक्षाविद है। उच्चतर शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असाधारण रिकॉर्ड है। उन्होने यूएसए, यूके और युनेस्को में विभिन्न संस्थाओं में कार्य किया है। उन्होने दुनिया भर के 77 देशों में उच्चतर शिक्षा प्रबंधन की समस्याओं के संबद्ध में परामर्शदाता की क्षमता से कार्य किया है/अनुसंधान किया है।

श्री विकास चंद्र सान्थाल को शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान तथा भारत की छवि को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया।

श्री सतनारायण सिंह रविन बलदेव सिंह

श्री सतनारायण सिंह रविन बलदेव सिंह सूरीनाम में हालैंड की पूर्व कॉलोनी में कार्य करने वाले भारतीय कर्मकार के परपौत्र हैं। वे हालैंड की राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होने हेग में बहुसंस्कृतिवाद और बहू-जातीयता को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और नीदरलैंड में भूमिका निभाई हैं। वे 2008 से हेग के डिप्टी-मेयर हैं। उन्होने हिंदुस्तानी सूरीनामी भाषा में एक उपन्यास भी लिखा हैं।

श्री सतनारायण सिंह रविन बलदेव सिंह को लोकसेवा क्षेत्र तथा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गहरे संबंध विकसित करने के योगदान के लिए जाना जाता हैं।

श्री सशिन्द्रन मुथुवेल

श्री सशिन्द्रन मुथुवेल, लोकसेवा, पापुआ न्यू गिनी की संसद में पहुचने वाले भारतीय मूल के पहले सदस्य हैं। उनका स्पष्ट राजनीतिक विजन यह सुनिश्चित करना है कि धन को सभी में बराबर बांटा जाए तथा उनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित और स्वास्थ्यकारी पेयजल, निशुल्क और उपयुक्त शिक्षा मिले तथा ग्रामीण जनसंख्या को कौशलयुक्त बनाया जाए और इस प्रकार सभी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। उन्होने वर्ष 2000 में मैसर्स हेमामास ट्रेडिंग लिमिटेड नामक प्रख्यात ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की।

श्री सशिन्द्रन मुथुवेल को लोकसेवा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

श्री शिशबुड्डीन वावा कुंजू

श्री शिशबुड्डीन वावा कुंजू गत कई वर्षों से सऊदी अरब किंग्डम में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।

सामुदायिक सेवा, उनके द्वारा श्रम विवादों के निपटान में, बीमार और नि:शक्तजनों के लिए शरण की व्यवस्था करने निराश्रित भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश भेजने और मृत्यु के मामलों की देख-रेख में किए गए बहुमूल्य और निस्वार्थ कार्यों की भारत और विदेशों में सराहना की गई हैं और उनके कार्यों को मान्यता प्रदान करते हुए कई संगठनों द्वारा उन्हे सम्मानित किया गया हैं।

श्री शिशबुड्डीन वावा कुंजू को समुदाय सेवा के क्षेत्र में किए कार्यों तथा भारत और किंगडम ऑफ सऊदी अरब के बीच सम्बन्धों को आगे बढ़ाने के लीये सम्मानित किया गया।

सुश्री ईला गांधी

सुश्री ईला गांधी, महात्मा गांधी की परपोत्री हैं। वे दक्षिण अफ्रीका में सार्वजनिक जीवन में बहुत सक्रिय रही हैं। वे वर्ष 1994-2004 तक दक्षिण अफ्रीका संसद की सदस्य रही हैं और महत्वपूर्ण संसदीय कार्यों में शामिल रही हैं। वे कई न्यासों और समितियों की अध्यक्ष रही है, जो विभिन्न सार्वजनिक कार्यों को पूरा करती हैं। उन्होने दक्षिण अफ्रीका की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं और वर्ष 1943 में उन्हें पाँच वर्ष तक हाउस अरेस्ट रख गया। उन्होने गांधीजी की दो पुस्तकों का प्रकाशन किया हैं।

सुश्री ईला गांधी को लोकसेवा के क्षेत्र में उनके योगदान भारतीय छवि को सुधारने तथा दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच सम्बन्धों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया।

डॉ. शमशीर वायलिल परमबद्ध

डॉ. शमशीर वायलिल परमबद्ध ने समुदाय के कल्याण और सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों को पूरा करते हुए एक सफल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हैं। उन्होने संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और भारत में संचालन सहित एक समेकित हेल्थ-केयर ग्रुप प्रारम्भ किया और मानवीय तथा सामाजिक परियोजनाओं में सक्रिय तौर पर भाग लिया हैं, जिससे मध्य-पूर्व, भारत एवं उत्तरी अफ्रीका के समुदायों को लाभ हुआ हैं।

डॉ. शमशीर वायलिल परमबद्ध को स्वास्थ्य देख-रेख कारोबार में उनके योगदान तथा संयुक्त अरब अमीरात में भारत की बेहतर छवि को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता हैं।

श्री शैलेश लखमन वारा

श्री शैलेश लखमन वारा मूल रूप से इंग्लैंड एंड वेल्स के उच्चतम न्यायालय में एक सॉलिसीटर हैं। वे पहली बार ब्रिटिश संसद के लिए 2010 में चुने गए और कंजरवेटिव पार्टी की सरकार में पहले भारतीय मूल के मंत्री बने। उन्होने यूनाइटेड किंग्डम के पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमंत्रियों तथा कंजरवेटिव पार्टी के नेताओं के सलाहकार के तौर पर भी कार्य किया हैं।

श्री शैलेश लखमन वारा को सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों और भारत तथा यूके के लोगों के बीच सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया।

श्री पार्थसारथी चिरामेल पिल्लई

श्री पार्थसारथी चिरामेल पिल्लई को अकादमिक और सरकारी दोनों ही क्षेत्र में शिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान में 34 वर्ष का अनुभव हैं और उन्होने 75 शोध पत्रों एवं सारांशों को प्रकाशन किया हैं। उन्होने संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनैतिक शेक्षिक कार्यकलापों को मुख्य धारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होने हाऊस ऑफ रिप्रिसेंटेटिवस एंड सिनेटर्स के साथ लाबिंग करने सहित अपने सभी हलफनामों/सहभागिताओं के माध्यम से भारत-अमेरिकी सम्बन्धों को आगे बढ़ाया हैं।

श्री पार्थसारथी चिरामेल पिल्लई को विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान तथा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सम्बन्धों को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता हैं।

सुश्री रेणू खातोर

सुश्री रेणू खातोर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयो के बीच एक अग्रणी नेता के तौर पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वे भारतीय मूल के पहली महिला थी, जिन्होंने अमेरिका की उच्चतर शिक्षा प्रणाली और अनुसंधान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। उन्होने भारत के हितों तथा भारत-अमेरिकी दोस्ती और सहयोग को आगे बढ़ाया हैं। उच्चतर शिक्षा में एक नेता के तौर पर उन्होने अमेरिका में अध्ययनरत हजारों भारतीय विद्यार्थियों के कल्याण म्मेन अपना योगदान दिया है और भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। वे प्रधानमंत्री वैश्विक प्रवासी भारतीय सलाहकार परिषद की सदस्य हैं।

सुश्री रेणू खातोर को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया हैं।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
भारत सरकार

युवा

बारहवां

प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी संबंधता : पीढियों का जुडना

7-9 जनवरी, 2014, नई दिल्ली

चित्र

युवाओं के जोश के उत्सव का आयोजन

प्रवासी भारतीय दिवस 2014 में युवाओं की चिंताओं और आकांक्षाओं को समझने और सहक्रियाएं स्थापित करते हुए उनकी ऊर्जा का उपयोग भारत के विकास में करने और राष्ट्रों के समुदाय में इसे उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए किए जाने का प्रयास किया गया।

चित्र

प्रवासी युवाओं और भारतीय युवाओं के बीच मजबूत सम्बन्धों के विकास का आहवान करते हुए श्री वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसे जुड़ाव से पूंजी और रोजगार पैदा होंगे और इससे अंतत: व्यापक तौर पर लोगों का भला होगा।

उन्होने व्यापार, उद्योग, उद्यमशीलता और सामाजिक कार्यो में प्रवासी युवाओं और भारतीय युवाओं के बीच मंत्री ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किए गए 'युवा प्रवासी भारतीय दिवस', 2014 नामक प्री-प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कह "हमारा लक्ष्य इस प्रयोजनार्थ मजबूत वैश्विक संबंध विकसित करना होना चाहिए।" इस कार्यक्रम का समन्वय और प्रबंधन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा किया गया।

मंत्री ने कहा कि, "प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय विभिन्न देशों में रह रहे युवा प्रवासियों के साथ विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं जैसे 'भारत को जानों' कार्यक्रम (केआईपी), 'स्टडी इंडिया कार्यक्रम' (एसआईपी) तथा प्रवासी भारतीयों के बच्चों के लिए छात्रवृति कार्यक्रमों को लागू करते हुए युवाओं के साथ सहभागिता करने में अग्रणी रहा है। इन कार्यक्रमों और योजनाओं से प्रवासी युवाओं के साथ-साथ अपने मातृभूमि देश में विकास को आगे बढाने में भी लाभ मिला है। इन कार्यक्रमों को समद्ध करना और विस्तारित करने का हमारा प्रयास होना चाहिए ताकि हमारे युवा प्रवासी लाभान्वित होते रहें और हमारी मातृभूमि के साथ जुडे रहें।"

इस अवसर पर श्री रवि ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक था - 'रिएलाइजिंग द ड्रीम ऑफ ए प्रोग्रेसिव एंड इनकलुसिव इंडिया - ए यूथ प्रेसपेक्टिव।' फिक्की द्वारा तैयार उस रिपोर्ट में उन तीन विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिनमें युवा प्रवासी मास के साथ सहयोग कर रहे है। इसमें भारतीय श्रम बाजार में हो रहे परिवर्तनों के तौर-तरीकों का उल्लेख किया गया है, उन युवाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है जो उद्यमिता को एक वहनीय करियर विकल्प के तौर पर देखते है तथा देश में समावेशी विकास का माहौल बनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के गठन में भारतीय युवाओं और प्रवासी युवाओं के बीच सहभागिता के तरीकों की पडताल की गई है।

श्री जितेंद्र सिंह, युवक कार्यक्रम और खेल एवं रक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने अपने संबोधन में यह घोषणा की कि भारत एक नई राष्ट्रीय युवा नीति लागू करने जा रहा है, जिसमें युवाओं को अपनी क्षमता का पूरा दोहन करने के लिए सशक्त करने का प्रावधान किया गया हैं।

उन्होने कहा कि नई नीति का फोकस युवाओं को उचित शिक्षा और कौशल प्रदान करके और उद्यमशीलता को बढावा देकर उन्हे एक उत्पादक कार्यबल के तौर पर विकसित करने पर है। इसके अतिरिक्त, उन्होने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल और स्वस्थ जीवन पद्धति और खेलों को बढावा देकर, सामाजिक मूल्यों के साथ प्रभावी सहभागिता तथा शासन प्रक्रिया में उनकी सदभागिता बढाकर तथा लाभवंचित वर्गो के युवाओं एवं विशेष आवश्यकताओं वाले युवाओं का ध्यान रखने के लिए समावेशी नीतियों के माध्यम से एक सुदृढ और स्वस्थ पीढी का विकास करना हैं।

श्री सिंह ने कहा, "नई राष्ट्रीय युवा नीति के माध्यम से भारत सरकार का आशय 'सामाजिक उद्यमशीलता' को बढावा देना है, यह एक आकर्षक रोजगार संभावना है, जो उपक्रम की निधियों की स्थापना करने और सामाजिक उद्यमशीलता के लिए अपेक्षित बहुमूल्य निवेश प्रदान करने हेतु एक समर्थकारी नीति बनानी है। इससे प्रवासी भारतीयों को भारत में सामाजिक उपक्रमों की स्थापना करने की सुविधा मिलेगी।"

इस संदर्भ में, उन्होने कहा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन(एनवाईकेएस) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), उनके मंत्रालय द्वारा गठित दो अखिल भारतीय उपस्थिति वाले युवा स्वैच्छिक नेटवर्कस, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जबकि एन वाई के एस में ग्रामीण भारत में लगभग 2.80 लाख युवाओं के क्लबों के माध्यम से 8 मिलियन गैर-विद्यार्थी युवा स्वंय सेवकों को नामांकित किया गया है एवं एनएसएस में देशभर के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेजों के लगभग 3.25 मिलियन विद्यार्थी स्वंयसेवक शामिल हैं। ये नेटवर्कस सामाजिक मूल्यों और सामूदायिक सेवा की भावना को बढावा देते हैं।

उन्होने स्वीकार किया कि रेजिडेंट और नॉन-रेजिडेंट इंडियन युवा एक ऐसा संघारणीय विकास मॉडल तैयार करने के लिए सहभागिता कायम करने पर कार्य कर रहे हैं, जो सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकें। इसके अतिरिक्त श्री सिंह ने कहा कि भारतीय श्रम बाजार शिक्षा और कौशल पर फोकस करते हुए अपने आपको बदल रहा है। उन्होने प्रवास प्रवृतियों में विपरीत परिस्थितियों का भी उल्लेख किया, जो बाजार में उपलब्ध अनुभव और विशेषज्ञता को बढावा दे रहा हैं।

इसके अतिरिक्त, उन्होने कहा कि भारतीय युवाओं की एक वहनीय करियर विकल्प के तौर पर उद्यमशीलता में रूचि बढ रही है और काफी संख्या में अनुभवी प्रवासी भारतीय अपना कारोबार स्थापित करने के लिए स्वदेश वापस लौट रहे है, यह एक उपयुक्त आधार है जो नवाचारी मॉडलों पर आधारित है और व्यापक सामाजिक पदचिंहों के साथ इनकी स्थापना की जा रही हैं।

उन्होने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) युवा भारतीयों को युवा प्रवासी भारतीयों में साथ लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की स्थापना करने का एक अवसर प्रदान करता है, ताकि यह सुनिश्चित

किया जा सके कि विकास परिभाषित अर्थव्यवस्था की सीमाओं को लांघते हुए देश के लाखों लाभ-वंचित लोगों तक उन्नत सामाजिक पैरामीटरों के तौर पर पहुॅच सके।

श्री प्रेम नारायण, सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय शीघ्र ही एक नेट-आधारित परियोजना प्रारंभ करेगा जो उत्प्रवास को एक आसान, पारदर्शी, सुव्यवस्थित और मानवीय प्रक्रिया में परिवर्तित करेगी। प्रस्तावित ई-प्रवास परियोजना प्रवासी कर्मकारों के लिए सुविधा की गुणवता में उल्ल्ोखनीय सुधार करेगी क्योंकि यह उत्प्रवास चक्र में निहित विभिन्न प्रक्रियाओं को सुकर बनाएगी और प्रभावशीलता को बढाएंगी।"

उन्होने कहा कि विदेश जाने वाले भारतीय कर्मकारों के हितों के संरक्षण हेतु विभिन्न देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों पर भी कार्य किया जा रहा हैं।

उन्होने कहा कि काफी संख्या में भारतीय युवा प्रवासियों को भारत मे निवेश और व्यापार के अवसरों के लिए नए स्थलों के विकास हेतु एक दूसरे के साथ सहभागिता और संबंध स्थापित करने के अवसर प्राप्त कर रहें, इसके आलोक में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का महत्व अधिक बढ जाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री राजीव गुप्ता, सचिव, युवक कार्यक्रम विभाग युवक कार्यक्रम, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय युवाओं को अपने समकक्ष प्रवासियों के साथ मुलाकात करने और संवाद स्थापित करने का एक मजबूत मंच प्रदान करने में प्रवासी भारतीय दिवस के महत्व पर बल दिया।

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र

प्रस्तावित ई-प्रवास योजना उत्प्रवास प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी, सुव्यवस्थित और मानवीय प्रक्रिया में परिवर्तित करेगी। यह उत्प्रवासी कर्मकारों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवताओं में महत्वपूर्ण सुधार करेगी
श्री प्रेम नारायण, सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

चित्र

प्रवासी भारतीय दिवस युवाओं के लिए अप्रवासी युवाओं के साथ संबंध स्थापित करने और लाभ न कमाने वाली संस्थाओं की स्थापना करने का एक अवसर प्रदान करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास परिभाषित अर्थव्यवस्था की सीमाओं को लांघते हुए देश के लाखों लाभ-वंचित लोगों तक उन्नत सामाजिक पैरामीटरों के तौर पर पहुॅच सके।
श्री जितेंद्र सिंह, युवक कार्यक्रम और खेल एवं

चित्र

हमारा लक्ष्य इस प्रयोजनार्थ युवाओं का एक सुदृढ वैश्विक संपर्क स्थापित करना होना चाहिए1
भारतीय युवाओं को व्यापार, उद्योग, उद्यमशीलता और सामाजिक कार्य में एक सुदृढ नेटवर्क विकसित करना चाहिए।

श्री वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री

चित्र

प्रवासी भारतीय दिवस युवाओं को प्रवासी समकक्षों के साथ मुलाकात करने और संवाद स्थापित करने का अवसर देने का एक बडॉ. मंच हैं।

श्री राजीव गुप्ता, सचिव, युवक कार्यक्रम विभाग युवक कार्यक्रम, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)और
रक्षा राज्यमंत्री

मुख्य घोषणाएं

- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय वर्ष 2014 में ई-प्रवास परियोजना प्रारंभ करेगा।
- युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश के युवाओं को अपनी क्षमता का पूर्ण दोहन करने का अवसर प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय युवा नीति विकसित करने के संबंध में कार्य कर रहा हैं।
- आगे का रास्ता: प्रवासी भारतीय दिवस की योजना इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए ताकि भारतीय युवाओं को प्रवासी युवाओं के साथ सहभागिता करने और 'लाभ-न-कमाने' वाली संस्थाओं का विकास करने का अवसर प्रदान कर सके और इसका परिणाम समग्र सामाजिक उत्थान के तौर पर हैं।

युवाओं के सपने और आकांक्षाएं

भारत अपनी आर्थिक समृद्धि की यात्रा में अपने समृद्ध प्रवासियों को शामिल करके काफी कुछ प्राप्त कर सकता है। परंतु उनकी विशिष्ट चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझने के लिए सहक्रियाएं स्थापित की जानी चाहिए।

चित्र

डॉ. रेणू खातोर, अमेरिका के टेक्सास राज्य में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय की प्रथम महिला चांसलर और अध्यक्ष, ने प्रवासी युवाओं की आकांक्षाओं के संबंध में पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि, "हमारी सफलता हमारे सपनों और आकांक्षाओं का उत्पाद है।"

उन्होने उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद, जहां उनका जन्म ओर पालन-पोषण हुआ, से अमेरिका जाने के बाद अपने संर्घष को श्रोताओं के साथ साझा करते हुए अमेरिका में व्यापक अनुसंधान विश्वविद्यालय की अध्यक्ष प्रथम प्रवासी महिला ने कहा, "आपके जीवन का एक सपना होना चाहिए, चाहे आपके स्वयं के बारे में हो, आपके परिवार के बारे में हो अथवा आपके देश के बारे में हो, तभी आप सफल हो सकते हो।

ह्यूस्टन प्रणाली के विश्वविद्यालय की चांसलर के तौर पर डॉ. खातोर एक ऐसे संगठन की देख-रेख करती है जो 60,000 से भी अधिक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसका बजट 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है और प्रत्येक वर्ष ग्रेटर ह्यूस्टन क्षेत्र पर 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक आर्थिक प्रभाव डलता है।

डॉ. खातोर ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 18 वर्ष की आयु में एक भारतीय अमेरिकी से शादी की। जब वह अमेरिका पहुँची तो उन्होने न केवल अंग्रेजी भाषा के कारण आने वाली समस्याओं पर काबू पाया अपितु पुरदूई विश्वविद्यालयसे राजनैतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर और पीएच.डी. की डिग्री भी प्राप्त की। वह वैश्विक पर्यावरणीय नीति के क्षेत्र में एक प्रख्यात विद्वान है और इस विषय पर उन्होने असंख्य पुस्तकों और लेखों का प्रकाशन किया हैं।

डॉ. खातोर ने अपने प्ररेणादायी भाषण में कहा कि, "जीवन हममे से ज्यादातर के साथ न्याय नहीं करता, प्रत्येक की परीक्षा लेता हैं, परंतु नेता बनना इस बात पर निर्भर है कि वे

अपनी विफलताओं को किस रूप में लेते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप परिस्थितियों का शिकार बनते है अथवा दुनिया को बदलते हैं। आपकी भावना आपको विपरीत परिस्थितियों में जीने का सहारा देती है। लोगों को साथ लीजिए, विनम्र बने रहे और उन लोगों की सहायता को स्वीकार कीजिए जो आपकी यात्रा में आपके साथ रहे हैं। यह आपके पांव जमीन पर रखेगा।"

डॉ. चारू वालीखन्ना, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने भाषण में युवा भारतीय लडकियों विशेष तौर पर पंजाब, गुजरात और केरल की उन लडकियों की आकांक्षओं की चर्चा की, जिन्होने विदेश में बेहतर जीवन की चाह में अप्रवासी भारतीयों से विवाह किया, परंतु उनके साथ धोखा हुआ और उन्हे यातनाएं सहनी पडी हैं। उन्होने अप्रवासी महिलाओं/भारतीय लडकियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए कुछ हैरान कर देने वाले मामलों का उल्लेख किया। उन्होने कहा कि प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग ने विदेशों में धोखाबाजी और जालसाजी वाले विवाह के मामलों के लिए एक एनआरआई प्रकोष्ठ का गठन किया हैं। उन्होने भारतीय प्रवासियों से अपने बच्चों को उन भारतीय लडकियों से विवाह करने के लिए मजबूरन करने का आग्रह किया जिनके साथ उनके सपने और महत्वकाक्षाएं मेल नहीं खाती है। डॉ. वालीखन्ना ने कहा, "हमें केवल सफल और कडी मेहनत करने वालों के तौर पर उदाहरण प्रस्तुत नहीं करने है अपितु अपने साथी मनुष्यों के प्रति सम्मान और सच्ची निष्ठा दर्शाकर भी उदाहरण प्रस्तुत करना है।"

नीतिगत सुझाव

- अप्रवासियों/ओसीआई लोगों की तुलना में पीआईओ के साथ किए जाने वाले भेदभाव का उचित समाधान किया जाना चाहिए।
- अन्य देशों में दूरदर्शन की डॉ.उनलिंकिंग समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।

सुश्री कीर्ति माताबादल, संयुक्त राष्ट्र में उच्च युवा प्रतिनिधि ने अपने भाषण में अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के बीच पहचान संकट का मुद्दा उठाया। उन्होने कहा कि भारत अपने समृद्ध प्रवासियों को शामिल करते हुए काफी कुछ हासिल कर सकता है।

सुश्री माताबादल ने इस बात पर बल दिया कि प्रवासी युवा भारत के साथ जुडना चाहता है। हालांकि वे विभिन्न देशों में पैदा हुए है और उनका पालन-पोषण भी वही हुआ है परंतु उनका दिल भारतीय है, उन्होने आगे कहा कि भारतीय मूल के लोगों को भ्रमित राष्ट्रीयता की समस्या का सामना करना पडता है क्योंकि नही तो जिस देश में वे रह रहे है, वह देश और न ही भारत उन्हे अपना नागरिक मानता हैं।

उन्होने कहा कि भारत और प्रवासी युवाओं के लिए एक दूसरे तक पहुॅच बनाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि विदेशों में बसे हुए भारतीय मूल के लोगों की आगामी पीढियों में सांस्कृतिक विरासत कायम रहें। "प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को भारतीय मूल के युवाओं के साथ अच्छे संबंध कायम करने चाहिए क्योंकि वे चाहे कही भी रहें, वे हमेशा महसूस करते है कि भारत उनका एक भाग है। प्रवासी युवाओं को जोडने के लिए अपेक्षित संसाधनों को जुटाया जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक नागरिक दुनिया को तेजी से बदल रहे हैं।"

उन्होने भेदभाव किए जाने संबंधी अपने स्वयं के अनुभवों को बताया जब उन्होने प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने के लिए भारतीय दूतावास में वीजा हेतु आवेदन किया। भारतीय मूल के लागों के समक्ष आ रहे मुद्दों को रेखांकित करते हुए सुश्री माताबादल ने कहा कि उन्हे भारत की यात्रा हेतु वीजा प्राप्त करने के लिए काफी प्रताडना का सामना करना पडता है और काफी कागजी खानापूर्ति करनी पडती हैं। उन्होने कहा, "इस वजह से वे भारत आने से बचते है। पीआईओ तथा एनआरआई के लिए वीजा नियमों को आसान बनाया जाना चाहिए और संभवत उन्हे भारतीय पासपोर्ट भी प्रदान किया जाए।"

इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि प्रवासियों को न केवल भारत के साथ जुडना चाहिए अपितु वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने बीच एक मजबूत नेटवर्क भी स्थापित करना चाहिए और अपने ज्ञान एवं अनुभव के माध्यम से भारत की प्रगति मे अपना योगदान देना चाहिए। उन्होने युवाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किए जाने की सिफारिश की।

श्री मनीष तिवारी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने प्रवासी युवाओं और भारत के युवाओं की आकांक्षाओं का उल्लेख किया। उन्होने कहा कि वैश्विक स्तर पर युवाओं को जोडने में सीमा नियंत्रण, वीजा विनियम और प्रवास औपचारिकताएं कुछ बाधाएं हैं परंतु इस बात से इंकार नही किया जा सकता कि इंटरनेट ने उन्हें वैश्विक विचार-विमर्श का एक भाग बना दिया है, इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बडॉ. गैर-अभिशासित क्षेत्र है और वर्ष 2000 में इसके प्रारंभ से ही हर दूसरे दिन इस पर और अधिक डॉ.टा उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होने कहा कि, "इस प्रौद्योगिकी ने एक आभासी सभ्यता को बढावा दिया है जो युवाओं को दुनिया में अपनी तरह की महत्वकांक्षा रखने वाले युवाओं के साथ जोडने का अवसर प्रदान करती हैं"

उन्होने कहा कि अपनी विदेश यात्राओं के दौरान उन्होने पाया कि युवा पीढी की आकांक्षाएं एक जैसी ही है - अपने जीवन को सवारना और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाना। पीबीडी में एक ऐसी अनौपचारिक संरचना तैयार की जानी चाहिए ताकि दुनिया भर के युवा निर्बाध तौर पर एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित कर सकें।

श्री तिवारी कहा कि प्रसार भारती ने प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोडे रखने के लिए दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल प्रारंभ किया है। उन्होने कहा कि कई देशों में इस संबंध में काफी प्रगति हुई है जिसे अन्य देशों में भी दोहराया जाएगा।

भागीदारों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे:

- भारत में भ्रष्टाचार घातक स्तर तक है, विशेष तौर पर निजी बैकिंग क्षेत्र में, काफी संख्या में अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को, जो अपनी कडी मेहनत से प्राप्त कमाई को भारत भेजते हैं, बेवकूफ बनाया जाता है।
- महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी इस अवसर पर उठाया गया।
- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने भारतीय संस्थाओं में पीआईओ/एनआरआईकेलिए योजनाएं लागू की हैं। हालांकि, पीआईओ औरएनआरआई के लिए शिक्षा, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, भारतीयों के समान फीस पर ही प्रदान की जानी चाहिए। योग्य अभ्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का कोटा होना चाहिए।
- प्रवासियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए दूरदर्शन का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र

दुनिया भर के युवा निर्बाध तौर पर एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस द्वारा गैर-ढांचागत तरीके से अनौपचारिक संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए।
-श्री मनीष तिवारी, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

चित्र

आपके मनोभाव आपको अत्यधिक परिस्थितियों मे भी जिंदा रखने मे सहायक हैं। लोगों को साथ लीजिए, विनम्र बने रहे और उन लोगों की सहायता को स्वीकार कीजिए जो आपकी यात्रा में आपके साथ रहे हैं।- डॉ. रेणू खातोर, चांसलर, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन सिस्टम और अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन

चित्र

हमें न केवल कठिन मेहनत करते हुए सफल होकर उदाहरण स्थापित करने है अपितु हमारे साथी मनुष्यों के प्रति सच्ची निष्ठा और सम्मान दर्शाते हुए भी मिशाल कायम करनी हैं। - डॉ. चारू वालीखन्ना, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग

चित्र

विदेशों में बसे हुए भारतीय मूल के लोगों की आगामी पीढियों में सांस्कृतिक विरासत कायम रखने के लिए भारत और युवा प्रवासियों के लिए एक-दूसरे तक पहुॅच बनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है ताकि रहें - सुश्री कीर्ति वेदिका माताबादल नीदरलैंड

समवर्ती सत्र - 1

एक ही विरासत होना: भावनात्मक जुडॉ.व

यह जुडॉ.व भावनात्मक है

एक ऐसे समय जब (नृ) जातीय दावे दिन प्रतिदिन तेजी से बढ रहे है, भारतीय प्रवासी भोजन, फिल्मों, व्यापार, धर्म, गांधीजी की विचारधारा और योग को एक दूसरे के साथ जुडने का एक साधन समझते हैं।

चित्र

युवा प्रवासी भारतीय दिवस के एक भाग के तौर पर "एक ही विरासत भावनात्मक जुड़ाव" सत्र का संचालन डॉ विद्या येरावाडेकर, प्रधान निदेशक, सिमबायोसिस सोसाइटी ने किया। इसमें विविध क्षेत्रों जैसे सिनेमा, राजनीति, मीडिया और कारोबार के वक्ताओं को शामिल किया गया था, येरावडेकर जिन्होने सिमबायोसिस के साथ जुडने से पूर्व मस्कट और ओमान में कार्य किया, ने विदेशों मे बसे हुए कई भारतीयों द्वारा महसूस की गई असुरक्षा की भावना पर चिंता व्यक्त की। डॉ येरावाडेकर ने कई प्रवासी अभिभावकों के समक्ष पैदा हुई दुविधा को व्यक्त करते हुए कहा, "क्या मेरे बच्चे जुड़े रह पाएंगें (भारत के साथ)?"

डॉ येरावाडेकर ने कहा, "विदेशों में कार्य कर रहे अथवा रह रहे ज़्यादातर भारतीय अपने बच्चों को भारतीय धार्मिक पुस्तकों में बताई गई ज्ञान की बातों की शिक्षा प्रदान करते हुए उनमें अपने मूल देश की संस्कृति और विरासत पैदा करने का हर संभव प्रयास करते हैं।" भावनात्मक जुड़ाव के मुद्दे पर अपने विचार रखते हुए उन्होने कहाँ ऐसा प्रयास भारतीय बच्चों में बढ़ती हुई सांस्कृतिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए किया जाता हैं।

डॉ येरावाडेकर ने सुझाव दिया कि भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए कार्यक्रम होने चाहिए।

उन्होने यह भी कहा कि भारतीय फिल्में न केवल प्रवासियों को प्रभावित कर रही हैं। उन्होने एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार एक विदेशी विद्यार्थी बालीवुड स्टार सलमान खान के सिमबायोसिस परिसर में छह माह तक "बोडीगार्ड" फिल्म की शूटिंग के कारण आवागमन के दौरान उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए लालायित था।

सिमबायोसिस की प्रधान निदेशक ने कहा कि प्रवासी युवाओं के लिए 4-6 सप्ताह का 'स्टडी इंडिया' का प्रयोग काफी सफल रहा क्योंकि इससे उन्हें भारतीय संस्कृति को अपने रहन-सहन में शामिल करने में सहायता मिलती है।

मेघना घई पुरी, अध्यक्ष, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल तथा बालीवुड डॉ.इरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन लेखक सुभाष घई की पुत्री ने इस विचार का समर्थन किया कि प्रवासियों के लिए सिनेमा सबसे बड़ा भावनात्मक जुड़ाव का साधन है।

उन्होने कहा, "भारत उपकर्मों और विशेष तौर पर मीडिया और मनोरंजन में समृद्ध हो रहा हैं " और यह भी कहा कि सिनेमा और टेलीविज़न प्रवासियों को भारत के साथ जोड़ें रखने में उत्कृ उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होने कहा कि प्रवासियों के लिए अभिसरण प्रदान करने में धार्मिक स्थलों का भी समान रूप से महत्व हैं।

प्रख्यात सुश्री पुरी ने कहा कि "कहानी सुनाने (तरीके को) के भारतीय तौर-तरीकों को बहुत पसंद किया जाता हैं। उनके अनुसार फिल्म प्रशिक्षण संस्थान में 15 प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी होते हैं तथा इनमें एक-तिहाई विदेशों में बसे हुए भारतीय होते हैं।

उन्होने कहा कि, "हमारा सिनेमा अपने रंगों, संस्कृति और कहानी को पेश करने के तरीके के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ता हैं..... भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ रही हैं। इस देश के लिए अच्छी शिक्षा और विशेष तौर पर मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अच्छी शिक्षा का निवेश सबसे महत्वपूर्ण हैं।"

सुभाष राज़दान, अमेरिका में गांधी प्रतिषठान के अध्यक्ष, ने भारत में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। उनका मानना था कि विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने हेतु निधियाँ भेजनी चाहिए और विकासशील दुनिया में पर्यायवरण और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए।

श्री राज़दान ने कहा कि प्रवासी युवा वैश्विक नागरिकता की तरफ अग्रसर हैं क्योंकि बेहतर क्नेक्टीविटी और सोशल मीडिया के कारण मतभेद समाप्त हो रहे हैं।

उन्होने भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा कि कमी, निधियों की कमी, महिलाओं संबंधी मुद्दों, टीकाकरण की कमी और अस्वच्छता जो भारत में हेल्थकेयर को प्रभावित कर रही है, और कुछ देशों में युवाओं को प्रभावित करने वाली प्रवास और जातीय भेदभाव की समस्याओं का उल्लेख किया।

उन्होने आग्रह किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु की सीमाओं के संबंध में सूचना और ज्ञान को तथा परिवारिक मूल्यों का सुदृढीकरण कर हम वैश्विक भागीदारी स्थापित करते हुए बदलाव ल सकते हैं।

पल्लवी अय्यर , इंडोनेशिया में द हिन्दू की पत्रकार, ने अपना ध्यान भारतीय मीडिया द्वारा दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन की कवरिंग करने में अनिच्छा के पीछे निहित कारणों पर केन्द्रित किया। उन्होने चीन, यूरोप, और इंडोनेशिया में भारतीय प्रवासियों पर अपनी बातें रखी। उन्होने उल्लेख किया कि चीन एक अपवाद है जहां भारतीयों कि उपस्थिती चिकित्सा और योग शिक्षा क्षेत्रों के अतिरिक्त तेजी से कम हो रही हैं। परंतु चीन और भारत में बढ़ते हुए आर्थिक सहयोग यह परवर्ती भविष्य में बादल जाएगी ।

उन्होने कहा, "आज एश्वर्य में हीरों के बाजार को भारतीय समुदाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लोगों को अपने निवास देश की संस्कृति को समहित करना सीखना होगा।"

श्री जगविंदर सिंह विर्क, अध्यक्ष, जीओआईपीआईओ और आस्ट्रैलिया में राजनेता ने भारतीय विद्यार्थियों के अपने निवास देश के खिलाफ जातिगत दुर्भावना के आरोपों का बचाव किया। डॉ. सिंह ने कहा कि भारत और आस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल क्रिकेट के लिए उत्साह है। डॉ. सिंह के उद्गम देश के साथ जुडॉ. हुआ महसूस करने के लिए धार्मिक स्थलों के निर्माण में हमेशा सहयोग दिया।

उन्होने कहा कि भारत और आस्ट्रेलिया के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी, सौर प्रौद्योगिकी, तटीय क्षेत्र विकास और कौशल विकस के क्षेत्रों में सहयोग स्थापित किया जा सकता है।

विषय विशेषज्ञों का विचार था कि भारतीय विश्वविद्यालय में 'भारत को जानो' और 'स्टडी इंडिया' कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाना ताकि प्रवासी विद्यार्थियों के भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो सकें।

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र	चित्र	चित्र	चित्र	चित्र
भारतीय फिल्में केवल भारतीय प्रवासियों को प्रभावित करती है अपितु एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अन्य लोगों को भी प्रभावित करती हें। डॉ विद्या येरावाडेकर,	चीन एक ऐसा अपवाद है, जहां भारतीयों की उपस्थिति चिकित्सा और योग शिक्षण के अतिरिक्त बहुत तेजी से कम हो रही है। भारत और चीन के	हमारा सिनेमा प्रवासियों को रंग,संस्कृति और कहानी सुनाने की शैली के माध्यम से जोडता है भारतीय फिल्मों का अपना स्वतंत्र कारोबार हैं।	परिवर्तन करो तथा भागीदारी करते हुए इसकी प्रतिबद्धता के साथ ही शिक्षा बाहयताओं, स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान	हम (भारतीय प्रवासी और भारत के लोग) कौशल विकस जल संसाधन और सौर उर्जा इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग कर सकतें हैं।

प्रधान निदेशक,
सिमबायोसिस

बीच बढती हुई
आर्थिक भागीदारी के
साथ ही इस संख्या
में
वृद्धि होने की
संभावना है।
सुश्री पल्लवी अय्यर ,
इंडोनेशिया पत्रकार ,
द हिन्दू

सुश्री मेघना घई
पूरी,
अध्यक्ष,विस्लिंग
वुड्स इंटरनेशनल

करने के सहित
परिवार के विकास
को सुदृढकरों।
श्री सुभाष
राज़दान, अध्यक्ष
गांधी प्रतिषठान
यूएसए

श्री जगविंदर सिंह
विर्क, अध्यक्ष,
जीओआईपीआईओ
और आस्ट्रैलिया

समवर्ती सत्र - 2

युवा एचीवर्स

पुनरूत्थानशील भारत के प्रभारी

भारतीयों की नई पीढी इस मायने में विशिष्ट है कि इसका एक ही दृष्टिकोण है - सफलता और उपलब्धि। समाज में बदलाव के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता हैं।

चित्र

श्री नवीन जिदंल, संसद सदस्य ने भारत की सफलता की कहानी में प्रवासी भारतीयों की भागीदारी को प्रभावी ढंग से स्वीकार किया। युवा एचीवर्स संबंधी सत्र के संचालक ने कहा कि अभी हाल ही के वर्षों में युवा भारतीयों ने अपने कार्य के संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनिय प्रगति की है। उन्होने कहा कि, "प्रत्येक पीढी की अपनी सुपरिभाषित योग्यताएं हैं। 21वीं सदी की पीढी का एक ही दृष्टिकोण हैं - सफलता और उपलब्धि।" इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि युवा प्रतिभा में जबरदस्त वृद्धि हुई है तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी उपलब्धियों में नाटकीय बढोतरी हुई हैं।

युवा प्रवासियों के समक्ष आने वाले विभिन्न मुद्दों को रेखांकित करते हुए उन्होने कहा कि युवाओं की सफलता के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया जाना आवश्यक है। युवा भारतीयों के कौशल में सुधार करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता सहित यह सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है कि उनके कौशल वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।

एक युवा नेता के तौर पर सुश्री सुप्रिया सूले, संसद सदस्य का मानना है कि भारत में युवाओं के दृष्टिकोण बदलाव आया है क्योंकि आज न केवल वह अपने बारे में चिंतित है अपितु व्यापक तौर पर समाज के कल्याण के लिए भी चिंतित है। उन्होने कहा कि कई विद्यार्थियों ने सामाजिक मुद्दों को उठाया है और अब भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

युवा सांसद ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस एक ऐसा मंच है जो भारत को अपनी उपलब्धियां दर्शाने का अवसर प्रदान करता है, परंतु देश अभी भी कई सामाजिक समस्याओं जैसे महिलाओं के मुद्दों से जूझ रहा है। उन्होने कहा कि, "आवश्यकता इस बात कि है भारत को एक निष्पक्ष और एक समान समाज बनाया जाना चाहिए।" इसके अतिरिक्त उन्होने कहा कि दहेज की बुराई आज भी देश के कई भागों में व्यापत है परंतु आज महिलाएं अपनी आवाज उठा रही है और ऐसे आदमी के साथ घर बसाना चाहती है जो उनके साथ बराबरी का व्यवहार करे। इस सत्र के दौरान उन्होने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को भी रेखांकित किया।

सुश्री सूले का मत था कि ऐसी सामाजिक चुनौतियों का समाधान केवल नीतिगत हस्ताक्षेपों द्वारा नहीं किया जा सकता अपितु व्यक्तिगत स्तर पर अवधारणा में बदलाव की आवश्यकता हैं।

श्री पी. राजीव, संसद सदस्य ने भारत की अर्थव्यवस्था में प्रवासियों द्वारा निभाई गई भूमिका को रेखांकित किया और सुझाव दिया कि इस मोर्चे पर भारत को काफी कुछ करने की आवश्यकता हैं। उन्होने कहा कि भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वदेश भेजे जानी वाली धनराशि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अधिक है परंतु अधिक धनराशि आकर्षित करने के लिए भारत में एक नीति की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रेषित की गई धनराशि का उपयोग निवेश प्रयोजनार्थ किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में नही हो रहा है। उन्होने कहा कि कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं अपने प्रवासियों के कारण विकसित हुई है, इसलिए भारत को भी इस कार्यक्रम को आगे बढाने के लिए विशिष्ट नीतियां बनानी चाहिए।

उन्होने निम्नलिखित पहलूओं को भी रेखांकित किया:-

1 खाडी क्षेत्र में 50 प्रतिशत प्रवासी महिलाएं हैं;
2 केरल में 10 प्रतिशत जनसंख्या विदेश जाने की इच्छुक है, जिनमें से 90 प्रतिशत खाडी देशों में जाते हैं;
3 केरल में, अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रेषित धनराशि राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी) का 31 प्रतिशत है;
4 केरल में एक तिहाई बैंक खाते अप्रवासी भारतीयों के हैं ;
5 केरल में 100 घरों में से 44 पर या तो अप्रवासी भारतीय है अथवा अप्रवासी भारतीयों के प्रतिधारक हैं;
6 अप्रवासी भारतीय द्वारा प्रेषित धनराशि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा आकर्षित की गई धनराशि से भी अधिक है;
7 भारत में विनिर्माण क्ष्ोत्र में आने वाले एक डॉ.लर में से 68 सेंट विदेश से आता है;

डॉ. ममता सिंघवी, प्रबंध निदेशक और पूर्व अध्यक्ष भारतीय मूल के चिकित्सकों का अमेरिकी संघ (एएपीआई), अमेरिका ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि किसी भी विरासत, इतिहास और पारिवारिक विकासको समझने से व्यक्ति में विश्वास पैदा होता हैं। डॉ. सिंघवी ने कहा कि अपने सिद्धांतों का समझौता नही करना चाहिए और यह कहा कि अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए वह एएपीआई की सबसे युवा अध्यक्ष बनीं।

डॉ. सिंघवी, जो सरवाईकल कैंसर को खत्म करने के मिशन पर कार्य कर रही हैं, ने कहा, "युवा लोगों में हमारे समाज की कई सबसे मुश्किल समस्याओं का समाधान करने

की सृजनशीलता और उर्जा है और वे पहले ही इस यात्रा पर चल पडे हैं।" उन्होने भारत में और अधिक तथा बेहतर टीकाकरण योजनाओं की आवश्यकता पर बल दिया और भारतीय प्रवासियों को इस संबंध में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया । उन्होने भारत में चिकित्सा पर्यटन की संभावनाका भी उल्ल्ेाख किया।

डॉ. रूबी ढल्ला, कनाडॉ.ई राजनेता, ने भारत के भाग्य निर्माण में प्रवासियों की अनंत संभावनाओं का उल्लेख किया

डॉ. ढल्ला ने कहा कि भारत में युवा और प्रतिभाशाली युवाओं का पूल है परंतु शिक्षा सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण वे देश के बाहर अवसर तलाश रहें हैं।

उन्होने कहा कि युवाओं को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि देश में अवसर उपलब्ध हैं, जिसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण हैं। उन्होने सुझाव दिया कि युवाओं में विश्वास बहाल करने के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम किए जाने चाहिए।

भारतीय बिजनेस समुदाय को युवा और उभरते हुए उद्यामियों के लिए मेंटरिंग के सभी विकल्पों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होने युवाओं द्वारा भारत में प्रारंभ किए गए बदलावों को भी रेखांकित किया। उन्होने कहा कि युवाओं को सफलता के लिए सही दृष्टिकोण, विश्वास और साहस को अपनाना चाहिए। इस बात पर बल देते हुए कि युवा भारतीय अर्थव्यवस्था की भविष्य की परिसंपति है, उन्होने नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करने का आहवान किया युवाओं का विश्वास बनाए रखा जाए और उसे प्रोत्साहित किया जाए।

श्री के.सी. वेणूगोपाल, नागर विमानन राज्य मंत्री ने दुनिया भर में अवसरों की तलाश में जाने वाले युवाओं के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

"एयर इंडिया प्रवासी भारतीयों की ऋणी है और आपको हमेशा उडॉ.न भरने का अवसर प्रदार करती है। राष्ट्रीय कैरियर ने बुरा दौर भी देखा है जब ऋणों के भार तले दबी थी। परंतु अब हम अपनी स्थिति में सुधार कर रहे हैं। हमें खुशी है कि बुकिंग में भी उपभोक्ताओं का बेहतर विश्वास परिलक्षित होता हैं"

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र	चित्र	चित्र	चित्र	चित्र	चित्र
प्रवासी भारतीयों ने भारत के सांस्थानिक विकास में अत्याधिक योगदान दिया है। श्री नवीन जिदंल, संसद सदस्य	भविष्य में पूंजी की बजाय विकास के लिए सूचना और शिक्षा महत्वपूर्ण कारक होगें। श्री के.सी. वेणूगोपाल, नागर विमानन राज्य मंत्री	भारत जटिल मुद्दों जैसे महिलाओं के साथ भेदभाव और घरेलू हिंसा में अभी भी काफी पीछे हैं सुश्री सुप्रिया सूले, संसद सदस्य	केरल में एक तिहाई बैंक खातो में अप्रवासी भारतीयों द्वारा जमा करवाया जाता हैं। केरल में 100 घरों में से 44 घरों में या तो अप्रवासी भारतीय है अथवा अप्रवासी भारतीयों द्वारा प्रेषित की जाने वाली धनराशि भारत द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश राशि से अधिक हैं। श्री पी. राजीव, सांसद	भारत में अधिक और बेहतर टीकाकरण योजनाओं की आवश्यकता है और भारतीय प्रवासियों से इस संबंध में सहयोग करने का आग्रह करती हुं। डॉ. ममता सिंघवी, प्रबंध निदेशक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ऑरिजन (एएपीआई), संयुक्त राज्य अमेरिका	नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करने चाहिए कि युवाओं के विश्वास को अनुरक्षित औा पोषित किया जाए, उनका स्वयं में और सेवाओं में विश्वास बहाली के उपाय करते हुए युवा भारतीय भविष्य की अर्थव्यवस्था में उन्हे परिसंपति के तौर पर विकसित किए जाने की आवश्यकता है। डॉ. रूबी ढल्ला, कनाडॉ.ई राजनेता

एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया समूह का कम लागत का कैरियर के कार्यानिष्पादन के बारे में कतिपय चिंताओं का समाधान करने की दिशा में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में उन्होने कहा: " एयर इंडिया एक्सप्रेस की अभिकल्पना विशेष तौर पर खाडी देशों में सेवाओं के लिए की गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस को एक स्वतंत्र कारोबारी संस्था के तौर पर सशक्त करने की प्रक्रिया प्रगतिशील है। हमने एयर इंडिया एक्सप्रेस को शिकायत मुक्त बनाने के लिए कई पहले की हैं। हमने खाडी क्षेत्र में अपनी सेवाओं को भी बढाया है और शीर्ष स्तर पर इसके कार्यनिष्पादनकी निगरानी की जा रही है ताकि उपयोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित की जा सकें। अप्रवासी भारतीयों से व्यक्तिगत तौर पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में चिंताओं की सुनवाई हूतु मैंने एक मेल सेवा भी प्रारंभ की है।"

श्री वेणूगोपाल ने कहा कि अप्रवासी भारतीयों की प्रत्येक पीढी के लिए विशिष्ट अवसर और चुनौतियां रही हैं। हालांकि, अप्रवासी भारतीयों की नई पीढी, विशेष तौर पर मध्य-पूर्व में रहने वाले अप्रवासियों, की सामाजिक-सांस्कृतिक समामेलन के अर्थों में अपेक्षाकृत कम समस्याए हैं।

उन्होने सुझाव दिया कि सरकार द्वारा नई आर्थिक नीतियों को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि न केवल प्रवासियों के साथ अधिक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली को बढावा मिले अपितु भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए अधिक अनुकूल निवेश योजनाएं भी बनाई जा सकें। उन्होने कहा कि भविष्य में विकास के लिए पूंजी की अपेक्षा सूचना और शिक्षा महत्वपूर्ण कारक होंगे।

मंत्री ने कहा कि अप्रवासियों की दूसरी पीढी पुनरूत्थानशील भारत की राजदूत है, जिसने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। महत्वकांक्षा, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रबंधन विशेषज्ञता सफल युवा भारतीय की मुख्य पहचान है उन्होने दुनिया भर में भारतीय कारोबार के पदचिंहों को आगे बढाया है। केरल में भी ऐसे कई युवा निवशक है जिन्होने छोटे शहरों के अपने मध्यवर्गीय घरों से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार हाटस्पॉटस तक का सफर तय किया हैं।

हालांकि, उन्होने कहा कि, " अप्रवासी भारतीयों की नई पीढी आकांक्ष स्तरों एवं दक्षताओं के मामले में अपने पूर्वजों से कई गुणा आगे हैं। भारत सरकार द्वारा उनके लिए अधिक कारगर और समर्थकारी नीतियां बनाई जानी चाहिए। यह सच है कि भारत में भी निवेशकों को प्रेरित करने के लिए नीतिगत पहलें की गई हैं। परंतु मेरा मानना है कि हमें अपने नेटवर्क का विस्तार करना होगा ताकि प्रवासी भारतीयों के लिए एक सरकारी छत्र की स्थापना की जा सके। ऐसे निकाय को प्रत्येक क्षेत्र में निवेश संभावना के संबंध में ऑकडे निकालने होगे ताकि विभिन्न सार्वजनिक-निजी भागीदार मॉडलों के लिए संभावित नकदी प्रवाह के हेतु सकझौता किया जा सके, अप्रवासी भारतीयों के लिए निवेश हेतु एकल खिडकी मंजूरी सुनिश्चित की जा सके।

देशों के बीच लंबे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सौदेबाजी ने युवा भारतीयों की वृहत स्वीकृति की जमीन तैयार कर दी है।

उन्होने अप्रवासी भारतीयों को अवसर प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री वेणूगोपाल ने कहा, "एक देश और जिम्मेदार सरकार के तौर पर हम युवा भारतीयों को कही भी समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वे विश्वास के साथ भारत में निवेश कर सकें। अब समय आ गया है कि हम अपनी स्वयं का इंजीनियरिंग अनुसंधान करें तथा उधार की प्रौद्योगिकीयों पर निर्भरता को अनुसंधान और विकास पर मुख्य ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कंपनियों द्वारा भी उद्योग और शिक्षा के बीच सामजस्य स्थापित करने की आवश्यकता हैं।

मुख्य सुझाव और सिफारिशें

- सेवाओं और सूचना तथा शिक्षा की समान सुलभता के साथ अधिक संख्या में लोगों को शामिल करने के लिए नेटवर्क का विस्तार किया जाना।

- अप्रवासी भारतीयों के लिए एकल खिडकी निवेश मंजूरी
- अनुसंधान और विकास, अनुसंधान और शिक्षा पर फोकस
- उद्योग और अकादमिक क्षेत्र के बीच सामजस्य
- गुणवत्ता सुधार एवं सेवाओं की वृद्धि के लिए श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाए जाने की आवश्यकता
- पूंजी के बजाय सूचना और शिक्षा पर फोकस
- खाडीक्षेत्र से एक अप्रवासी भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के समक्ष कहा कि खाडी क्षेत्र के लिए हवाई किरायों में कमी की जाए।

अन्य शामिल की गई महत्वपूर्ण चिंताएं:

- अप्रवासी भारतीय के लिए अनुपस्थिति मताधिकार
- ओसीआई कार्डों पर स्थानीय पता मुद्रित करवाना ताकि वे भारत में अधिक कारोबार अवसर प्राप्त कर सकें।
- एयर इंडिया की टिकटों विशेष तौर पर खाडी देशों में जाने वाली उडॉ.नों के टिकट मूल्यों को युक्ति संगत बनाया जाना

युवा प्रवासी भारतीय दिवस

समापन सत्र

उपयोगी अंर्तदृष्टि

भारत और इसके प्रवासियों के बीच सृजित सांमजस्य समावेशी समृद्धि के मुख्य सिद्धांत द्वारा निर्देशित होनी चाहिए और यह नवाचार एवं प्रौद्योगिकी आधारित होनी चाहिए। इस संदर्भ में युवाओं की उर्जा का लाभ उठाया जाना चाहिए।

चित्र

युवा प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर आयोजित विभिन्न सत्रों ने भारत के युवा राष्ट्र के तौर पर उभार के संबंध में उपयोगी अंर्तदृष्टि प्रदान की, जहां लगभग 50 प्रतिशत कार्यगत जनसंख्या 18-35 वर्ष आयु समूह में आती है, और इन सत्रों से प्रवासियों की चुनौतियों, मुद्दों तथा उभरती हुइ्र प्रवृत्तियों का निर्माण करने के लिए विचार-विमर्श का फोकस देश का समावेशी और बेहतर आर्थिक निर्माण करने के लिए युवा प्रवासियों के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए विभिन्न अवरोधों को दूर करने पर था।

श्री सचिन पायलट, कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भारत के आर्थिक और कारोबारी सम्बन्धों को शेष दुनिया के साथ और गहरा बनाने में आप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों की सराहना की । उन्होने विदेशों से भारत प्रेषित कि जाने वाली धनराशि को 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पहुचाने के लिए भारतीय प्रवासियों का आभार व्यक्त किया।

उन्होने कहा कि अमेरिका और दुनिया के अन्य भागों में प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या में उपस्थिती ने भारत को अमेरिका के साथ इस सौदे को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। जिनमें भारत के अमेरिका के साथ आर्थिक रिश्तों में पहले ही तेजी आ चुकी हैं और आने वाले वर्षों में रिश्ता और गहरा होगा।

अभी हाल ही के वर्षों में भारत के कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध कई गुणा बढ़े हैं और विशेष तौर पर उन देशों के साथ जहां भारतीय प्रवासी सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। श्री पायलट ने आग्रह किया कि प्रवासी भारतीयों को अपने मेजबान देश में “भारत और भारतीयता” को बढ़ावा देने के लिए अपना श्रेष्ठ योगदान देना चाहिए।

श्री अशोक तंवर, संसद सदस्य का मानना था कि सभी एनआरआई/पीआईओ को मताधिकार प्रदान किया जाना चाहिए और विशेष तौर पर उन लोगों को जो खाड़ी देशों में रह रहे हैं और उन्होने प्राधिकारियों ले दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा संसद ने अधिक मात्रा में धन

प्रेषित कर भारत की अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण में योगदान के लिए एनआरआई और पीआईओ लोगों का धन्यवाद किया, जिसने देश के मौजूदा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान की हैं।

श्री कंवलजीत सिंह बक्शी, संसद सदस्य, नेशनल पार्टी, न्यूजीलैंड ने कहा कि उन्होने वर्ष 2008 में इस सपने के साथ इस देश में प्रवास किया था एफ़डी भारतीय मूल का प्रथम सांसद बनकर संसद में न्यूजीलैंड के युवाओं का प्रतिनिधित्व करूंगा। उन्होने कहा कि न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की संख्या में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और हिन्दी अब न्यूजीलैंड में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा हैं। सर एडमंड हिलेरी, भारत में न्यूजीलैंड के पूर्व उच्चायुक्त ने भारत के साथ मजबूत संबंध करने की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है और अभी हाल ही मे उत्कृष्टता , चहुमुखी विकास और नेतृत्व को प्रेरित करने के लिए श्री राहुल गांधी को सर एडमंड हिलेरी अध्येतावृति प्रदान की गई हैं।

उन्होने कहा कि युवाओं के सपने बड़े होने चाहिए। भारतीय जनसंख्या कि मध्य आयु 2020 तक 29 वर्ष होने की संभावना हैं। युवा राष्ट्र की आशा हैं। श्री बक्शी ने कहा कि युवाओ की ऊर्जा का सही उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि न्यूजीलैंड मे युवाओं की ऊर्जा का दोहन करने में युवा निधि और युवा मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होने कहा, “उन्हें कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनके भविष्य के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना महत्वपूर्ण हैं।”

प्रवासी भारतीय दिवस, 2014 के आशुचित्र

चित्र

मैं यहाँ उपस्थित प्रवासी भारतीयों से अपने मेजबान देश में भारत और भारतीयता को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह करता हूँ।

- श्री सचिन पायलट, कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

चित्र

न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या में 48 प्रतिशत कि वृद्धि हुई है और हिन्दी न्यूजीलैंड में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा हैं।

श्री कंवलजीत सिंह बक्शी, संसद सदस्य, नेशनल पार्टी, न्यूजीलैंड

चित्र

सभी एनआरआई और पीआईओ तथा विशेष तौर खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मताधिकार प्रदान किया जाना चाहिए और उन्होने प्राधिकारियों से दोहरी नागरिकता प्रदान करने के मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया ।

श्री अशोक तंवर, सांसद

1. भारतीय विश्वविद्यालयों को अपने प्रवासी विद्यार्थियों के लिए ‘भारत को जानो’ और ‘स्टडी इंडिया’ कार्यक्रम प्रारंभ करने चाहिए ताकि देश के साथ उनके जुड़ाव को सुदृद किया जा सके।
2. भारतीय प्रवासियों को युवा स्वैच्छिक नेटवर्क्स जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ जूड़ने का प्रयास करना चाहिए ताकि भारतीय युवाओं तक पहुंच बनाई जा सके।
3. एक ऐसी योजना पर विचार किया जाना चाहिए जिसके तहत प्रवासी लोग भारत के गांवों में स्कूलों को गोद ले सकें।

4. भारत में चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं तथा सरकार और प्रवासियों को आपस में सांमजस्य स्थापित करते हुए इसे सफल बनाना चाहिए।
5. आयरिश और चीनी प्रवासियों की तरह, जो अपने घरेलू देश में विकास और नवाचार में मुख्य योगदान देने वाले लोग बन गए हैं, भारतीय प्रवासियों को भारत और इसके लोगों के विकास मे सहयोग करने मे अग्रणी बनना चाहिए।
6. प्रवासी भारतीय दिवस में एक अनौपचारिक और गैर-संरचनागत तरीके का विकास किया जाना चाहिए ताकि दुनिया भर के युवा निर्बाध तौर पर एक दूसरे के संपर्क में रह सकें।
7. एनआरआई/ओसीआई की तुलना में पीआईओ के खिलाफ भेदभाव का उपयुक्त समाधान किया जाना चाहिए।
8. अन्य देशों में दूरदर्शन इंटरनेशनल के डॉ.उनलिंकिंग समस्याओं के मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए।
9. ओसीआई कार्डों पर स्थानीय पता मुद्रित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भारत में रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें।
10. एयर इंडिया की टिकटों और विशेष तौर पर खाड़ी देशों में जाने वाली उड़ानों की टिकटों के मूल्य को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।
11. मलेशियाई मंत्री ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को मलेशिया में परिसर स्थापित करने और अधिक संख्या में भारतीय बैकों को शाखाएं खोलने के लिए आमंत्रित किया।
12. अन्य देशों के विभिन्न लोग चाहते थे कि फिक्की जैसा कारोबारी निकाय बेहतर कारोबारी संवाद स्थापित करने के लिए उनके देशों मे चैप्टर स्थापित करे।
13. पूंजीगत बाजार में एनआरआई की भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने कि आवश्यकता हैं।
14. भारत सरकार को विदेशी सरकारों के साथ वहाँ भारतीय फिल्मों के निर्बाध प्रदर्शन और रिलीज के संबंध में बातचीत करनी चाहिए।
15. भारत को 'एलर्ट' मंत्रालय बनाना चाहिए ताकि अर्हता प्राप्त बेरोजगार कार्यबल को रोजगार के संबंध में जानकारी मिल सके।
16. शरणार्थियों, आर्थिक शरणार्थियों विशेष तौर पर पंजाब के शरणार्थियों के मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए।
17. चूंकि राजदूत और विदेश सेवा के अधिकारी सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देते हैं, इसलिए भारत सरकार को विदेशी कार्यालयों में कर्मियों कि संख्या बढ़ानी चाहिए।
18. पीएमजीएसी में युवाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
19. भारतीय मिशनों का स्तरोन्नयन करने के उपाय किए जाने चाहिए क्योंकि वे भी देश कि सॉफ्ट पावर को बढाते हैं।
20. भारत सरकार को रोजगार भूमिकाओं में दक्षता के लिए कौशल विकास हेतु कदम उठाने चाहिए।
21. भारत सरकार को विभिन्न देशों में भारतीय प्रवासियों के आंकड़ों/सांख्यिकी की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
22. अन्य प्रवासी संगठनों के साथ कार्य करने और मुद्दों के समाधान में सहयोग हेतु सम्झौता ज्ञापन।

23. खाड़ी देशों मे भारतीय प्रवासियों के मुद्दों पर अत्यधिक ध्यान देना।
24. पीआईओ के लिए टीवी चैनल।
25. भारतीय प्रवासियों के लिए सोशल नेटवर्किंग।
26. वीजा-ऑन-अराइवल।
27. भारत सरकार को विश्व श्रम अथवा करारनामों के संबंध में सहयोगत्मक अनुसंधान परियोजना तैयार करनी चाहिए।

चित्र

तीन दिवसीय भारतीय प्रवासी दिवस में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया - अपनी प्रभावी स्टॉल लगाई। श्री वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और श्री जितेंद्र सिंह, युवक कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने इस प्रदर्शनी का उदघाटन किया। प्रवासी भारतीय दिवस 2014 कि प्रदर्शनी ने इस अर्थपूर्ण संवाद करने और प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों जैसे पर्यटन, आईटी मिशन, दस्तकारी तथा अन्य विभागों ने अपने स्टॉल लगाए तथा विभिन्न योजनाओं और निवेश अवसरों का उल्लेख किया।

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

चित्र

बारहवां प्रवासी भारतीय दिवस

7-9 जनवरी, 2014

कार्यकर्म : प्रथम दिन

10.15-11.00 बजे	युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उदघाटन सत्र
दीप प्रज्जवलन	
स्वागत भाषण	श्री प्रेम नारायण सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
सम्बोधन	श्री जितेंद्र सिंह, युवक कार्यकर्म और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा राज्य मंत्री युवाओं संबंधी प्रतिवेदन जारी किया गया
सम्बोधन	श्री वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
धन्यवाद प्रस्ताव	श्री राजीव गुप्ता सचिव, युवक कार्य विभाग, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
11.00-11.30 बजे	अंतराल
11.30-13.00 बजे	युवा प्रवासी भारतीय दिवस का पूर्व सत्र - प्रवासी युवाओं की आकाक्षाएं
अध्यक्ष	श्री मनीष तिवारी सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सम्बोधन	डॉ. रेणू खातौर चांसलर, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन सिस्टम एंड प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन
	डॉ. चारू वालीखन्ना, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग
	सुश्री कीर्ति वेदिका माताबादल नीदरलैंड
13.00-14.00 बजे	लंच
14.00-16.00 बजे	समवर्ती सत्र-1 एक ही विरासत होना: भावनात्मक जुडॉ.व
संचालन	डॉ विद्या येरावाडेकर, प्रधान निदेशक, सिमबायोसिस
सम्बोधन	सुश्री पल्लवी अय्यर , इंडोनेशिया पत्रकार, द हिन्दू
	सुश्री मेघना घई पुरी, अध्यक्ष,विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल
	श्री सुभाष राज़दान, अध्यक्ष, गांधी प्रतिष्ठान यूएसए

	श्री जगविंदर सिंह विर्क, अध्यक्ष, जीओआईपीआईओ आस्ट्रैलिया बिज़नेस कांउसिल
14.00-16.00 बजे	समवर्ती सत्र - 2 युवा एचीवर्स
संचालन	श्री नवीन जिदंल, संसद सदस्य
सम्बोधन	श्री के.सी. वेणूगोपाल, नागर विमानन राज्य मंत्री
	सुश्री सुप्रिया सूले, सांसद
	श्री पी. राजीव, सांसद
	डॉ. ममता सिंघवी, प्रबंध निदेशक अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ऑरिजन
	डॉ. रूबी ढल्ला, कनाडॉ.ई राजनेता
16.00-16.30 बजे	ब्रेक(अंतराल)
16.30-18.00 बजे	समापन सत्र
अध्यक्ष	श्री सचिन पायलट, कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सम्बोधन	श्री कंवलजीत सिंह बक्शी, संसद सदस्य, नेशनल पार्टी, न्यूजीलैंड
	श्री अशोक तंवर, सांसद
19.00-20.00 बजे	सांस्कृतिक कार्यक्रम

कार्यक्रम - दूसरा दिन

9.30 बजे से	उदघाटन सत्र
9.30 बजे	दीप प्रज्जवलन
9.32 बजे	पुरस्कार विजेताओं का परिचय, फोटोग्राफी
9.42 बजे	स्वागत भाषण श्री वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
9.50 बजे	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण श्री डॉ.टुक सेरी जी पालनीवेल प्राकृतिक संसाधन और पर्यायवरण मंत्री एवं अध्यक्ष, मलेशियन इंडियन कांग्रेस
10.00 बजे	प्रधानमंत्री द्वारा भाषण पुस्तक विमोचन (इंक्रेडिबल ऑपर्चुनिटीज बैक होम)
10.02 बजे	डॉ. मनमोहन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उदघाटन भाषण
10.15 बजे	धन्यवाद प्रस्ताव श्री प्रेम नारायण सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
10.15-10.45 बजे	ब्रेक(अंतराल)
10.45-13.00 बजे	पूर्ण सत्र-1 भारत का विकास और वृद्धि कार्यक्रम
	श्री सैम पित्रोदा, जन सूचना, नवाचार और अवसंरचना सलाहकार
सम्बोधन	श्री कमलनाथ शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्री आनन्द शर्मा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सिद्धार्थ बिरला अध्यक्ष, फिक्की
लंच	लंच
अध्यक्ष	पूर्ण सत्र - 2 भारत की साफ्ट पावर
सम्बोधन	श्री सलमान खुर्शीद, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी एवं विधि और न्याय मंत्री डॉ. के चिंरजीवी, अभिनेता, प्रोड्यूसर और राजनेता लार्ड कर्ण बिल्लमोरिज सीबीईडीएल
16.00-16.30 बजे	पीबीडी ओरेशन-'रिफ्लेकशन ऑन द डॉ.यसपोरा एक्सपिरियन्स
पीबीडी ओरेशन	श्री उज्ज्ल दोसांझ, पीसी,क्यूसी पूर्व सदस्य कनाडॉ.ई हाउस ऑफ कॉमस
16.30-17.00 बजे	ब्रेक(अंतराल)
19.00-20.30 बजे	सांस्कृतिक कार्यक्रम

कार्यक्रम - तीसरा दिन

09.30-11.30 बजे	
संचालन	डॉ. मोंटेक सिंह आहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग
सम्बोधन	श्री ओमान चांडी मुख्यमंत्री, केरल श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, मुख्यमंत्री, हरीयाणा श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, गुजरात डॉ. मुकुल संगमा, मुख्यमंत्री, मेघालय
11.30-12.00 बजे	ब्रेक(अंतराल)
12.00-13.30 बजे	अलग समानान्तर राज्य सत्र • बिहार • केरल • पंजाब • राजस्थान
13.30-14-30 बजे	लंच
14.30-16.00 बजे	समवर्ती सत्र 1- नवाचार और प्रौद्योगिकी
संचालन	डॉ. ए. दीदार सिंह, महासचिव, फिक्की
सम्बोधन	श्री सुब्रमणियम रमादोराई, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) श्री प्रसाद यरलागड्डा, क्वीन्सलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ब्रिसबेन आस्ट्रेलिया श्री बिरेंद्र (राज)दत्त पीएच.डी. अध्यक्ष एवं सीईओ, एपीआईसी कॉरपोरेशन एडं फोटोनिक कार्पोरेशन
14.30-16.00 बजे	समवर्ती सत्र - 2 भारत में स्वास्थ्य देख-रेख अवसर
संचालन	सुश्री संगीता रेड्डी, कार्यकारी निदेशक, अपोलो अस्पताल
मुख्य अभिभाषण	सुश्री संतोष चौधरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री
सम्बोधन	डॉ. जयेश बी शाह, एमडी एवं अध्यक्ष, एएपीआई, यूएसए डॉ. अशोक सेठ, अध्यक्ष फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट डॉ. नंदिनी टंडन, उपाध्यक्ष एवं बोर्ड सदस्य, ईएल केमिनो अस्पताला, सिलिकॉन वेली श्री ई.एम. नजीब, काय्रकारी निदेशक, केरल चिकित्सा विज्ञान संस्थान
14.30-16.00 बजे	समवर्ती सत्र - 3 प्रवासी संगठनों की बैठक
संचालन	श्री टी.पी. श्रीनिवासन, आईएफएस (सेवानिवृत)पूर्व राजदूत
सम्बोधन	डॉ.टो मेरी उत्तमा एस.सेमी वेल्लू , भारत और दक्षिण

	एशिया में अवसंरचना हेतु विशेष राजदूत, प्रधानमंत्री विभाग, मलेशिया सरकार श्री महयेंद्र उद्याना, अध्यक्ष अप्रवासी घाट न्यास निधि मॉरीशस श्री अशूक रामाशरण, अध्यक्ष, जीओपीआईओ, यू.एस लार्ड दिलजीत सिंह राणा, सदस्य, हाउस ऑफ लार्डस, यूके श्री नवल बजाज, अध्यक्ष, इंडो-चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एडवोकेट वाई.ए. रहीम, अध्यक्ष, भारतीय संघ शारजंहा श्री के. कुमार, संयोजक, भारतीय समुदाय कल्याण समिति,(आईसीडबल्यूसी), दुबई, यूएई
14.30-16.00 बजे	समवर्ती सत्र - 4 भारत को मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बनाया जाना
संचालन	श्री विक्रम चंद्रा, निदेशक एवं सीईओ, एनडीटीवी
मुख्य अभिभाषण	डॉ. कमल हसन, फिल्म निर्माता, प्रोडयूसर, अभिनेता
सम्बोधन	श्री रमेश सिप्पी, फिल्म प्रोडयूसर एवं निदेशक सुश्री अनुराधा प्रसाद, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बी.ए.जी. फिल्मस एडं मीडिया लिमिटेड श्री मुनीष गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध संपादक, पीआईओटीवी प्राइवेट लिमिटेड
14.30-16.00 बजे	समवर्ती सत्र - 5 खाडी देशों में आप्रवासी भारतीयों के मुद्दें
अध्यक्ष	श्री ई. अहमद, विदेश राज्यमंत्री
मुख्य अभिभाषण	श्री ओमान चांडी मुख्यमंत्री, केरल
विशेष सम्बोधन	श्री के.सी. जोसफ, ग्रामीण विकास, योजना, संस्कृति और नोरका रूटस मंत्री
सम्बोधन	श्री एम.ए. युसूफ अली, प्रबंध निदेशक, ईएमई के ग्रुप एवं उपाध्यक्ष, नोरका रूटस डॉ. बी. रवि पिल्लई, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आरपी ग्रुप ऑफ कंपनिज डॉ. बी. रवि पिल्लई, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आरपी ग्रुप ऑफ कंपनी श्री जे आर गंगारमाणी, अध्यक्ष और कार्यकारी चेयरमैन अलफ्रा ग्रुप
विशेष अतिथि	सभी जीसीसी देशों मै भारतीय राजदूत
16.00-16.30 बजे	ब्रेक(अंतराल)
17.00-18.00 बजे	विदाई सत्र और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाना (मंच पर- भारत के राष्ट्रपति, माननीय प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री, सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
	राष्ट्रीय गान
स्वागत भाषण	श्री प्रेम नारायण

	सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
सम्बोधन	श्री वायलार रवि, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
	प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाना
एक्सेपटेंस स्पीच	सुश्री ईला गांधी
विदाई सम्बोधन	श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के राष्ट्रपति
धन्यवाद प्रस्ताव	श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
	राष्ट्रीय गान
	सामूहिक फोटोग्राफ
19.00-20.30 बजे	सांस्कृतिक कार्यक्रम

बारहवां

प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी संबद्धता : पीढियों का जुडना

7-9 जनवरी, 2014, नई दिल्ली

प्रायोजकों का धन्यवाद

भारतीय स्टेट बैंक

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

एयर इंडिया
जीन्युज
टाइम्स नाऊ
शेरटान नई दिल्ली
मारुति सुज़ुकी